सिविल सर्विसेस मासिक

— मार्च 2020 —

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के सभी समाधान एक स्थान पर

- जम्मू एवं कश्मीर के लिए नए अधिवास नियम
- खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020
- भारिबैं द्वारा कोविड–19 से निपटने के लिए किए गए उपाय
- अंतर्राष्टोय महिला दिवस
- कोलकाता में आइकॉनसेट 2020
- 83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान
- ग्रीन कंपनी (ग्रीनको) रेटिंग सिस्टम
- जी20 वर्चुअल समिट
- पोक्सो के नए नियम अधिसूचित
- SIRT1 की भूमिका
- इंडिया पर्सपेक्टिव
- मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्युट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड ऐनलिसीस

विषय–सूची

प्रारंभिक परीक्षा

नीति एवं शासन

जम्मू एवं कश्मीर के लिए नए अधिवास नियम 1
विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 2
विडयो ऐप 4
एकम उत्सव 6
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम विरोधी प्रदर्शन 7
नवनियूक्त सीआईसी 8
खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 8

अर्थव्यवस्था

भारिबैं द्वारा कोविड–19 से निपटने के लिए किए गए उपाय 8
इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफार्म 9
एपीईडीए के एसएफएसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 11
रोपाक्ष सेवा 14
2020 के अंत तक भारत की साझा अर्थव्यवस्था 2 बिलीयन डॉलर होगी 14
स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए उत्पादों का ई–विपणन 16
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट 16

समाज एवं स्वास्थ्य

सामाजिक लिंग मानदंड सूचकांक (जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स) 16
ऑपरेशन नमस्ते 17
एनएएम के तहत आयुष वेलनेस सेंटर 18
दिव्य कला शक्ति – विकलांगों में साक्षीभाव 19
कार्यस्थल सुरक्षा 20
पीएचडी में अजा, अजजा छात्रों का नामांकन कार्यक्रम 21
शून्य भेदभाव दिवस 21

विज्ञान एवं तकनीक

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन संयोजन की अनुमति दी 22
कोविड–19 के लिए टेस्ट किट 23
वास्प–76बी पर लोहे की बारिश 23
पाई दिवस 25
सूक्ष्मजीवों से जैव ईंधन 26
कोलकाता में आईकनसेट 2020 26
2020 सीडी 3 28

आंतरिक सुरक्षा

लाइट मशीन गन्स (एलएमजी) 29
83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान 30
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 30
विस्फोटक पता लगाने का नया यंत्र 30

भूगोल एवं पर्यावरण

दिल्ली में कुड़ा फैंकने के स्थान का प्रभाव 30
विश्व गौरैया दिवस 31
ग्रीन कंपनी (ग्रीनको) रेटिंग सिस्टम 32
रेड पांडा का अवैध व्यापार 32
मछली पकड़ने वाली बिल्ली तथा ऊदबिलाव 34

अंर्तराष्ट्रीय संबंध

भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि 34
वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से जी 7 बैठक 35
अमेरिका में हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण सफल 35
जी20 वर्चुअल समिट 35

कला एवं संस्कृति

शेख मुजीर्बुरहमान 37
900 से अधिक यक्षगान लिपियों को डिजिटाइज किया गया 37
बीएचयू की टीम ने वाराणसी में 4,000 वर्ष पुराने शिल्प गांव का पता लगाया 38
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 39

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन I

मरक्कड़ फिल्म विवाद 39
समाज और स्वास्थ्य प्रणाली पर कोविड–19 का प्रभाव 41
पोक्सो के नए नियम अधिसूचित 44

सामान्य अध्ययन II

दलबदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता 45
पूर्व मुख्य न्यायाधीश की राज्य सभा में नियूक्ति 46
लोकपाल (शिकायत) नियम, 2020 48
भूमि अधिग्रहण 51
कोविड–19 एवं मल्टीलेटरिज़्म (बहुपक्षिता) 53
सार्क बैठक 55

सामान्य अध्ययन III

चावल के पौधों में मीथेन शमन के लिए सक्षम बैक्टीरिया 57
SIRT1 की भूमिका 58
गर्भनाल रक्त की बैंकिंग 59
विश्व अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का प्रभाव 60
केरल ने FRBM नियमों में छूट मांगी 63
यस बैंक संकट 65
गंगोत्री ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन का संकेंद्रण 67
भारत, फ्रांस द्वारा रीयूनियन द्वीप से संयुक्त गश्ती दल का संचालन 69
क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर और नेशनल साइबरक्राइम ट्रेनिंग सेंटर 72

इंडिया पर्सप्रेक्टिव

मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्युट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड ऐनलिसीस

प्रारंभिक परीक्षा

नीति एवं शासन

जम्मू एवं कश्मीर के लिए नए अधिवास नियम

समाचार –

- जम्मू–कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने तथा इसे 2 संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठित करने के बाद, केंद्र ने इसके मूलनिवास तथा भर्ती नियमों को फिर से परिभाषित किया है।
- इसके अंतर्गत स्तर 4 को छोड़कर अन्य किसी भी स्तर की सरकारी नौकरियों को देश के बाकी हिस्सों के लिए प्रभावी ढंग से खोल दिया गया है।
- जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश 2020, 31 मार्च 2020 को जारी किया गया जिसमें 29 कानूनों को निरस्त तथा 109 अन्य में संशोधन किया गया।
- जम्मू–कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम के तहत धारा 3 ए, जो अधिसूचना का हिस्सा था, मूलनिवासी को निम्न रूप से परिभाषित करता है – 'जो जम्मू–कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में 15 वर्ष की अवधि से रहता आया है या की उसने राज्य में 7 वर्ष की अवधि तक अध्ययन किया हो एवं राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10 वीं/12 वीं की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो।
- इससे पहले, जम्मू और कश्मीर के एक स्थायी निवासी होने के लिए वहाँ जन्म लेना आवश्यक होता था तथा इन मूलनिवासीयों को राज्य में निवास, रोजगार, शिक्षा, चुनाव लड़ने और संपत्ति रखने के विशेषाधिकार प्राप्त थे।
- अब, इस परिभाषा में विस्तार किया गया है तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारीयों, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वैधानिक निकायों के अधिकारीयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकारीयों और मान्यता प्राप्त बच्चे तथा केंद्र सरकार के अनुसंधान संस्थान जो 10 वर्षों से जम्मू–कश्मीर में सेवा दे रहे हैं, को शामिल किया गया हैं।
- इसके अतिरिक्त अब, जम्मू–कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासियों) द्वारा एक प्रवासी के रूप में पंजीकृत किसी भी व्यक्ति तथा जम्मू–कश्मीर निवासियों के बच्चे जो बाहर रहते हैं लेकिन जिनके माता–पिता ऊपर की किसी भी शर्त को पूरा करते हैं, को मूलनिवासी माना जाएगा।
- एक तहसीलदार को एक मूलनिवासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है, जैसा कि पहले इसके लिए अधिसूचित उपायुक्तों या अधिकारियों को नियूक्त किया गया था।
- जम्मू–कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम की धारा 5–ए में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति स्तर–4 (25500) से अधिक के वेतनमान वाले पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का मूलनिवासी ना हो।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

- यह भारत की संसद का एक अधिनियम है।
- इसमें जम्मू और कश्मीर के भारतीय प्रशासित राज्य के दो प्रशासित संघ शासित प्रदेशों में पुनर्गठन के प्रावधान हैं, एक को जम्मू–कश्मीर और दूसरा लद्दाख कहा जाता है।
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल और लेह जिले शामिल हैं तथा जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर राज्य के शेष क्षेत्र शामिल होंगे।

उच्चतम न्यायालय ने कोविड.19 पर चर्चा करने क अधिकार को सही ठहराया

समाचार –

- 31 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कोविड–19 के बारे में स्वतंत्र चर्चा के अधिकार को सही ठहराया, यहां तक कि इसने मीडिया को निर्देश दिया कि वह गलत घटनाओं तथा बड़े पैमाने पर घबराहट से बचने के लिए घटनाक्रम के आधिकारिक संस्करण को प्रकाशित करें।
- इसने सरकार को कोविड–19 के घटनाक्रम पर अगले 24 घंटों में सभी मीडिया के माध्यम से एक दैनिक बुलेटिन शुरू करने का आदेश दिया।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक बेंच, केंद्र सरकार के एक अनुरोध का जवाब दे रही थी कि मीडिया आउटलेट्स को 'न्याय के बड़े हित' में, केवल तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के बाद कोविड–19 पर कुछ भी प्रकाशित या प्रसारित करना चाहिए।
- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि कोविड–19 कल अभूतपूर्व घटना के बीच इस तरह की रिपोर्टिंग पर आधारित कोई भी घबराहट भरी प्रतिक्रिया पूरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आतंक पैदा करना भी एक अपराध है।
- अदालत ने स्वतंत्र प्रेस को संतुलित करते हुए एक दृष्टिकोण लिया और मीडिया (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल) को जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना बनाए रखे और यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी कि आतंक पैदा करने में सक्षम असत्यापित समाचार का प्रसार नहीं किया जाए।

कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट) अध्यादेश, 2020

समाचार –

- सरकार ने कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट) अध्यादेश, 2020 को प्रख्यापित कर दिया है, जो कोविड–19 महामारी के मद्देनजर घोषित 'कर अनुपालन' से जुड़े विभिन्न उपायों को प्रभावी बनाता है।
- सरकार ने आयकर लाभ का दावा करने के लिए आय कर दाखिल करने की अंतिम तिथि, राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि जैसे उपकरणों में निवेश करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
- पैन (परमानेंट अकाऊँट नंबर) को बायोमेट्रिक आईडी आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
- अध्यादेश ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएम–केयर कोष) के रूप में उपलब्ध प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (राहत–बचाव कोष) में समान कर प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों में भी संशोधन किया है। पीएम केयर कोष को किया गया दान आईटी अधिनियम की धारा 80 जी के तहत 100 प्रतिशत छूट के लिए पात्र होगा। 10 प्रतिशत सकल आय में कटौती की सीमा भी पीएम–केयर कोष को किए गए दान के लिए लागू नहीं होगी।

विमान (संशोधन) विधेयक, 2020

समाचार –

- लोकसभा ने विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया है, जिसमें विमान अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया है।
- अधिनियम नागरिक हवाई जहाजों के निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात एवं निर्यात को नियंत्रित करता है तथा हवाईअड्डों को लाइसेंस देता है।
- विधेयक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) जैसे नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करेगा। इनमें से प्रत्येक निकाय का नेतृत्व एक महानिदेशक करेगा जो केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- डीजीसीए विधेयक के तहत मामलों के संबंध में सुरक्षा निरीक्षण और विनियामक कार्यों को अंजाम देगा तथा बीसीएएस नागरिक उड्डयन सुरक्षा से संबंधित विनियामक निरीक्षण कार्य करेगा। इसके अलावा, एएआईबी विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं से संबंधित जांच करेगा।
- विधेयक में विमानन उद्योग के व्यवसायीओं के लिए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव है।
- अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार कई मामलों पर नियम बना सकती है जैसे विमान का पंजीकरण, वायु परिवहन सेवाओं को विनियमित करना और किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में उड़ान को रोकना।
- विधेयक के तहत, यदि व्यक्ति अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो केंद्र सरकार अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को दिए गए लाइसेंस, प्रमाण पत्र या अनुमोदन को रद्द कर सकती है।
- अधिनियम में संघ के नौसैनिक, सैन्य, या वायु सेना से संबंधित विमानों को छूट दी गई है।
- विधेयक इन तीनों के अलावा किसी अन्य सशस्त्र बलों से संबंधित विमानों को शामिल करने के लिए इस छूट का विस्तार भी करता है।

भारतीय नौसेना में स्थायी महिला आयोग

समाचार –

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना के महिला लघु सेवा आयोग (एसएससी) अधिकारियों को अपने पुरुष समकक्ष साथियों के बराबर स्थायी आयोग (पीसी) की सेवा देने के अधिकार को बरकरार रखा।
- यह निर्णय सेवानिवृत्त महिला अधिकारियों, जिन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया गया था, को पेंशन लाभ भी देता है।
- निर्णय 17 महिला एसएससी अधिकारियों द्वारा दायर किए गए एक मामले पर आधारित था, जिन्हें 14 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद स्थायी आयोग अधिकारी के रूप में दर्जा देने से वंचित कर दिया गया था।
- यह निर्णय, शीर्ष अदालत द्वारा सेना में समान रूप से पदस्थापित महिला अधिकारियों के निर्णय के पश्चात् आया है।

निर्णय –

- शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिलाओं के स्थायी कमीशन पर वैधानिक रोक हटा दी और कहा कि सरकार महिलाओं से भेदभाव नहीं कर सकती।

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बिल 2020

समाचार –

- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बिल 2020 को जहाजरानी राज्य मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दी गई ।
- यह विधेयक मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स अधिनियम, 1963 का स्थान लेगा और मेजर पोर्ट्स को निर्णय लेने में पूर्ण स्वायत्तता के आधार पर तथा मेजर पोर्ट्स के संस्थागत ढांचे का आधुनिकीकरण करके अधिक दक्षता के साथ प्रदर्शन करने में सशक्त करेगा।
- यह विधेयक, सभी हितधारकों और मंत्रालयों/विभागों के साथ व्यापक परामर्श और पीएससी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
- यह विधेयक चेन्नई, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मंगलौर, मोर्मुगाओ, पारादीप, वी ओ चिदंबरनार, और विशाखापत्तनम के प्रमुख बंदरगाहों पर लागू होगा।

पृष्ठभूमि –

- इससे पहले, विधेयक 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था और उसके बाद संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) के लिए भेजा गया था। पीएससी ने साक्ष्य और व्यापक प्रसार परामर्श के बाद, जुलाई 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर, शिपिंग मंत्रालय ने लोकसभा में 2018 में विधेयक में आधिकारिक संशोधन पेश किया। हालांकि, 17 वीं लोकसभा के विघटन के कारण बिल समाप्त हो गया।

विधेयक का उद्देश्य –

- निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना और प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना।
- हितधारकों और बेहतर परियोजना निष्पादन क्षमता को लाभान्वित करते हुए तेज और पारदर्शी निर्णय प्रदान करना।
- सफल वैश्विक अभ्यास के अनुरूप केंद्रीय बंदरगाहों में शासन मॉडल को लैंडलॉर्ड बंदरगाह मॉडल के के रूप में पुनर्जीवित करना। इससे मेजर पोर्ट के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। (लैंडलॉर्ड बंदरगाह मॉडल में, सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय के रूप में और मालिक के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह संचालन–मुख्य रूप से कार्गो–हैंडलिंग गतिविधियों को अंजाम देती हैं।)

बिल 2020 की मुख्य विशेषताएं –

- मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की तुलना में बिल अधिक कॉम्पैक्ट है क्योंकि ओवरलैपिंग और अप्रचलित अनुभागों को समाप्त करके वर्गों की संख्या को 134 से घटाकर 76 कर दिया गया है।
- नए विधेयक में पोर्ट अथॉरिटी के बोर्ड की एक सरलीकृत रचना प्रस्तावित की गई है जिसमें विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान 17 से 19 सदस्यों में 11 से 13 सदस्य शामिल होंगे। पेशेवर स्वतंत्र सदस्यों के साथ एक छोटाबोर्ड निर्णय लेने और रणनीतिक योजना को मजबूत करेगा।
- प्रमुख बंदरगाह जिस राज्य में स्थित है उस सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, रेल मंत्रालय, रक्षा और सीमा शुल्क मंत्रालय, राजस्व विभाग में बोर्ड में सदस्य के अलावा एक सरकारी सदस्य और एक सदस्य मेजर पोर्ट प्राधिकरण के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स (टीएएमपी) को अब टैरिफ तय करने की शक्तियां दी गई हैं जो पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के उद्देश्यों के लिए एक संदर्भ टैरिफ के रूप में कार्य करेगा। पीपीपी ऑपरेटर बाजार की स्थितियों के आधार पर टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- पोर्ट अथॉरिटी के बोर्ड को भूमि सहित अन्य पोर्ट सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिए दरों का पैमाना तय करने की शक्ति सौंपी गई है।
- तनावग्रस्त पीपीपी परियोजनाओं की समीक्षा करने, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए उपाय सुझाने, बंदरगाहों तथा पीपीपी रियायतदारों के बीच विवादों पर गौर करने, प्रमुख बंदरगाहों के लिए पूर्ववर्ती टीएएमपी के अवशिष्ट कार्य को पूरा करने तथा बंदरगाहों में कार्य कर रहे नीजि/पोर्ट ऑपरेटरों की शिकायतों को देखने के लिए एक सहायक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- 1963 अधिनियम के तहत, सभी प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के संबंधित पोर्ट ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण का बोर्ड बनाने का प्रावधान है। ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट की जगह लेंगे।
- पोर्ट अथॉरिटी के बोर्डों को अनुबंधों, योजना और विकास में प्रवेश करने, राष्ट्रीय हित, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टैरिफ तय करने और निष्क्रियता और डिफॉल्ट रूप से उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान एमपीटी अधिनियम, 1963 में ऐसे 22 प्रकरणों में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी।
- प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह का बोर्ड बंदरगाह की सीमा और भूमि के भीतर स्थापित होने वाले किसी भी विकास या अवसंरचना के संबंध में विशिष्ट मास्टर प्लान बनाने का हकदार होगा और इस तरह का मास्टर प्लान किसी भी स्थानीय या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकरण नियम से स्वतंत्र होगा।
- पोर्ट प्राधिकरण द्वारा सीएसआर और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रावधान पेश किए गए हैं।
- प्रमुख बंदरगाहों के कर्मचारियों के पेंशन लाभ, मेजर पोर्ट्स के टैरिफ सहित वेतन और भत्तों और सेवा शर्तों की सुरक्षा के प्रावधान किये गए है।

विडयो ऐप

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने कोविड–19 महामारी के कारण अपने कामकाज को और अधिक प्रतिबंधित करने और सामाजिक विचलन को बनाए रखने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए डिजिटल मोड का सहारा लेने का फैसला लिया। कोर्ट परिसर पूरी तरह से बंद रहेगा।
- यह निर्णय लिया गया था कि केवल अत्यंत आवश्यक मामलों को एक बेंच (या बेंचों) द्वारा विडयो ऐप के माध्यम से सुना जाएगा।
- उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल देश में ट्रिब्यूनलों और अदालतों में सभी मामलों में सीमा अवधि बढ़ाने के लिए किया।
- मामलों की सुनवाई विडयो नामक ऐप के माध्यम से की जाएगी।
- विडयो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लिकेशन है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा जाँचा गया है। अमेरिका–आधारित फर्म द्वारा विकसित ऐप का उपयोग पहली बार 1995 में स्टूडियो–आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मेजबानी करने के लिए एनआईसी द्वारा किया गया था। 2009 में, एप्लिकेशन का उपयोग डेस्कटॉप–आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया गया था।

गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी

समाचार –

- उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नामित किया, जिसका उपयोग विशेष रूप से गर्म मौसम की विस्तारित अवधि के दौरान प्रशासनिक राजधानी के रूप में किया जाता है।
- ताजा घोषणा के साथ, यह स्पष्ट नही है कि क्या देहरादून की वर्तमान स्थिति समान रहेगी या इसे नई शीतकालीन राजधानी माना जाएगा।

पृष्ठभूमि –

- उत्तराखंड को 1998 में उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में तराशा गया था। जिन लोगों ने उत्तराखंड को राज्य का दर्जा देने के लिए आंदोलन किया था, वे चाहते थे कि गैरसैंण को इसकी स्थायी राजधानी बनाया जाए।
- हालांकि, देहरादून को राज्य की अस्थायी राजधानी बनाया गया था, जिसमें अभी भी मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और विधायक निवास हैं।
- राज्य विधानसभा देहरादून में स्थित है, लेकिन सत्र गैरसैंण में भी आयोजित किए जाते हैं।

गैरसैंण क्यों?

- राज्य के कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से कहा है कि चमोली जिले की एक तहसील गैरसैंण, पहाड़ी राज्य की राजधानी होने के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों की सीमा पर पड़ने वाला एक पहाड़ी क्षेत्र था।
- यह राजधानी के निर्माण और लोगों को समायोजित करने के लिए उपयुक्त एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है।
- यह एक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है और यह गढ़वाल को कुमाऊँ क्षेत्र से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग का एक हिस्सा भी है।
- यह रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है जो दूधातोली पर्वत के पास से निकलती है।
- प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (यूनेस्को विश्व विरासत स्थल), बद्रीनाथ, वसुंधरा जलप्रपात आदि हैं।

तीसर पक्ष तक अदालत के दस्तावेजों की पहुँच

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अदालत के दस्तावेज जैसे निर्णय और वाद की प्रतियां अब तीसरे पक्ष या उन लोगों को प्राप्त हो सकती हैं जो मामले में वादी नहीं थे।
- यह जानकारी केवल अदालत के नियमों की अनुमति के बाद ही उपलब्ध होगी और सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत नहीं।
- यह फैसला उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को आरटीआई अधिनियम के तहत जांच करने के लिए खोलने के कुछ महीनों बाद आया है।

विवरण –

- गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 151 को बरकरार रखा गया है जिसमें न्यायालय के किसी अधिकारी के आदेश के तहत किसी तीसरे पक्ष को निर्णयों, आदेशों और वादों की प्रमाणित प्रतियों तक पहुँच प्रदान की जा सकती है।
- बॉम्बे, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मद्रास आदि उच्च न्यायालयों में समान प्रावधान हैं।
- पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय मुकदमों को स्थगित करने और न्याय का प्रशासन करने के लिए सूचना को मुकदमों के ट्रस्टी के रूप में रखता है।
- तीसरे पक्ष को मुकदमों की ऐसी व्यक्तिगत जानकारी या कार्यवाही में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के लिए खुली और आसान पहुंच की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे अदालत की प्रक्रिया और एक असहनीय स्तर तक जानकारी का दुरुपयोग होगा।
- नियमों के अनुसार, मुकदमेबाजों को निर्धारित कोर्ट फीस स्टैम्प के साथ आवेदन दाखिल करने पर दस्तावेजों/निर्णयों आदि की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है।
- तीसरे पक्ष को सहायक रजिस्ट्रार के आदेश के बिना निर्णय और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां नहीं दी जाती हैं।
- दस्तावेजों की जानकारी/प्रमाणित प्रतियों की मांग के लिए उचित कारण के बारे में संतुष्ट होने पर रजिस्ट्रार, दस्तावेजों तक पहुंच की अनुमति देता है।

यदि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के नियमों के बजाय, कानून के तहत जानकारी चाहता है तो सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम इस तरह की जानकारी मांगने पर रोक नहीं लगाता है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम और अन्य कानून के प्रावधानों के बीच अंतर्निहित असंगतता के अभाव में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम लागू नहीं होगा।'

द्वार प्रदाय योजना

समाचार –

- द्वार प्रदाय योजना एक पायलट परियोजना है जिसे इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
- इस योजना के अंर्तगत, इंदौर नगर निगम (आईएमसी) की सीमाओं के भीतर रहने वाले आवेदकों को पांच प्रकार के दस्तावेज – अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और खसरा–खतौनी (एक भूमि स्वामित्व दस्तावेज) की प्रति – ऑनलाइन आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर अपने घर पर प्राप्त होते हैं।
- प्रशासन ने एक स्थानीय कूरियर एजेंसी लगाई है, जो दस्तावेजों को सार्वजनिक सेवा केंद्रों से एकत्र करने के बाद वितरित करती है।
- केंद्रीय विचार सरकार के सेवा वितरण तंत्र में सुधार करना है।

एकम उत्सव

समाचार –

- 2 मार्च 2020 से नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) द्वारा एक सप्ताह की प्रदर्शनी–सह–मेला "एकम उत्सव" आयोजित किया गया।
- एकम उत्सव दिव्यांगजनों के बीच उद्यमशीलता और ज्ञान को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।
- एकम (ईकेएएम) का अर्थ है उद्यमिता (एंत्रयोप्रेनरशीप), ज्ञान (नॉलेज), जागरूकता (अवेयरनेस) और विपणन (मार्केटिंग)।
- यह विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) उद्यमियों की क्षमता के बारे में समाज के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा।
- यह विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) उद्यमियों की क्षमता के बारे में समाज के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) –

- एनएचएफडीसी की स्थापना जनवरी 1997 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर–लाभकारी कंपनी के रूप में की गई थी।
- यह विकलांग व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

5 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) की स्थिति दी गई

समाचार –

- लोकसभा ने 5 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया।
- आईआईआईटी कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक–निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 के तहत सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में स्थित 5 संस्थानों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से इस योजना के तहत स्थापित 15 आईआईटी के समान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया।
- यह स्थिति सूचना प्रौद्योगिकी में एक मजबूत अनुसंधान आधार विकसित करने के लिए आवश्यक छात्रों को आकर्षित करने में संस्थान की मदद करेगी।

अवमानना मामलों में पासपोर्ट आत्मसमर्पण – उच्चतम न्यायालय

समाचार –

- उच्चतम न्यायालय ने माना कि अदालतों को कार्यवाहीयों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अवमानना मामले में पार्टियों को अपने पासपोर्ट का आत्मसमर्पण करने का आदेश देने का अधिकार है।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि विचारक केवल अदालत के पास अपना पासपोर्ट जमा करेंगे।
- अदालत ने डेविड जूड बनाम हाना ग्रेस जूड में 2003 के एक फैसले का उल्लेख किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की तारीख पर अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अवमानना करने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द करे।

CHAHAL ACADEMY

न्यायालयों की अवमानना –

- ऐसा कुछ भी जो न्यायिक कार्यवाही की सीमा की स्वतंत्रता को कम करता है तथा जिसके परिणामस्वरूप कानून के प्रशासन में बाधा डालने और न्याय के नियत समय में हस्तक्षेप होता है।
- भारत, 1971 की अवमानना अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत अदालत की अवमानना को नागरिक अवमानना या आपराधिक अवमानना के रूप में परिभाषित करता है, आमतौर पर यह महसूस किया जाता है कि अदालतों की अवमानना से संबंधित मौजूदा कानून कुछ अनिश्चित, अपरिभाषित और असंतोषजनक है।
- अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार क्षेत्र नागरिकों के दो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों, अर्थात् व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर छूता है। इसलिए, एक विशेष समिति द्वारा इस विषय पर पूरे कानून की जांच करने की सलाह दी जाती है।

जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग

समाचार –

- कानून मंत्रालय ने एक परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगे, जो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के 4 उत्तर–पूर्वी राज्यों को फिर से संगठित करने के का कार्य करेगा।
- चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू–कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त और चार उत्तर–पूर्वी राज्यों में पदेन सदस्य होंगे।
- आयोग जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के प्रावधानों के अनुसार परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा।
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 60 के अनुसार, इस केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा में सीटों की संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 किया जाएगा।
- इनमें से 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं। प्रभावी रूप से, सीटें 83 से 90 तक जाएंगी।

परिसीमन –

- 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के उद्देश्य से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के विभाजन को फिर से लागू करने के लिए परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम विरोधो प्रदर्शन

समाचार –

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ प्रशासन को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपीयों के फोटो और व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित करने वाले सभी होर्डिंग्स को हटाने का निर्देश दिया।
- न्यायालय कहा कि पोस्टर लगाने का राज्य सरकार का कदम एक अनुचित हस्तक्षेप था लोगों की निजता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
- पुलिस ने पिछले दिसंबर में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों की पहचान करने वाले लखनऊ के कई होर्डिंग्स लगाए, जिससे उन व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा हो गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया।
- चयनित व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की नियुक्ति सरकार की 'शक्तियों के दुरूपयोग' को दर्शाती है।

निजी संपत्ति

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से हटाया जाना मानवीय अधिकार का उल्लंघन है।
- न्यायमूर्ति एस. के. कौल, के नेतृत्व वाली एक बेंच द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले में अदालत ने अपने निर्णयों से उद्धृत करते हुए जोर दिया कि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत, संवैधानिक अधिकार है।
- वर्तमान निर्णय 1980 में सिक्किम राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रॉजेक्ट ऑर्चर्ड रीजनल सेंटर के निर्माण के लिए कुछ एकड़ जमीन के अधिग्रहण से संबंधित है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2020

समाचार –

- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल 2020 संसद द्वारा पारित किया गया है।
- बिल में अड़चनों को दूर करने और कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया को कारगर बनाने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य पिछले मालिकों के दुष्कर्मों के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ ऋण डिफाल्टर कंपनी के नए मालिकों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- आईबीसी के विभिन्न वर्गों के साथ–साथ एक नए अनुभाग की शुरुआत से संबंधित नवीनतम बदलाव।

नई सीआईसी

समाचार –

- सूचना आयुक्त बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय सूचना आयोग में सीआईसी के रूप में जुल्का को पद की शपथ दिलाई।
- 11 जनवरी 2020 को सुधीर भार्गव के सेवानिवृत्त होने तथा स्वीकृत 11 इंफोर्मेशन कमिश्नरों की तुलना में छः इंफोर्मेशन कमिश्नरों (सीआईसी सहित) के कारण कम बल होने के बाद, विभाग प्रमुख के बिना काम कर रहा था।
- जुल्का की सीआईसी के रूप में नियुक्ति के बाद आयोग में पांच और सूचना आयुक्तों की रिक्ति है।

खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020

समाचार –

- संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 और कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 में संशोधन के लिए खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया।
- विधेयक एमएमडीआर अधिनियम 1957 और सीएमएसपी अधिनियम के संशोधन के लिए अध्यादेश की जगह लेता है जिसे जनवरी 2020 में प्रख्यापित किया गया था।
- एमएमडीआर अधिनियम भारत में समग्र खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है। सीएमएसपी अधिनियम उन खानों की नीलामी और आवंटन का प्रावधान करता है, जिनका आवंटन 2014 में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
- यह विधेयक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से भारतीय कोयला और खनन क्षेत्र में एक नये युग की शुरूआत करेगा।
- संशोधित प्रावधान स्पष्ट रूप से यह प्रस्तावित करते हैं कि जिन कंपनियों के पास भारत में कोयला खनन का कोई पूर्व अनुभव नहीं है और/या अन्य खनिजों में खनन का अनुभव है या अन्य देशों में कोयला/लिग्नाइट में खनन का अनुभव है, ब्लॉक की नीलामी में भाग ले सकते हैं। इससे न केवल कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामी में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि कोयला क्षेत्र में एफडीआई नीति के कार्यान्वयन में भी आसानी होगी।
- अंत उपयोग प्रतिबंध को हटाने से विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों जैसे कि स्वयं की खपत, बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोयला खानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी की अनुमति होगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- नए प्रावधान गैर–विशिष्ट रीकॉन्डेंस परमिट (एनईआरपी) धारकों को समग्र लाइसेंस या खनन पट्टे (पीएल–सह–एमएल) के लिए आवेदन करके जमीन में गहरे स्थित राष्ट्रीय हित के खनिजों और अन्वेषण को भी बढ़ाएंगे। एमएमडीआर अधिनियम और सीएमएसपी अधिनियम के कई व्यापक दोहरावों और निरर्थक प्रावधानो को आसानी से व्यापार करने के लिए हटा दिया गया है।

कंपनी अधिनियम

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिसमें विभिन्न अपराधों को कम करने के एक कदम के रूप में कंपनी अधिनियम के 72 संशोधनों को मंजूरी दी है। इससे वास्तविक वाणिज्यिक विफलताओं के मामले में कॉर्पोरेट्स की रक्षा होगी।
- विधेयक, चूक के ऐसे मामलों जिन्हें उद्देश्यपूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है या जिनमें अन्यथा, धोखाधड़ी के तत्व का अभाव है या बड़ा सार्वजनिक हित शामिल नहीं है, में आपराधिकता को हटाता है।
- इस विधेयक ने कानून का पालन करने वाले कॉरपोरेट्स को जीवन को आसान बनाने और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को दुरूस्त करने की दिशा में कार्य किया है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम (2013) में संशोधन करने के लिए कंपनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। संशोधनों के साथ, अधिनियम के तहत 66 कंपाउंडेबल अपराधों में से 23 अपराध फिर से वर्गीकृत किए जाएंगे।

- इसके साथ, सात कंपाउंडेबल अपराधों को भी अधिनियम से हटा दिया जाएगा।
- इससे पहले, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया।

अर्थव्यवस्था

8 कोर सेक्टर के उद्योगों में विकास

समाचार –

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कोर क्षेत्र के आठ उद्योगों ने फरवरी, 2020 में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 11 महीने में सबसे अधिक है।
- यह वृद्धि रिफाइनरी उत्पादों, बिजली, उर्वरक, सीमेंट और कोयला उत्पादन में वृद्धि के कारण है।
- हालांकि, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और इस्पात ने फरवरी में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की।
- यह लगातार चौथा महीना था जब आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई।
- मार्च 2020 के लिए संभावनाएँ बहुत उज्ज्वल नहीं है, क्योंकि कोविद–19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने देश और विश्व स्तर पर उत्पादन प्रक्रिया को बाधित किया है।

हस्तशिल्प की निर्यात संवर्धन परिषद ने आईएचजीएफ को निरस्त किया

- निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने भारत और विदेश में कोविड–19 की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला (आईएचजीएफ) – दिल्ली स्प्रिंग–20 का 49 वां संस्करण रद्द कर दिया है।
- भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला (आईएचजीएफ) एशिया का सबसे बड़ा उपहार और हस्तशिल्प व्यापार मेला है।
- आईएचजीएफ–दिल्ली मेला ऑटम–20 के अगले (50 वें) संस्करण का आयोजन 14 से 2020 अक्टूबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा।

भारिबैं द्वारा कोविड–19 से निपटने के लिए किए गए उपाय

समाचार –

- रेपो दर में 5.15 प्रतिशत से 4.40 प्रतिशत तक 75 आधार अंकों (इचे) की कटौती की गई है।
- दरों में कटौती, बैंकों को अधिक उधार देने और विकास को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई है।
- रिवर्स रेपो दर में 90 बीपीएस की कटौती करके 4 प्रतिशत कर दिया गया है।
- रिवर्स रेपो दर में अधिक कमी का उद्देश्य बैंकों को भारिबैं के साथ अपनी अतिरिक्त तरलता रखने के बजाय अधिक उधार देने के लिए प्रेरित करना था।
- भारिबैं ने बैंकों को 31 मई तक तीन महीने के लिए घर, कार, व्यक्तिगत ऋणों के साथ–साथ क्रेडिट कार्ड बकाये पर समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के भुगतान को स्थगित करने की अनुमति दी है।
- आरबीआई ने उधार देने वाले संस्थानों, बैंकों को कार्यशील पूंजी पुनर्भुगतान पर ब्याज को 3 महीने तक स्थगित करने की अनुमति दी है – जो कि उत्पादन की कमी के कारण संस्थानों में उत्पन्न संकट से निपटने की दिशा में एक कदम है।
- 1 ट्रिलियन तक के लक्षित दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन्स (टीएलटीआरओ) से संबंधित सुधार, कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) में 100–बीपीएस कटौती और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) खिड़की के तहत आसान उधार।

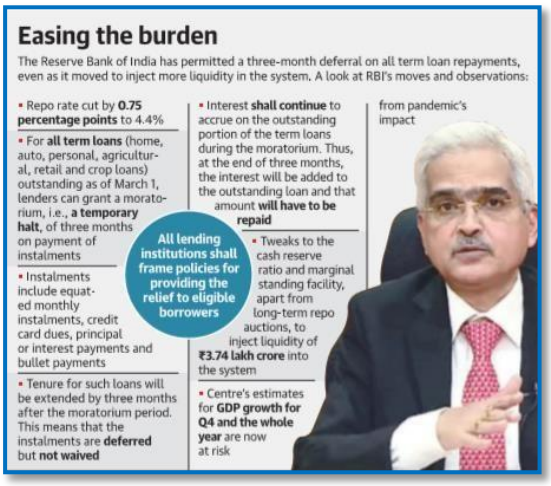

इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफार्म

समाचार –

- इन्वेस्ट इंडिया ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत इन्वेस्ट इंडिया बिज़नेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

बिजनस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म –

- बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म (बीआईपी) को व्यवसायों और निवेशकों को कोविड–19 (कोरोनावायरस) के लिए भारत की सक्रिय प्रतिक्रिया पर वास्तविक समय के अपडेट प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में डिजाइन किया गया है।
- एमएसएमई के प्रश्नों का जवाब देने और हल करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया ने सिडबी (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया) के साथ साझेदारी की भी घोषणा की है।
- बीआईपी व्यवसाय के मुद्दे के निवारण के लिए एक सक्रिय मंच है, जो समर्पित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक टीम के साथ और जल्द से जल्द प्रश्नों का जवाब देने के लिए 24/7 का संचालन करता है।

बीआईपी की विशेषताएं –

- कोरोनोवायरस के संबंध में विकास पर एक नियमित नजर रखता है।
- विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की पहल पर नवीनतम जानकारी प्रदान करता है, और ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप पर प्रश्नों का उत्तर देता है और हल करता है।
- कोविड–19 परीक्षण के स्थानों और अन्य स्थान–विशिष्ट जानकारी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल हैं।
- प्रमुख भारतीय कंपनियों द्वारा स्टाफ वाहनों की स्वच्छता, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अक्षम करने, वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग और टेली–कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग, ऑनलाइन समाधान और अन्य अनूठी पहलों को विकसित करके प्रतिक्रिया तंत्र को मैप और हाइलाइट किया जाता है।

कंपनियों का बोझ कम करने के प्रयास

समाचार –

- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कोविड–19 के प्रकोप के दौरान कंपनियों के बोझ को कम करने के लिए कई घोषणाएँ की हैं।
- कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी की दीक्षा के लिए सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया है।
- इससे छोटे व्यवसायों को दिवालियेपन में घसीटने से रोका जा सकता है (ऋण का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर)।
- इससे कोरोनोवायरस प्रकोप के दौरान कंपनियों पर अनुपालन बोझ कम हो जाएगा।
- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एमसीए–21 पोर्टल पर अनिवार्य फाइलिंग पर देर से दाखिल करने पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क भी हटा दिया गया है।
- अगले दो तिमाहियों के लिए हर 120 दिनों में एक बार आयोजित की जाने वाली बोर्ड की बैठकों में 60 दिन की छूट दी गई है।
- कंपनियों को कंपनी अधिनियम के तहत इस नियम से भी छूट दी जाएगी कि कम से कम एक निदेशक वर्ष में कम से कम 182 दिन देश में निवास करें।

'टेक फॉर ट्राइबल्स' (आदिवासीयों के लिए तकनीक) कार्यक्रम

समाचार –

- भारतीय ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (आईटीसीएमडीएफआई) ने ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप विकसित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस (आईएनआई) के साथ साझेदारी में एक ट्रांसफॉर्मल 'टेक फॉर ट्राइबल्स' प्रोग्राम लॉन्च किया है।
- 'टेक फॉर ट्राइबल्स' प्रोग्राम का उद्देश्य प्रधान मंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) के तहत नामांकित आदिवासी वन उपज संग्रहकर्ताओं को क्षमता निर्माण और उद्यमिता कौशल प्रदान करके 5 करोड़ जनजातीय उद्यमियों के जीवन को बदलना है।
- यह कार्यक्रम जनजातीय उद्यमियों को विपणन प्रमाणपत्र के साथ विपणन उत्पादों के साथ व्यवसाय को चलाने में मदद करके उच्च सफलता दर सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें सशक्त बनाएगा।
- कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षु छह सप्ताह में 30 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरेंगे, जिसमें 120 सत्र शामिल होंगे। साझेदार संस्थान मूल्य संवर्धन और वन उपज के प्रसंस्करण में उद्यमशीलता से संबंधित पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करेंगे।
- पाठ्यक्रम में एचीवमेंट मोटिवेशन और पॉजिटिव साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटिशन, क्षमता उपयोग, उत्पाद स्थिति – ग्रेडिंग/सॉर्टिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग जैसे विषय शामिल होंगे।

विश्व उपभोक्ता दिवस

समाचार –

- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 'एक सतत उपभोक्ता' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन कर विश्व उपभोक्ता दिवस (15 मार्च) मनाया।
- प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- हालांकि, भारत हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है।
- इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर चुका था और प्रभाव में आया था।
- कोविड–19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक भेद को बनाए रखने के लिए एक भौतिक कार्यक्रम के स्थान पर वेबिनार का आयोजन किया गया था।
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का विषय 'सतत उपभोक्ता' है।
- विषय का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर टिकाऊ खपत की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है, साथ ही उपभोक्ता अधिकारों और सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर कर सकता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन में एकजुटता का संकेत देता है एवं यह मांग करता है कि उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान और संरक्षण किया जाना है।
- यह आयोजन बाजार की उन विधियों जो ग्राहकों के अधिकारों को कमजोर करती है तथा सामाजिक अन्याय के खिलाफ विरोध करने का मौका भी देता है।

विश्व ऊर्जा सांख्यिकी 2019

समाचार –

- भारत दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2017 में प्रति व्यक्ति खपत के मामले में भारत 106 वें स्थान पर था।
- यह 1497 टेरावाट–घंटे (टीडब्ल्युएच) विद्युत उत्पन्न करता है।
- अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- बिजली भी भारत के 8 क़ोर उद्योगों में से एक है।

त्वरित ट्रेन सूचना प्रणाली – रियल टाईम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम (आरटीआईएस)

समाचार –

- ट्रेन की आवाजाही पर बेहतर नजर रखने के लिए त्वरित ट्रेन सूचना प्रणाली स्थापित की जा रही है।
- आरटीआईएस, वास्तविक समय डेटा राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (एनटीईएस) से भी जुड़ा हुआ है।
- आरटीआईएस परियोजना को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
- आरटीआईएस 'द मेक इन इंडिया' का एक उदाहरण है क्योंकि यह देश के भीतर पूरी तरह से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है।

एपीईडीए के एसएफएसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

समाचार –

- हाल ही में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने कृषि गतिविधियों में बेहतर तालमेल लाने के लिए लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (एसएफएसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एपीईडीए, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसानों की सहकारी समितियों को आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता उत्पादन के माध्यम से निर्यात मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के लिए एसएफएसी के साथ संवाद में रहा है।
- कृषि निर्यात नीति के साथ भारत सरकार द्वारा घोषित एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी देश में उत्पाद विशिष्ट समूहों को विकसित करने में मदद करती है ताकि एफपीओ की विशेष भागीदारी के साथ फसलों की किस्मों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- एफपीओ थोक धारकों को थोक दरों पर आवश्यक आदानों की खरीद, उत्पादन और थोक परिवहन के एकत्रीकरण को कम करके उत्पादन लागत को कम करने में मदद करने के लिए एक संस्थागत नवाचार है।
- नीति का उद्देश्य अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एसएफएसी जैसे संगठनों के माध्यम से एफपीओ द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को दूर करना है।

- संयुक्त सहयोग से एसएफएसी और एपीईडीए को कृषि उत्पादों के उत्पादन आधार में मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से सुधार के लिए किसानों की एक बड़े संख्या तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
- यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता की आपूर्ति करने वालों की छवि को बनाए रखेगा और निर्यात की मात्रा और मूल्य में वृद्धि करेगा, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान होगा।

भारिबैं डॉलर–स्वैप विंडो खोला

समाचार –

- भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में तरलता को पंप करने के लिए 6 महीने के अमेरिकी डॉलर की बिक्री–खरीद स्वैप विंडो खोली है, कोविड–19 के प्रसार के कारण अशांति के अनुभव के बाद जो भारत और विश्व भर के वित्तीय बाजारों का पहला कदम है।
- केंद्रीय बैंक ने बाजार में अस्थिरता से लड़ने के प्रयास में, 16 मार्च 2020 को यूएस डॉलर–रुपया बेचने–खरीदने के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर का स्वैप चलाया।
- स्वैप कई नीलामी मार्गों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और नीलामी कई मूल्य–आधारित होगी, अर्थात, सफल बोली उनके संबंधित उद्धृत प्रीमियम मूल्य पर स्वीकार की जाएगी।
- केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दर पर कई किस्तों में 1 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एलटीआरओ) की भी घोषणा की।
- एलटीआरओ एक ऐसा उपाय है जिससे बाजार सहभागियों को उम्मीद है कि वे अल्पकालिक दरों को कम करेंगे और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को भी बढ़ावा देंगे। भारिबैं के पहले शुरू किए गए 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के साथ जोड़े गए ये नए उपाय केंद्रीय बैंक द्वारा बांड पैदावार को प्रबंधित करने और पहले की दर में कटौती के पुश ट्रांसमिशन के लिए एक प्रयास है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

समाचार –

- केंद्र ने 2020–21 के दौरान भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) को जोखिम में डालने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए 340 करोड़ रूपये के पुनर्पूंजीकरण योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे इन क्षेत्रों को मजबूत किया जा सके जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- 18 मार्च 2020 को, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में रुपये 670 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी, जिसे प्रायोजक की द्वारा आनुपातिक हिस्सेदारी के आधार पर जारी किया जाएगा।
- यह एक और वर्ष के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी प्रदान करेगा। उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 2020–21 तक जो 9 प्रतिशत की न्यूनतम सीआरएआर को बनाए रखने में असमर्थ हैं।
- यह 2011 से चल रही योजना है।
- आरआरबी को अपने कुल ऋण का 75 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में देना पड़ता है, जिसमें कृषि ऋण पर प्राथमिक ध्यान दिया जाता है, जिसमें लघु और सीमांत किसान, साथ ही सूक्ष्म उद्यमी और ग्रामीण कारीगर शामिल हैं।
- कोविड–19 संकट के कारण लॉकडाउन के समय, ग्रामीण क्षेत्रों में तरलता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत ग्रामीण बैंक भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की योजना

समाचार –

- भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन योजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें लगभग 48,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शामिल है।

विवरण –

- तीन योजनाएं एक साथ 21 मार्च 2020 को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, घटकों की एक घरेलू आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र तथा बड़ी लंगर इकाइयों और उनके आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाओं और अत्याधुनिक सुविधाओं के एक राज्य को सक्षम करेगी।

- इस योजना से क्षेत्र में कम से कम 50,000 करोड़ रुपये के नए निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जबकि 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 15 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य 5 वर्षों के लिए 40,995 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय पर मोबाइल फोन निर्माण और विधानसभा, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करना है।
- यह योजना भारत में निर्मित सामानों की वृद्धिशील बिक्री पर 4–6 प्रतिशत की प्रोत्साहन की पेशकश करेगी और कुल 8 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
- मोबाइल फोन के लिए घरेलू मूल्य वृद्धि 2025 तक वर्तमान 20–25 प्रतिशत से 3540 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है जो इस योजना द्वारा प्रदान की गई प्रेरणा के कारण है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और अर्धचालक के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना के अंर्तगत 8 वर्षों में 3285 करोड़ रूपये का परिव्यय किया गया है और लगभग 6 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
- तीसरी योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी) 2.0, का लक्ष्य आठ वर्षों में 3762.25 करोड़ रूपयों से विशिष्ट सुविधाओं जैसे कि सामान्य सुविधा केंद्रों, रेडी–बुलिट फैक्ट्री शेड/प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ–साथ 200 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र के साथ गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इस योजना से लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

वित्त अधिनियम

समाचार –

- संसद ने, वित्त अधिनियम में संशोधन पारित किये है जिसमें 15 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा शुरू की गई है, प्रवासी भारतीयों पर कर लगाने, ई–कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए एक समान लेवी, उन लोगों द्वारा नकद वापसी के लिए टीडीएस की अनिवार्यता में वृद्धि, जिन्होंने 3 वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और शिक्षा ऋण के पैसे निकालने के लिए स्रोत (टीसीएस) पर एकत्रित कर की कम दर इत्यादि कुछ संशोधनों किए गए हैं।
- सरकार ने सेवाओं की आपूर्ति में शामिल अनिवासी ई–कॉमर्स ऑपरेशन के लिए समान लेवी के दायरे का विस्तार किया, जिसमें माल की ऑनलाइन बिक्री और सेवाओं का प्रावधान शामिल है।

किसान रेल

समाचार –

- सरकार ने कृषि मंत्रालय के तहत एक समिति का गठन किया है जिसमें भारतीय रेलवे के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है ताकि 'किसान रेल' के तौर–तरीकों पर काम किया जा सके।
- किसान रेल को खराब हो सकने वाले माल की आपूर्ति के लिए कोल्ड सप्लाई चेन के लिए सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से स्थापित करने का प्रस्ताव था।
- इस तरह के नौ प्रशीतित यान पहले से ही नेटवर्क पर उपलब्ध थे। अत्यधिक खतरनाक पार्सल यातायात के परिवहन के लिए प्रत्येक में 17 टन की क्षमता वाली ये यान कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री के माध्यम से विकसित और खरीदी किए गए थे।

एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा बढ़ाई गई

समाचार –

- निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने 13 मार्च 2020 को घोषणा की कि उसने एयर इंडिया लिमिटेड के लिए बोली की समय सीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 कर दिया है। पहले यह समय सीमा 17 मार्च 2020 को समाप्त हो रही थी।
- केंद्र ने एयर इंडिया की प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) से संबंधित प्रश्नों पर प्रतिक्रिया की अंतिम तिथि 16 मार्च से 20 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है।
- समय सीमा की यह वृद्धि, कोविड–19 प्रकोप की पृष्ठभूमि में की गई है, जिसने अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से विमानन और पर्यटन क्षेत्रों और दुनिया भर में निवेश की भावनाओं को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है।
- 100 से अधिक देशों में वायरस के प्रसार ने यात्रा और आतिथ्य उद्योग को सबसे अधिक हानि पहुँचाई है, जिसमें देशों में आवक और जावक दोनों यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- सरकार, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया में अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी को विनिवेशित करना है, ने महंगे टर्नअराउंड योजना की विफलता और नियंत्रण हिस्सेदारी बेचने के लिए किए गए पहले प्रयास के बाद, संभावित निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित करके जनवरी 2020 में हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया शुरू की थी।

- केंद्र ने एयर इंडिया के ऋण को 56,334 करोड़ रूपयों से घटाकर लगभग 23,287 करोड़ रूपये कर दिया है।
- कैबिनेट ने हाल ही में स्वचालित मार्ग के तहत अनिवासी भारतीयों द्वारा एयर इंडिया में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन को मंजूरी दी थी।

रोपाक्ष सेवा

समाचार –

- केंद्रीय नौवहन मंत्री ने महाराष्ट्र में मुंबई, मांडवा, अलीबाग से भुच्चा ढाका के लिए रोपाक्ष सेवा का उद्घाटन किया।
- रोपाक्ष सेवा एक 'जल परिवहन सेवा परियोजना 'है, जो पूर्वी जलमार्ग विकास के तहत है।
- रोपाक्ष वेसल एम 2 एम –1 एक बार में 200 कारों और 1000 यात्रियों को ले जा सकता है और दोनों तरफ एक रैंप है, इसलिए कारें आसानी से जहाज के अंदर और बाहर जा सकती हैं।
- इस सेवा के लाभों में यात्रा समय में कमी, वाहनों का उत्सर्जन और सड़क पर यातायात शामिल हैं।
- मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने 31 करोड़ रुपये की लागत से भूखा ढाका (फेरी घाट) में रोपाक्ष जेटी और टर्मिनल सुविधाएं विकसित की हैं। महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड ने 135 करोड़ रुपये की लागत से मंडवा में ब्रेकवाटर, रोपाक्ष जेट्टी और टर्मिनल सुविधाएं विकसित की हैं।

सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी हुई

समाचार –

- सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। 13 मार्च 2020 को कैबिनेट की बैठक में निर्णय को मंजूरी दी गई। इसका मतलब है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन/पेंशन के 17 प्रतिशत से बढ़ाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मूल वेतन/पेंशन का 21 प्रतिशत कर दिया गया है।
- इस कदम से कम से कम 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होगी। सरकारी खजाने की लागत लगभग 14,500 करोड़ रूपये होगी।
- डीए सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए जाने वाले जीवन निर्वाह भत्ते की लागत है और इसकी गणना मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- इसे मूल रूप से वेतन के एक घटक के रूप में समझा जा सकता है जो मूल वेतन का कुछ निश्चित प्रतिशत है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है।

2020 के अंत तक भारत की साझा अर्थव्यवस्था 2 बिलीयन डॉलर होगी

समाचार –

- मेपल कैपिटल एडवाइजर्स की 'शेयर्ड ईकोनॉमी–इंडिया स्टोरी' रिपोर्ट के अनुसार, 2020 तक भारत में साझा अर्थव्यवस्था लगभग 2 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
- 'साझा अर्थव्यवस्था' में सह–कामकाज (एवफिस, वेवर्क इंडिया), सह–जीवन (स्टेन्जा लिविंग, ओयो लाइफ, ऑक्सफोर्ड कैप्स), साझा गतिशीलता (उबेर, ओला, शट्ल) और फर्नीचर किराये (फुरेलेंको, रेंटोमोजो) जैसे खंड शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, उच्च मोबाइल पैठ, उच्च सहस्राब्दी एकाग्रता और एक आकांक्षात्मक आबादी के साथ, एशिया में साझा परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उच्चतम इच्छा है।
- भारत इन पहलुओं में एशिया के रुझानों को दर्शाता है और इस तरह उच्च विकास और साझा सेवाओं को अपनाने के लिए तैयार है।
- सह–कार्य क्षेत्र के लिए बाजार का आकार 500 मिलियन डॉलर आंका गया है, जबकि सह–जीवन के लिए 400 मिलियन डॉलर का अनुमान लगाया गया है, 630 मिलियन डॉलर से अधिक की साझा गतिशीलता और फर्नीचर किराये पर 200 मिलियन डॉलर।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अब तक इस तरह की सेवाओं में लगभग 3.7 बिलियन डॉलर की पूंजी का उपयोग किया गया है, यह कहते हुए कि अगले कुछ वर्षों में भी इसी तरह की राशि का उल्लंघन होने की आशंका है।
- रिपोर्ट में कहा गया है, 'जलवायु, अपव्यय, संसाधन की कमी और जनसंख्या की तीव्रता (विशेष रूप से विकासशील दुनिया में) पर बढ़ती चिंता के इस युग में, साझा अर्थव्यवस्था इन चिंताओं को दूर करने का एक स्थायी, स्केलेबल और कुशल रूप है।'

कर्नाटक में कोकून उत्पादन

समाचार –

- शहतूत की बीमारी की चपेट में आने के बाद, कर्नाटक में कोकून उत्पादन स्वदेशी रेशम की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए समय पर उठता प्रतीत हो रहा है।
- कीटनाशकों के इस्तेमाल से राज्य में जलवायु के हालिया बदलाव ने इस बीमारी को नियंत्रण में ला दिया है, और राज्य भर के अधिकांश कोकून बाजारों में आवक में वृद्धि दर्ज की गई है।
- चीन से रेशम का आयात कोरोनावायरस के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चीन से रेशम की खेप लगभग दो महीने तक भारतीय तटों तक नहीं पहुंचने से अब इस स्वदेशी रेशम के अंतर को पाटने की उम्मीद है।
- सेरीकल्चर कृषि आधारित उद्योग है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है।
- रेशम के कीड़ों को पालने के लिए रेशम की खेती की प्रमुख गतिविधियों में खाद्य–पौधों की खेती शामिल है, जो प्रसंस्करण और बुनाई जैसे कार्यों के लिए रेशम के रेशा को तैयार करने के लिए कोकून को फिर से जमा करती है।
- रेशम के कीड़ों की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त वाणिज्यिक महत्व के रेशम के पांच प्रमुख प्रकार हैं। ये शहतूत, ओक तसर, उष्णकटिबंधीय तसर, मुगा और एरी हैं।
- उपरोक्त में से सुनहरी पीली चमक के साथ मुगा रेशम भारत में अनूठा और प्राचीन है।
- दक्षिण भारत देश का प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है और यह कांचीपुरम, धर्मावरम, अरनी, आदि जैसे प्रसिद्ध रेशम बुनाई परिक्षेत्रों के लिए भी जाना जाता है।

मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकरसेठ टर्मिनस किया गया

समाचार –

- महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकरसेठ टर्मिनस रखने का प्रस्ताव पारित किया।
- जगन्नाथ शंकरसेठ 19 वीं शताब्दी की शुरुआत में एक उद्योगपति और शिक्षाविद् थे। वे भारत की पहली रेलवे कंपनी के पहले निदेशकों में से एक थे।

स्त्रोत स्थिरता और जलवायु तन्यक वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना

समाचार –

- भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार लाने और हिमाचल प्रदेश, जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक पहाड़ी राज्य है, में चयनित ग्राम पंचायतों (ग्राम परिषदों) में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- हिमाचल प्रदेश में स्त्रोत स्थिरता और जलवायु तन्यक वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना 428 जिलों की 10,000 ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी, जिसमें 4,00,000 से अधिक छोटे किसानों, महिलाओं और देहाती समुदायों को लाभ होगा।
- यह परियोजना वनों, चरागाहों और घास के मैदानों में ऊपरी जल स्रोतों में सुधार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हिमाचल प्रदेश और नीचले राज्यों में टिकाऊ कृषि के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो।
- कृषि और इसकी संबद्ध गतिविधियों की जलवायु तन्यकता बढ़ाना परियोजना का एक प्रमुख घटक है जिसके लिए पानी का कुशल उपयोग केंद्र बिंदु है। परियोजना जल गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी के लिए हाइड्रोलॉजिकल निगरानी स्टेशन स्थापित करेगी।
- यह न केवल बेहतर भूमि उपयोग और कृषि निवेशों के माध्यम से भविष्य के पानी के बजट की नींव रखने में मदद करेगा, बल्कि अधिक समग्र कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (कैट) योजनाओं को भी सुनिश्चित करेगा जो स्रोत स्थिरता, कार्बन अनुक्रम और जल गुणवत्ता पर आधारित हैं।

सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन

समाचार –

- अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, गुजरात ने देश भर में सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना में सूची में सबसे ऊपर है, 2 मार्च 2020 तक लगभग 50,915 सिस्टम राज्य में घरेलू छतों पर लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र ऐसे 5,513 प्रतिष्ठानों के साथ गुजरात के पीछे है।
- देश भर में स्थापित 79,950 प्रणालियों में, गुजरात 64 प्रतिशत या दो–तिहाई कुल घरेलू सौर छत प्रतिष्ठानों के साथ शीर्ष पर है।

- राज्य सरकार ने 2022 तक योजना के तहत लगभग आठ लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कवर करने के लिए – सौर गुजरात – सूर्य गुजरात योजना को अपनाया है।
- सरकार ने योजना के लिए लगभग 912 करोड़ भी आवंटित किए हैं।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए उत्पादों का ई–विपणन

समाचार –

- दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाय–एनयुएलएम) के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमेजॅन के साथ देश भर में शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए उत्पादों के ई मार्केटिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- महिला सशक्तीकरण की एक अंतर्निहित कथा के साथ, सहयोग का उद्देश्य एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच प्रदान करना और शहरी क्षेत्रों में स्थायी आजीविका बनाने के मिशन को मजबूत करना है।
- मिशन ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ भी ऐसा ही सहयोग किया है। ये सहयोग 28 मार्च से 12 अप्रैल, 2020 तक आयोजित किए जाने वाले शहरी समृद्धि उत्सव के दूसरे संस्करण के लिए प्रमुख पहलों का हिस्सा हैं।
- एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देने से, पहल करने और विभिन्न राज्यों की अनूठी पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
- डीएवाई–एनयूएलएम, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और भेद्यता को कम करने के लिए उन्हें सक्षम स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

समाचार –

- दुनिया के दो सबसे बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्रों सऊदी अरब एवं रूस के बीच मूल्य युद्ध शुरू होने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आ गई है।

ओपेक–प्लस गठबंधन –

- 2014 के बाद 'ग्लट' कूटनीति जिससे कच्चे तेल की कीमतों को यूएसडी 30 प्रति बैरल से नीचे की लाया गया था, के दौरान सऊदी अरब एवं रूस उत्पादन में कटौती और कीमतों को स्थिर करने के लिए एक साथ आए थे। इसे ओपेक प्लस व्यवस्था के रूप में जाना जाता है (रूस ओपेक का सदस्य नहीं है), इस गठबंधन ने उत्पादन कम रखा और कीमतों को ऊपर रखा।
- रूस द्वारा सऊदी अरब के कोविड–19 के चजमं आई माँग में कमी के मद्धेनजर उत्पादन में और अधिक कटौती के अनुरोध को खारिज करने के बाद मार्च 2020 में यह गठबंधन ध्वस्त हो गया।

सउदी क्या चाहते हैं?

- जैसा कि यह स्पष्ट है, रूस अपने उत्पादन में और कटौती करने के लिए तैयार नहीं है, सउदी आक्रमण मुद्रा में आ गए।
- सऊदी योजना, कच्चे तेल के बाजारों में उत्पादन की बाढ़ लाने और कीमतों को और कम करने की है, जिससे सभी तेल निर्यातकों को नुकसान होगा।
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, कम खाद्य कीमतों और कमजोर मांग के कारण मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में सुधार हुआ। सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2020 में 6.58 प्रतिशत तक धीमी हो गई, जबकि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि सूचकांक में मापा गया।
- औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) विनिर्माण क्षेत्र द्वारा प्रदर्शन के बीच, जनवरी 2020 में 2 प्रतिशत तक बढ़ गया।

स्वास्थ्य एवं समाज

सामाजिक लिंग मानदंड सूचकांक (जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स)

समाचार –

- जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया गया है।
- यह सूचकांक बताता है कि कैसे सामाजिक विश्वास राजनीति, काम और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बाधित करते हैं, और इसमें 75 देशों के डेटा शामिल हैं, जो दुनिया की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी को कवर करते हैं।

- यह सूचकांक इस बात पर प्रकाश डालता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं को बंद करने की वास्तविक प्रगति के बावजूद पुरुषों और महिलाओं के बीच 'पावर गैप' अभी भी मौजूद है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरुष और महिला समान दरों पर मतदान करते हैं, दुनिया भर में केवल 24 प्रतिशत संसदीय सीटें महिलाओं के पास हैं और 193 सदस्य राज्यों में से केवल 10 महिला प्रमुख सरकारें हैं।
- इसके अलावा, महिलाओं को समान काम करने वाले पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है और वरिष्ठ पदों पर रहने की संभावना बहुत कम होती है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया का कोई देश 'लैंगिक समानता' वाला नहीं है।
- सूचकांक के अनुसार, लगभग आधी दुनिया के पुरुषों और महिलाओं को लगता है कि पुरुष बेहतर राजनीतिक नेता बन सकते हैं, और 40 प्रतिशत से अधिक लोगों को लगता है कि पुरुष बेहतर व्यवसायिक अधिकारी बन सकते हैं और यह कि जब नौकरी दुर्लभ होती है, पुरुषों के पास नौकरी के लिए अधिक अधिकार होते हैं। 28 प्रतिशत को लगता है कि एक आदमी के लिए अपनी पत्नी को पीटना जायज है।
- लगभग 30 देशों में पूर्वाग्रह कैसे बदल रहे हैं, इस पर भी जानकारी उपलब्ध है। यह दर्शाता है कि कुछ देशों में सुधार हुआ है, जबकि अन्य में, रवैया हाल के वर्षों में बिगड़ गया है, यह दर्शाता है कि प्रगति हुई है ऐसा नही समझा जा सकता।
- 2020 में बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (बीजिंग–25) की 25 वीं वर्षगांठ भी है जो महिला सशक्तिकरण पर अब तक का सबसे दूरदर्शी एजेंडा है।
- यूएनडीपी सरकारों और संस्थानों से शिक्षा के माध्यम से इन भेदभावपूर्ण मान्यताओं और प्रथाओं को बदलने और जागरूकता बढ़ाने और प्रोत्साहन को बदलने के लिए नीतियों की एक नई पीढ़ी का उपयोग करने के लिए कह रहा है।
- विश्व नेताओं ने लैंगिक समानता पर वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऑपरेशन नमस्ते

समाचार –

- भारतीय सेना ने सरकार को महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए अपने एंटी–कोविड –19 अभियान को ऑपरेशन नमस्ते का कोड–नाम दिया है।
- सैनिकों को, जहां भी उनकी कोई परिचालन भूमिका नहीं है लॉकडाउन का पालन करने और फिट रहने की सलाह दी जाती हैं। उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि उनके परिवारों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा।
- छुट्टी पर जाने वालों का विस्तार और साथ ही छुट्टीयों को कम किया जा रहा है ताकि आवाजाही कम से कम हो।
- विभिन्न राज्यों से छुट्टी से वापिस आने वाले सैनिकों के निरीक्षण के लिए अलग सुविधाएं स्थापित की गई हैं।
- अब तक मानेसर, जैसलमेर, जोधपुर, चेन्नई, हिंडन और मुंबई में छह संगरोध सुविधाएं स्थापित की गई हैं, जहां कोरोनोवायरस प्रभावित देशों से निकाले गए 1,463 लोगों को समायोजित किया गया है।
- सेना कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि, डंडीगल, बेंगलुरु, कानपुर, जैसलमेर, जोरहाट और गोरखपुर में ऐसी और सुविधाएं स्थापित कर रही है जो जरूरत पड़ने पर 72 घंटों के भीतर तैयार हो सकती हैं।
- 28 सशस्त्र बल अस्पतालों को कोविड अस्पतालों के रूप में निर्धारित किया गया है।
- इन अस्पतालों में सशस्त्र बल के रोगियों के साथ–साथ राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से स्थानांतरित नागरिक रोगी भी शामिल होंगे।
- थल सेना, नौसेना और वायु सेना के पांच अस्पताल कोरोनोवायरस परीक्षण का उपयोग कर रहे हैं आरटी–पीसीआर पद्धति और अधिक अस्पताल जल्द ही संसाधनों से लैस होंगे।
- 62 छावनी बोर्डों को अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों और किसी भी घटना के लिए गेस्टहाउस में बेड की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खुशी दिवस (20 मार्च) पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की। विश्व खुशी दिवस को वर्ष 2012 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है।

विवरण –

- रिपोर्ट 156 देशों को शामिल किया गया है तथा यह बताती है कि इन देशों के नागरिक खुद को कितना खुश मानते हैं।
- रैंकिंग मतदान (गैलप वर्ल्ड् पोल) पर आधारित है, जो छह चरों – जीडीपी प्रति व्यक्ति, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति को मापता है।
- 2020 की रिपोर्ट में पहली बार दुनिया भर के शहरों को उनके व्यक्तिपरक कल्याण द्वारा देखा गया और इस बात पर ध्यान दिया गया कि सामाजिक, शहरी और प्राकृतिक वातावरण कैसे खुशी को प्रभावित करते हैं।

मुख्य विचार –

- फिनलैंड लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश है।
- नॉर्डिक राज्यों ने स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के साथ शीर्ष 10 में अपना दबदबा बनाया।
- लक्जमबर्ग इस वर्ष पहली बार 10 वें स्थान पर पहुंच गया।
- नीचे के देशों में जिंबाब्वे, दक्षिण सूडान और अफगानिस्तान हैं जो हिंसक संघर्ष और अत्यधिक गरीबी से पीड़ित हैं ये दुनिया के सबसे कम खुश देशों के रूप में वर्गीकृत हैं।

भारत की स्थिती –

- भारत अपने पहले के स्थान 140 से नीचे गिरकर 144 पर आ गया।
- इसकी रैंक अपने पड़ोसियों की तुलना में कम है।
- नेपाल 92 वें स्थान पर, पाकिस्तान 66 वें स्थान पर, बांग्लादेश 107 वें और श्रीलंका 130 वें स्थान पर है।
- भारत सबसे नीचले पंद्रह देशो के समूह में एक नया प्रवेश है।

पारंपरिक दवाओं को कवर करने के लिए नया नियामक निकाय

समाचार –

- राज्य सभा ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएम) विधेयक, 2019 और क्रमशः चिकित्सा और होम्योपैथी की भारतीय पारंपरिक प्रणालियों के लिए अलग–अलग आयोगों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी विधेयक, 2019 पारित किया।
- नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (एनसीआईएम) विधेयक, 2019 पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नए निकाय के साथ मौजूदा नियामक सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन (सीसीआईएम) की जगह लेना चाहता है।
- जबकि, नेशनल कमिशन फॉर होम्योपैथी बिल, 2019 का उद्देश्य सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को प्रतिस्थापित करना है, जो होम्योपैथी के लिए वर्तमान नियामक निकाय है।

आयुष वेलनेस सेंटर एनएएम के तहत

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) में आयुष्मान भारत के आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (आयुष एचडब्ल्यूसी) के घटक को शामिल करने को मंजूरी दी है।
- प्रस्ताव में 3399.35 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है – आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को पाँच वर्ष की अवधि में संचालित करने के लिए 22209.5 करोड़ रुपये केंद्र तथा 1189.88 करोड़ रूपये राज्य के हिस्से के रूप में दिए जाने हैं।
- इस कदम का उद्देश्य आयुष सिद्धांतों पर आधारित समग्र स्वास्थ्य मॉडल की स्थापना करना है और मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ एकीकरण द्वारा निवारक, प्रचारक, उपचारात्मक, पुनर्वास स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने एकीकृत स्वास्थ्य सेवा की बहुलतावादी प्रणाली के भीतर आयुष प्रणालियों (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा–रिग्पा और होम्योपैथी) की मुख्यधारा संभावनाओं की वकालत की थी।

CHAHAL ACADEMY

अंग दान

- महाराष्ट्र अंग दान के क्षेत्र में तमिलनाडु और तेलंगाना से आगे निकल गया और इस क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया।
- संवेदीकरण ड्राइव और क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के सावधानीपूर्वक प्रयास – राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोटो–सोटो) के साथ चार जोनल प्रत्यारोपण समन्वय केंद्र (ज़ेडआईसीसी) इस उपलब्धि के पीछे महत्वपूर्ण योगदान कारक हैं।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) और राज्यों के स्तर पर क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोटो) और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोटो) की स्थापना की है।
- अंग प्रत्यारोपण और दान की अनुमति कानून द्वारा दी जाती है, और इसे 'मानव अंगों अधिनियम 1994 के प्रत्यारोपण' के तहत कवर किया गया है, जिससे लाइव और ब्रेन–स्टेम डेड दाताओं द्वारा अंग दान की संभावना उत्पन्न हुई है।
- 2011 में, अधिनियम के संशोधन से मानव ऊतकों को भी दान के दायरे में लाया गया, जिससे संशोधित अधिनियम 'मानव अंगों और ऊतकों अधिनियम 2011 का प्रत्यारोपण' था।

दिव्य कला शक्ति – विकलांगों में साक्षीभाव

समाचार –

- पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम "दिव्य कला शक्ति – विकलांगों में साक्षीपन" का आयोजन चेन्नई (तमिलनाडु) में राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान (दिव्यांगजन), चेन्नई के सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से विकलांग (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था।
- यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें प्रदर्शन कला, संगीत, नृत्य, कलाबाजी आदि के क्षेत्र में अलग–थलग रहने वाले व्यक्तियों की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए एक व्यापक और अनूठा मंच प्रदान किया गया है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 18 अप्रैल और 23 जुलाई 2019 को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया था।
- आयोजन में दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न विकलांगों के साथ लगभग 98 बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने शास्त्रीय, लोक और आधुनिक शैली में नृत्य, संगीत आदि का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में पहली बार योग और कलाबाजी भी शामिल थी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्युडी) 2020

समाचार –

- महिला और बाल विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण और सरकार के अन्य मंत्रालय जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (एच एंड एफडब्ल्यू), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), कृषि और किसान कल्याण (एएंड एफडब्ल्यू), ग्रामीण विकास (आरडी), आवास और शहरी मामलों (एचयूए), वित्त, रक्षा और गृह ने 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्युडी) 2020 को मनाने के एक कैंपेन की शुरूआत की।
- अभियान में 1 मार्च, 2020 से शुरू होने वाले सभी दिनों के लिए एक थीम थी। जिन विषयों को शामिल किया गया उनमें– शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, महिलाओं का सशक्तिकरण, कौशल और उद्यमिता तथा खेल, विशेष परिस्थितियों, ग्रामीण महिलाओं और कृषि और शहरी महिलाओं में भागीदारी इत्यादि थे।
- दूरदर्शन ने भारतीय संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को याद करने तथा भारतीय गणतंत्र की नींव में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए।
- पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं और महिला सभाओं (महिला सभाओं) को आयोजित करने का निर्देश दिया है।
- इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज (आइएनसीओआईएस), हैदराबाद ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।
- भारत के प्रधान मंत्री ने सात महिला प्राप्तकर्ताओं को अपने सोशल मीडिया खातों का नियंत्रण सौंपकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को चिह्नित किया।
- इस दिनयह घोषित किया गया है कि केंद्र जनवरी 2021 से सेनेटरी नैपकिन कंपनियों के लिए जैव–अपघर्षक निपटान बैग प्रदान करना अनिवार्य कर देगा।

CHAHAL ACADEMY

- वास्तव में, स्कॉटलैंड टैम्पोन और पैड को निःशुल्क बनाने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। स्कॉटलैंड की संसद ने 25 फरवरी 2020 को पीरियड प्रोडक्ट्स (फ्री प्रोविजन) स्कॉटलैंड बिल पास किया, जो कि टेंपॉन, पैड और अन्य मासिक धर्म उत्पादों के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करेगा, जो कि गरीबी के खिलाफ वैश्विक आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है।
- महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए, भारत सरकार ने 8 मार्च 2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा महिला सशक्तीकरण के कारणों के लिए उनकी सेवा की मान्यता में प्रतिष्ठित महिलाओं और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया।
- युनाईटेड नेशन वुमेन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के लिए विषय है ' समानता का सृजन – महिलाओं के अधिकारों को साकार करना'।
- इससे पहले, इसे राष्ट्रीय महिला दिवस कहा जाता था और 28 फरवरी, 1909 को अमेरिका में इसे पहली बार मनाया गया।
- जर्मन महिला अधिकार कार्यकर्ता क्लारा जेटकिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सुझाव दिए जाने के बाद ही 1910 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दी गई थी।
- इस दिन 1917 में सोवियत रूस में महिलाओं ने वोट का अधिकार प्राप्त किया था, इसलिए 8 मार्च को उनके लिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सदस्य राज्यों को 1977 में महिलाओं के अधिकारों और विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में 8 मार्च को घोषित करने के लिए आमंत्रित किया।

शहरी गरीब महिलाओं के बीच कुपोषण

समाचार –

- हाल के एक अध्ययन के अनुसार, शहरी क्षेत्रों की गरीब महिलाएँ उच्चतर धन सम्पदा वर्ग की तुलना में छोटी, पतली और अधिक एनीमिक थीं।
- यह 2005–2006 (डीएचएस –3) और 2015–16 (डीएचटी –4) के दौरान आयोजित जनसांख्यिकी स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दो राउंड से डेटा का विश्लेषण करता है।
- अध्ययन में शहरी गरीब माताओं की सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं की भी जांच की गई है और पाया गया है कि उनमें से 49.3 प्रतिशत का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था, जबकि सभी शहरी माताओं के 31.2 प्रतिशत की तुलना में शहरी गरीबों में एक चौथाई या उससे अधिक माताएँ थीं।
- सभी शहरी माताओं के बीच 17 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जाति के घरों से थे और डीएचएस–4 में उनमें से 40 प्रतिशत से कम के पास बीपीएल कार्ड था।
- अध्ययन में पोषण सेवाओं के साथ–साथ एनीमिया की जांच के लिए शहरी गरीब महिलाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है।
- यह शहरी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के बेहतर कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए नए तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता भी बताता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) विभिन्न कारणों से शहरों में परिणाम देने में असमर्थ हैं, जिनमें उच्च जनसंख्या घनत्व भी शामिल है।
- अध्ययन पौष्टिक खाद्य पदार्थों और परामर्श सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी चोट करता है और राष्ट्रीय पोषण में अधिक वजन और मोटापे की चुनौतियों का सामना करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना करता है शहरी आबादी और विशेष रूप से गरीबों के रूप में मिशन अधिक जोखिम में हैं।

कार्यस्थल सुरक्षा

समाचार –

- नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया, भारत (एनडब्ल्युएमआई) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 70 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए एक आंतरिक समिति से संपर्क किया था, जो परिणाम से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे।
- सर्वेक्षण में पाया गया कि सभी उत्तरदाताओं में से 36 प्रतिशत ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का अनुभव किया। काम पर ऐसे उत्पीड़न का अनुभव करने वाले उत्तरदाताओं में से, 53 प्रतिशत ने इसकी सूचना किसी को नहीं दी।
- एक छोटे प्रतिशत ने अपने मीडिया हाउसों की आंतरिक समिति (आईसी) को एक रिपोर्ट दी। लेकिन शिकायत करने वालों में से 70 प्रतिशत परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे।

- जिन महिलाओं ने कहा कि उनके संगठन में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक तंत्र नहीं था, 47 प्रतिशत ने यौन उत्पीड़न का सामना किया था।
- उत्तरदाताओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले उत्पीड़न के प्रकारों के संदर्भ में, सबसे आम सेक्सिस्ट टिप्पणिया, अनचाहे यौन चुटकुले, शर्मनाक इशारे या शारीरिक भाषा, अवांछित रोमांटिक और/या यौन संबंधों को स्थापित करने का प्रयास, और डेट्स को थोपना इत्यादि शामिल था।

महुआ आधारित मादक पेय

समाचार –

- सरकार द्वारा भारतीय बाजार में पहली बार एक नया मादक पेय पेश किए जाने की संभावना है। पेय महुआ–आधारित है और इसका नाम महुआ न्यूट्रिवरेज है। यह पहली बार है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय बोतलबंद और मादक पेय पदार्थों की बिक्री कर रहा है।
- इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली द्वारा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राईफेड) के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका विपणन वन धन विकास कार्यकम के तहत किया जा रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पेय अप्रैल 2020 तक बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। लगभग 700 रुपये की कीमत पर, पेय में छह फल आधारित स्वाद होंगे और मात्रा 750 मिलीलीटर होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्कोहल की मात्रा तुलनात्मक रूप से 5 फीसदी कम है और इसे पीने का पोषण मूल्य उच्च है।

पीएचडी में अजा, अजजा छात्रों का नामांकन कार्यक्रम

समाचार –

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, हाशिए पर रह रहे समुदायों के छात्रों, मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी), का नामांकन 2015 से 2019 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के पीएचडी कार्यक्रमों में कम रहा है।
- 25,007 में से पीएचडी पांच वर्ष की अवधि में 23 आईआईटी में विद्वानों ने प्रवेश किया, केवल 9.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति समुदायों से और 2.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से थे। यह पूर्व के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत सीटों और बाद के लिए 7.5 प्रतिशत से कम है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों ने 23.2 प्रतिशत का आरक्षण किया, जो कि आरक्षण के अनिवार्य 27 प्रतिशत से भी कम है। लगभग दो–तिहाई प्रवेश (65.6 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए गए।
- हालांकि, इस अवधि के दौरान पीएचडी कार्यक्रमों में नामांकन के कुल मामलों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस वृद्धि के परिणामस्वरूप दो समुदायों के छात्रों की संख्या में समान वृद्धि नहीं हुई।

शून्य भेदभाव दिवस

समाचार –

- प्रतिवर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम द्वारा मनाया जाता है।
- यह पहली बार 2014 में मनया गया था जब यूएनएड्स ने दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपना शून्य भेदभाव अभियान शुरू किया था।
- 2020 थीम – महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव

सरकारी स्कूल के बुनियादी ढांचे में कमी

समाचार –

- मानव संसाधन विकास (एचआरडी) रिपोर्ट पर संसदीय स्थायी समिति ने खुलासा किया कि केवल 56 प्रतिशत स्कूलों में बिजली है, जिसमें मणिपुर और मध्य प्रदेश में सबसे कम दर है, जहां 20 प्रतिशत से कम बिजली की पहुंच है।
- युडीआईएसई सर्वेक्षण के अनुसार, 57 प्रतिशत से कम स्कूलों में खेल के मैदान हैं, जिनमें ओडिशा और जम्मू और कश्मीर के 30 प्रतिशत से कम स्कूल शामिल हैं।
- अनुदान की मांग में 2020–2021 में, बजटीय आवंटन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए गए प्रस्तावों से 27 प्रतिशत कटौती हुई थी।

- सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मजबूत करने के लिए कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के निर्माण में प्रगति की निराशाजनक दर सरकारी स्कूलों से छात्रों को अलग कर देगी।
- 2019–20 के लिए स्वीकृत 2,613 परियोजनाओं में से केवल तीन वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में पूरी हो गई थीं।
- सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, स्वीकृत 1021 में से, 31 दिसंबर, 2019 तक एक भी अतिरिक्त कक्षा का निर्माण नहीं किया गया था।
- 1,343 प्रयोगशालाओं के लिए स्वीकृत धन के विरुद्ध, केवल तीन प्रयोगशालाएँ बनाई गई थीं।
- पुस्तकालयों, कला/शिल्प संस्कृति के कमरे के मामले में, क्रमश प्रतिशत 135 और 74 के स्वीकृत लक्ष्य के बावजूद अभी तक कोई भी निर्माण नहीं किया गया था।
- कुल मिलाकर, मुख्य समझौता शिक्षा योजना के लिए, विभाग ने 31 दिसंबर, 2019 तक संशोधित अनुमानों का केवल 71 प्रतिशत खर्च किया था।

विज्ञान एवं तकनीक

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन संयोजन की अनुमति दी

समाचार –

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीर बीमारी के रोगियों के लिए नजदीकी निगरानी के तहत आईसीयू और कोविड–19 नैदानिक प्रबंधन पर जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार एजिथ्रोमाइसिन के साथ हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग की अनुमति दी है।
- हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पहले परीक्षण में था तथा केवल डॉक्टरों और कोविड–19 सकारात्मक मामलों के साथ सीधे संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को इसे प्रशासित करने की अनुमति दी गई थी।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाया है कि वर्तमान आँकड़ों के अनुसार किसी भी विशिष्ट एंटीवायरल प्रभावी नही पाया गया है तथापि उपलब्ध जानकारी के आधार पर (अनियंत्रित नैदानिक परीक्षण) निम्नलिखित दवाओं पर विचार किया जा सकता है।

अल्ट्रावायलेट (यूवी) सैनिटाइजर

समाचार –

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के औद्योगिक डिजाइन केंद्र (आईडीसी), बॉम्बे ने एक पोर्टेबल अल्ट्रावायलेट (यूवी) सेनेटाईज़र विकसित किया है।
- यह हाथ से हाथ में पारित होने वाली वस्तुओं जैसे कि पर्स और अन्य छोटी वस्तुओं को शुद्ध कर सकता है।
- यूवी सेनेटाईज़र को स्टेनलेस स्टील रसोई के कंटेनरों और एल्यूमीनियम जाल का उपयोग कर बनाया गया है और अभी यह प्रूफ–ऑफ–कांसेप्ट स्टेज में है।
- यह डिजाइन यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक जर्नल पबमेड में प्रकाशित अध्ययन पर आधारित है।
- अध्ययन में यह पाया गया है कि किस प्रकार अल्ट्रावायलेट सी लाईट गंभीर तीव्र श्वसन कोरोनावायरस, क्रीमियन–कांगो, रक्तस्रावी बुखार (सीसीएचएफ) वायरस और निप्पा वायरस को निष्क्रिय कर सकती है।
- ऑब्जेक्ट वायरस के वाहक हो सकते हैं और सेनेटाईजींग जेल का उपयोग हर वस्तुओं मनुष्य के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं जैसे कि कागज, फाइल, मुद्रा नोट और फोन पर नहीं किया जा सकता है।

गेहूं की किस्म एमएसीएस 4028

समाचार –

- पुणे स्थित अघारकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई) के वैज्ञानिकों ने बायोफोर्टिफाइड ड्यूरम गेहूं किस्म एमएसीएस 4028 विकसित की है।
- एआरआई पुणे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- बायोफोर्टिफाइड ड्यूरम एमएसीएस 4028 गेहूं की किस्म लगभग 14.7 प्रतिशत की उच्च प्रोटीन सामग्री, बेहतर पोषण गुणवत्ता वाले जस्ता 40.3 पीपीएम, और लोहे की सामग्री क्रमशः 40.3 पीपीएम और 46.1 पीपीएम, अच्छी मिलिंग गुणवत्ता और समग्र स्वीकार्यता दर्शाती है।
- एमएसीएस 4028, एक अर्ध–बौनी किस्म है, जो 102 दिनों में परिपक्व होती है और इसने 19.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की श्रेष्ठ और स्थिर उपज क्षमता दिखाई है।

- यह स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट, फोलियर एफिड्स, रूट एफिड्स और ब्राउन गेहूं माइट के लिए प्रतिरोधी है।
- एमएसीएस 4028 किस्म संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के लिए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) कार्यक्रम में भी शामिल है ताकि कुपोषण को स्थायी तरीके से दूर किया जा सके और राष्ट्रीय पोषण रणनीति विजन 2022 'कुपोषण मुक्त भारत' को बढ़ावा दिया जा सके।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भी वर्ष 2019 के दौरान जैव विविधता श्रेणी के तहत इस किस्म को टैग किया है।
- एमएसीएस 4028 को केंद्रीय उप–समिति द्वारा फसल मानकों पर अधिसूचित किया गया है, महाराष्ट्र और कर्नाटक को शामिल करते हुए प्रायद्वीपीय क्षेत्र की समय पर बुवाई, बारिश की स्थिति के लिए कृषि फसलों (सीवीआरसी) के लिए किस्मों की अधिसूचना जारी की गई है।

कोविड–19 के लिए टेस्ट किट

- पुणे स्थित मायलेब डिस्कवरी सॉल्यूशंस तथा जर्मनी की एल्टन डायग्नोस्टिक्स द्वारा कोविड–19 के लिए विकसित टेस्ट किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) से व्यावसायिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद दोनों कंपनियों को बड़े पैमाने पर किट बनाने की मंजूरी मिली है।
- वर्तमान में, कोविड–19 के लिए लोगों का परीक्षण करने के लिए नैदानिक किट यूएसए से आयात किए जाते हैं।
- इससे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित या यूरोपीय संघ द्वारा प्रमाणित किटों का सार्स सीओवी–2 का पता लगाने के लिए वाणिज्यिक परीक्षण की पेशकश करने की अनुमति दी गई थी।
- हालांकि, आईसीएमआर ने कहा कि इसकी अब आवश्यकता नहीं है और यहां तक कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) द्वारा अनुमोदित भी परीक्षण के लिए पात्र होंगे।
- विकसित किट प्रोटोकॉल वर्तमान में संक्रमण का पता लगाने के लिए लगने वाले सात घंटों की तुलना में ढाई घंटे के भीतर संक्रमण का पता लगाता है।

कपास की सफेद–प्रतिरोधी किस्म

समाचार –

- राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), लखनऊ ने कपास की एक सफेद रंग की प्रतिरोधी किस्म विकसित की है।
- व्हाइटफ्लाइज दुनिया के शीर्ष दस विनाशकारी कीटों में से एक हैं जो 2000 से अधिक पौधों की प्रजातियों को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ 200–पौधों में वायरस के लिए रोगवाहक के रूप में भी कार्य करते हैं।
- कपास, व्हाइटफ्लाइज द्वारा सबसे अधिक नुकसान पहुँचाए जाने वाली फसलों में से एक है। 2015 में पंजाब में कपास की दो–तिहाई फसल को व्हाइटफ्लाइज द्वारा नष्ट कर दिया गया था।

नैनोकॉम्पोसिट कोटिंग्स

समाचार –

- इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यु मटेरियल (एआरसीआई) के वैज्ञानिकों के एक समूह ने नैनोकम्पोसाइट कोटिंग्स के आकार–चयन के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है।
- एआरसीआई विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) का एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।
- नई सामग्री के भौतिक, रासायनिक और भौतिक रासायनिक गुणों में सुधार करने के लिए नैनोस्कॉपल में दो या अधिक विभिन्न सामग्रियों को मिलाकर नैनोकॉम्पोसाइट कोटिंग्स का निर्माण किया जाता है।
- वैज्ञानिकों ने पाया है कि एक स्पंदित इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग करके विशेष आकार के सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) सूक्ष्म कणों के जलसेक के साथ निकल–टंगस्टन आधारित कोटिंग्स संक्षारण प्रतिरोध का एक उत्कृष्ट संयोजन प्रदान कर सकते हैं।

स्टील को जंग लगने से बचाने के लिए कोटिंग

समाचार –

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस), धनबाद और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक दल ने स्टील को जंग से बचाने के लिए एक सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग बनाई है।
- कोटिंग को पॉलीयुरेथेन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनोकणों से बनाया गया था।

वास्प–76बी पर लोहे की बारिश

समाचार –

- वास्प–76 बी, एक एक्सोप्लैनेट (सौर मंडल के बाहर का ग्रह), पर शायद लोहे की बारिश हो रही है।
- वास्प–76 बी अपने मेजबान तारे के इतने करीब है कि उसका दिन का तापमान 2,400 डिग्री सेल्सियस से अधिक है जो लोहे की तरह धातुओं को वाष्पित करने के लिए पर्याप्त गर्म।
- दूसरी ओर, ग्रह की रात्रि 1,000 डिग्री ठंडी है, जिससे उन धातुओं को संघनित किया जा सकता है और बारिश हो सकती है।
- वास्प–76 बी एक विशाल गैस ग्रह है जो बृहस्पति से आकार में दोगुना है। इसका नाम यूके के नेतृत्व वाली वास्प टेलीस्कोप प्रणाली से आया है जिसने 2016 में इसका पता लगाया था।
- यह पृथ्वी से 640 प्रकाश वर्ष दूर है और यह अपने तारे के इतने करीब है कि एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 43 घंटे लगते हैं।
- ग्रह की एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि इसका हमेशा एक ही भाग अपने तारे के सामने होता है – एक ऐसा व्यवहार जिसे वैज्ञानिक 'टाईडली लॉक' कहते हैं। बिल्कुल पृथ्वी के चारो और चंद्रमा के परिभ्रमण की तरह।

दवा–प्रतिरोधी टीबी के उपचार में सफलता के चिन्ह

समाचार –

- हाल ही में, बड़े पैमाने पर दवा प्रतिरोधी टीबी (एक्सडीआर– टीबी) और मल्टीड्रग–प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर–टीबी) के खिलाफ कुछ मौखिक दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए एक छोटा परीक्षण किया गया था।
- परीक्षण ने 90 प्रतिशत की सफलता दर के साथ उत्साहजनक परिणाम दिखाए।
- रोगियों के एचआईवी स्थिति से उदासीन अनुकूल परिणाम सही साबित हुए।
- परीक्षण (निक्स–टीबी) ने एक्सडीआर–टीबी और एमडीआर–टीबी के रोगियों में तीन मौखिक दवाओं जैसे कि बेडैक्लाइन, प्रेटोमिड और लाइनजोलिड का परीक्षण किया।

बल्क ड्रग पार्क

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए, 3,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है।
- इसने अगले 8 वर्षों के लिए 6,940 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से महत्वपूर्ण दवा मध्यवर्ती और सक्रिय दवा घटक (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दी है।
- सरकार प्रति बल्क ड्रग पार्क, 1000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ राज्यों को अनुदान सहायता देगी, जिसमें आम सुविधाएं होंगी जैसे सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट, पावर और स्टीम यूनिट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आदि।
- बल्क ड्रग्स पार्क योजना से देश में थोक दवाओं के विनिर्माण लागत में कमी आने की उम्मीद है।
- यह ऐसी दवाओं के लिए अन्य देशों पर निर्भरता को भी कम करेगा।
- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना से 46,400 करोड़ रुपये की अनुमानित वृध्दि होगी तथा 8 वर्षों में और महत्वपूर्ण अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा।

मछली खाने वाले निएंडरथल

समाचार –

- एक अध्ययन के अनुसार, निएंडरथल 80,000 वर्ष पहले माँस, मछली और अन्य समुद्री जीवों का नियमित रूप से भोजन कर रहे थे, जो यह बताता है कि इस ग्रह पर केवल आधुनिक मनुष्य ही नहीं थे जो समुद्र से भोजन ले रहे थे।
- पत्रिका साइंस में प्रकाशित अध्ययन में पुर्तगाल में फिगुएरा ब्रावा की गुफा में खुदाई के दौरान इसके पहले मजबूत सबूत मिले हैं।

एक भयावह डायनासोर के जीवाश्म का पता चला

समाचार –

- वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिमी न्यू मैक्सिको में एक डरावने पंख वाले डायनासोर के जीवाश्मों का पता लगाया है जो एक त्वरित और चुस्त शिकारी थे।
- डायनोबेलोटोर नोटोहेस्पेरस जो 67 मिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में थे छोटे शिकार करते थे तथा झुंडों में मिलकर बड़े शिकार भी कर सकते थे।

पाई दिवस

समाचार –

- पाई दिवस 14 मार्च को पाई (ग्रीक अक्षर π) को समर्पित कर मनाया जाता है। इस विचार की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, जहाँ के प्रारूप में 14 मार्च को 3/14 के रूप में लिखा जाता है। ये तीन अंक 3.14 पर दो दशमलव स्थानों तक पाई के मूल्य से मेल खाते हैं।
- परिभाषा के अनुसार, π एक वृत्त के परिधि से उसके व्यास का अनुपात है। पाई वृत्त के क्षेत्र को उसके त्रिज्या के वर्ग से विभाजित करके भी पाया जाता है। अनुपात हमेशा स्थिर होता है।
- पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे एक प्रतीक π दर्शाया जाता है।
- पाई का उपयोग ज्यामिति, त्रिकोणमिति, भौतिकी, खगोल विज्ञान और अन्य विज्ञानों में है।

क्वांटम सिक्के और कंप्यूटर के साथ क्वांटम सेंसिंग के लिए नया टेस्ट

समाचार –

- रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान) के शोधकर्ताओं ने क्वांटम सिक्के या क्यूबिट की निष्पक्षता के लिए इनटेंगलमेंट सिद्धांत का उपयोग करके एक नया परीक्षण तैयार किया है।
- परीक्षण क्वांटम सिक्के की निष्पक्षता का परीक्षण करने के लिए इनटेंगलमेंट का उपयोग करता है। उनकी रणनीति क्वांटम अवस्थाओं के बीच बेहतर भेदभाव को सक्षम बनाती है। क्वांटम सेंसर में इस तरह के लाभ मूल्यवान है।
- यह क्वांटम अवस्था भेदभाव और क्वांटम सूचना विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिससे क्वांटम संवेदन के प्रभावित होने की उम्मीद है।

पासपोर्ट की नकली छपाई और मुद्रा नोटों की जालसाजी पर अंकुश लगाने के लिए स्याही

समाचार –

- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)–नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने एक द्वि–ल्यूमिनसेंट सुरक्षा स्याही विकसित की है जो दो अलग–अलग उत्तेजना स्रोतों द्वारा प्रकाशित होने पर लाल और हरे रंगों में चमकती है।
- स्याही को बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), नई दिल्ली की इकाई को दिया गया था।
- फॉर्मूलेशन का उपयोग पासपोर्ट की प्रामाणिकता, सरकारी दस्तावेजों, छेड़छाड़ स्पष्ट लेबल, पहचान पत्र आदि की जांच के लिए किया जा सकता है।

भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम

समाचार –

- अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) ने बताया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने NavIC मैसेजिंग सिस्टम और एक NavIC रिसीवर विकसित किया है तथा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम (INCOIS) इस मैसेजिंग सिस्टम का उपयोग आपातकालीन चेतावनी संदेशों जैसे चक्रवात, सुनामी और उच्च लहरों की जानकारी के प्रसारण के लिए कर रहा है। इसका प्रसारण मत्स्य पालन क्षेत्र में मछुआरों को इन प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देने के लिए भी किया जाता है।
- अंतरिक्ष विभाग ने बताया है कि इसरो ने रिसीवरों के निर्माण के लिए इस तकनीक को भारत के पांच उद्योगों में स्थानांतरित कर दिया है। विभिन्न तटीय राज्यों के मत्स्य विभाग को मछुआरा समुदाय के लिए इस तकनीक से अवगत कराया गया है।
- इसरो ने मछुआरों के उपयोग के लिए केरल और तमिलनाडु के राज्य मत्स्य विभाग को लगभग 250 इकाइयां वितरित की हैं। इसरो ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मछुआरों के लिए भी लगातार परीक्षण किए हैं। NavIC का वितरण संबंधित राज्य सरकारों के मत्स्य विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

हानिकारक रसायनों के बिना सैनिटाइजर

समाचार –

- हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित CSIR - Institute of Himalayan Bioresource Technology (CSIR-IHBT) के वैज्ञानिकों ने कोरोनोवायरस के डर के कारण ऐसे उत्पादों की बढ़ती मांग के बाद बाजार में नकली सैनिटाइटर्स के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए एक नए प्रकार के सेनेटाईज़र को विकसित किया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के दिशा–निर्देशों के अनुसार इस सेनेटाईज़र को बनाने के लिए प्राकृतिक फ्लेवर, सक्रिय चाय के घटक और अल्कोहल की मात्रा का उपयोग किया गया है। एक खास बात यह है कि इस उत्पाद में पैराबेंस, ट्राइक्लोसन, सिंथेटिक खुशबू और फाल्लेट्स जैसे रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

सूक्ष्मजीवों से जैव ईंधन

समाचार –

- इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (ICGEB) के शोधकर्ता एक सूक्ष्मजीव की वृद्धि दर और शर्करा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक विधि विकसित कर रहे हैं जिसे Synechococcus sp PCC 7002 कहा जाता है।
- इससे जैव ईंधन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। जैव ईंधन उत्पादन सहित अधिकांश जैव–प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाएं, कम लागत और शर्करा की सतत आपूर्ति और एक नाइट्रोजन स्रोत की उपलब्धता पर निर्भर हैं। शर्करा आमतौर पर पौधों से आती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
- कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि सायनोबैक्टीरिया (नीला–हरा शैवाल), भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक करके शर्करा का उत्पादन कर सकते हैं। सायनोबैक्टीरिया से शर्करा की उपज संभावित रूप से भूमि आधारित फसलों की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है। इसके अलावा, पौधे–आधारित शर्करा के विपरीत, साइनोबैक्टीरियल बायोमास प्रोटीन के रूप में एक नाइट्रोजन स्रोत प्रदान करता है।
- सायनोबैक्टीरिया ताजा और समुद्री पानी दोनों में पाए जाते हैं। समुद्री साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करना बेहतर हो सकता है क्योंकि मीठे पानी में तेजी से कमी हो रही है।
- ICGEB की एक टीम ने सफलतापूर्वक एक सियानकोबैक्टीरियम नामक सिन्थोकोकस एसपी का निर्माण किया है। पीसीसी 7002 जिसने एक उच्च विकास दर और शर्करा (ग्लाइकोजन) सामग्री को दिखाया है को जब हवा में उगाया जाता है, तो उसका विकास दोगुना हो गया और कोशिकाओं के ग्लाइकोजन सामग्री में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- Synechococcus sp. PCC 7002 एक मॉडल समुद्री सायनोबैक्टीरियम है।

कम लागत वाली फ्लो–डायवर्टर स्टेंट विकसित हुई

समाचार –

- श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST) की शोध टीम ने एक अभिनव विकास किया है।
- मस्तिष्क के रक्त वाहिकाओं के एन्यूरिज्म के उपचार के लिए इंट्राक्रैनील फ्लो डायवर्टर भेजा जाता है।
- इंट्राक्रैनील एन्यूरिज्म या मस्तिष्क धमनीविस्फार एक स्थानीयकृत गुब्बारा है, रक्त वाहिकाओं की दीवार की आंतरिक मांसपेशियों के उत्तोरत्तर कमजोर पड़ने के कारण मस्तिष्क में धमनियों का उभार या फैलाव होता है।
- एन्यूरिज्म के सहज फटने से मस्तिष्क के चारों ओर जगह में रक्तस्राव हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप एक सबराचेनॉइड हेमरेज (SAH) हो जाता है। SAH से लकवा, कोमा या मृत्यु हो सकती है।
- चित्रा प्रवाह डायवर्टर को उपकरण के प्रवास के जोखिम को कम करने के लिए जटिल आकृतियों की धमनियों की दीवारों पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

कोलकाता में आईकनसेट 2020

समाचार –

- नैनो मिशन एवं नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICONSAT) 2020 का आयोजन 5–7 मार्च 2020 के दौरान कोलकाता में नैनो मिशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तत्वावधान में किया गया था।
- ICONSAT द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला है जो भौतिक, रासायनिक, सामग्रियों के साथ–साथ जीव विज्ञान के क्षेत्र में नैनो विज्ञान की मदद से अत्याधुनिक विकास लाने का इरादा रखती है।

- इस कार्यक्रम में 5 एम – मशीन, मटेरियल, मैन्यूफेक्चरिंग तथा मैनपावर तथा नैनो–विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ इन 5 एम के एकीकरण पर जोर दिया गया।
- इसका उद्देश्य नैनो टेक्नोलॉजी को सतत विकास और नई तकनीक (मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि) के साथ एकीकृत करना है।
- इसने नैनो–विज्ञान में विशेषज्ञों का एक नेटवर्क बनाने और ऊर्जा, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य इत्यादि जैसे क्षेत्रों में ज्ञान का सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- इसका उद्देश्य देश और विदेश के युवा शोधकर्ताओं और छात्रों के मध्य नवीनतम नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में विकास के साथ तालमेल रखने के लिए एक संभावित मंच प्रदान करना है।

चाय के पौधों में उर्वरकां और कवकनाशी की जगह ले सकने वाले कीटाणु

समाचार –

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएएसएसटी) गुवाहाटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी के शोधकर्ताओं ने चाय के पौधे और संबंधित पीढ़ी से जुड़े एंडोफाइटिकिनो बैक्टीरिया की महत्वपूर्ण पादप–वृद्धि–संवर्धन और ऐंटिफंगल गतिविधियों को पाया है। एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया का अनुप्रयोग चाय बागान में रासायनिक आदानों को कम कर सकता है।
- आईएएसटी ने विभिन्न वातावरणों में पाए जाने वाले 46 एंडोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया (मुख्य रूप से मुक्त रहने वाले सूक्ष्मजीव), जो चाय के पौधों से जुड़े स्पष्ट रोग पैदा करने और आणविक तकनीकों के माध्यम से विशेषता के बिना अपने जीवन चक्र के कम से कम हिस्से के लिए एक पौधे के भीतर रहता है, को अलग कर दिया। अलग किए गए 46 कीटाणुओं में से, 21 कीटाणुओं ने कम से कम एक टेस्ट फंगल फाइटोपथोजेंस के विकास को बाधित किया और स्ट्रेन SA25 और SA29 ने व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीफंगल गतिविधि का प्रदर्शन किया।
- चाय (कैमेलिया साइनेंसिस) भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि उत्पादित चाय का एक बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाता है। हालांकि, हाल के वर्षों में, आयात करने वाले देशों द्वारा रासायनिक अवशेष मुक्त चाय की अधिक मांग के कारण चाय के निर्यात में गिरावट आई है। वर्तमान अध्ययन में चाय उद्योग में रासायनिक आदानों के उपयोग को कम करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संयंत्र लाभकारी विशेषताओं वाले एन्डोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया के उपयोग का प्रयास किया गया है।

आपदा प्रबंधन के लिए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी

समाचार –

- पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल (एआरसीआई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान में वैज्ञानिक, हैदराबाद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त आर एंड डी सेंटर ने पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल (पीईएमएफसी) विकसित किया है।
- पीईएमएफसी, अपनी संपूर्णता में, विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन प्रणालियों में अनुप्रयोगों के साथ कम तापमान पर परिचालन क्षमता का लाभ उठाता है।
- एआरसीआई अब तमिलनाडु राज्य इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (टीएन एसईओसी) में 10 किलोवॉट क्षमता का प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, वीएचएफ सेट, आईपी फोन, बीएसएनएल ईथरनेट और कार्यालय उपकरण जैसे स्केनर, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोन, फेक्स और सामान्य उपकरण जैसे कि लाईट और पंखे स्थापित करने की योजना बना रहा है।

माइक्रोआरएनए पौधों में बने होते हैं

समाचार –

- नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, बेंगलुरु और सस्तरा विश्वविद्यालय, तंजावुर के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि पौधों में माइक्रोआइन नामक छोटे अणु कैसे बनाए जाते हैं।
- यह खोज पौधों में प्रक्रियाओं के अध्ययन को बहुत आसान बनाती है। माइक्रोआरएनए छोटे अणु होते हैं, लगभग 21 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं, तथा कोशिका में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। शोध को न्यूक्लिक एसिड रिसर्च जर्नल में प्रकाशित किया गया था।
- पौधों के विकास और विकास के सभी पहलु चाहे वह फूल बनने की शुरूआत हो या हार्मोन के वितरण या नियंत्रण हो, सेल में विभिन्न स्तरों पर विनियमित होते हैं। इस तरह के विनियमन की हमेशा प्रोटीन जो कोशिका के कार्य करने के घोड़े होते हैं द्वारा मध्यता की जाती है।

- एक स्तर पर, प्रक्रियाओं का विनियमन कोशिकाओं में होने वाले विशिष्ट प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित करने के बारे में है। इसे माइक्रोआरएनए द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- विशिष्ट कोशिकाओं में एक विशेष प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए, माइक्रोआरएनए मैसेंजर आरएनए अणुओं को नष्ट करते हैं जो कोशिका में उस विशिष्ट प्रोटीन के उत्पादन में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को मैसेंजर आरएनए की सिलिंग कहा जाता है। माइक्रोआरएनए जो साईलेसिंग को प्राप्त कर लेते हैं विकासवादी रूप से संरक्षित है – अर्थात, वे सभी फूलों के पौधों में पाए जाते हैं, चाहे वे काई या गुलाब हों।
- इसी तरह, डीएनए में जीन के प्रभाव का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका जीन को 'साईलेंस'या 'नॉकआउट' करना होता है। एक जीन को नॉक करने का मतलब पूरे जीन को हटाना नहीं है। प्रक्रियाओं को खटखटाने में, वे आरएनए जो जीन को प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं, नष्ट हो जाते हैं या उनका स्तर पहले से वर्णित माइक्रोआरएनए द्वारा कम कर दिया जाता है।

रेज़(आरएआईएसई) 2020

समाचार –

- भारत सरकार (भारत सरकार) ने नई दिल्ली में 11 से 12 अप्रैल 2020 तक आयोजित होने वाले मेगा इवेंट, रेज 2020 – 'रिसपोंसिबल एआई फॉर सोशल एंपावरमेंट 2020' की घोषणा की। यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन है जिसे सरकार ने उद्योग और शिक्षा जगत के साथ साझेदारी में आयोजित किया है।
- शिखर सम्मेलन प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में स्मार्ट मोबिलिटी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा स्मार्ट मोबिलीटी में सामाजिक सशक्तिकरण, समावेश और परिवर्तन के लिए एआई का उपयोग करने के लिए पाठ्यक्रम बनाने के लिए विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए आयोजित की गई थी।
- सत्र के दौरान, सरकार ने एआई–स्टार्टअप चैलेंज और इवेंट वेबसाइट को भारत में एआई के प्रसार को बढ़ाने के एक भाग के रूप में शुरू किया।
- रेज़ 2020 अपनी तरह का पहला आयोजन है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत की दृष्टि और जिम्मेदार एआई के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण, समावेश और परिवर्तन के लिए रोडमैप तैयार करने की वैश्विक बैठक है।
- यह आयोजन एक स्टार्टअप चैलेंज पिचफेस्ट के साथ शुरू हुआ तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भारत सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद वैश्विक उद्योग के नेताओं, प्रमुख राय निर्माताओं, सरकार के प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों की मजबूत भागीदारी का गवाह बना।

2020 सीडी 3

समाचार –

- खगोलविदों पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक छोटे पिंड को देखा है, जिसे उन्होंने 'मिनी–मून' या ग्रह के 'दूसरे चंद्रमा' के रूप में करार दिया है।
- 2020 सीडी 3 के नाम से पहचाने जाने वाले, मिनी–मून की खोज 15 फरवरी की रात को एरिजोना में नासा द्वारा वित्त पोषित कैटालिना स्काई सर्वे (सीएसएस) के केकेपर विर्जचोस और टेडी प्रुएन द्वारा की गई थी।
- यह वास्तव में एक कार के आकार का क्षुद्रग्रह है जिसका व्यास लगभग 1.9–3.5 मीटर है।
- कक्षा एकीकरण यह दर्शाता है कि यह वस्तु अस्थायी रूप से पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। यानी हमारे स्थायी चंद्रमा के विपरीत, मिनी–चंद्रमा अस्थायी है। यह अंततः पृथ्वी की कक्षा से मुक्त हो जाएगा और अपने रास्ते पर चला जाएगा।

जीन संपादन उपकरण क्रिस

समाचार –

- वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जीन एडिटिंग टूल क्रिस्प–कास 9 का उपयोग किया है, जो रोगों के इलाज के लिए डीएनए पर काम करने के प्रयासों में एक नया विकास है।
- चिकित्सको ने पहली बार 2017 में जिंक फिंगर के रूप में पहचाने जाने वाले उपकरण का उपयोग करके एक अलग विरासत में मिली बीमारी के लिए शरीर में जीन संपादन का प्रयास किया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशिष्ट स्थान पर डीएनए का पता लगाने और काटने के लिए क्रिस्पर एक बेहतर उपकरण है, और नए शोध में रुचि बहुत अधिक है।
- जीन संपादन से सबसे बड़े संभावित जोखिमों में से एक यह है कि क्रिस्प अन्य जीनों में अनपेक्षित परिवर्तन कर सकता है, लेकिन पियर्स ने कहा कि कंपनियों ने इसे कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वही कट हो जहाँ उपचार की आवश्यकता है, बहुत कुछ किया है।

आंतरिक सुरक्षा

लाइट मशीन गन्स (एलएमजी)

समाचार –

- रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने लाइट मशीन गन्स (एलएमजी) की खरीद के लिए इजरायल वेपन इंडस्ट्रीज (आईडब्ल्युआई) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- एलएमजी को पैदल सेना के हथियार के रूप में, एक सहायक के साथ या उसके बिना एक व्यक्तिगत सैनिक द्वारा नियोजित किया जा सकता है।
- इसे अक्सर स्क्वाड स्वचालित हथियार कहा जाता है।

ड्राफ्ट रक्षा खरीद (डीपीपी) प्रक्रिया 2020 जारी की गई

समाचार –

- रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने पहली बार अपने 20 मार्च 2020 को जारी ड्राफ्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर (डीपीपी) 2020 में रक्षा आवश्यकता को पट्टे पर देने की शुरुआत एक नई श्रेणी के रूप में की है।
- यह 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी और डीपीपी 2016 को सुपरसीड करेगी।
- यह डीपीपी 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।
- अन्य प्रस्तावित उपायों में शामिल हैं – पूंजी अधिग्रहण अनुबंध के तहत बिक्री पश्चात् सेवा, स्थानीय सामग्री के लिए अधिग्रहण और प्रोत्साहन में उच्च स्वदेशी सामग्री और सॉफ्टसेट और ऑफसेट के तहत उत्पाद निर्यात पर जोर।
- मसौदे को महानिदेशक (अधिग्रहण) की अध्यक्षता वाली समिति ने अंतिम रूप दिया था, जिसे अगस्त 2019 में स्थापित किया गया था।
- लीजिंग को मौजूदा 'खरीदें' और 'बनाए' श्रेणियों के अलावा 'अधिग्रहण' नामक एक नई श्रेणी के साथ पेश किया गया है, जो समय–समय पर किराये के भुगतान के साथ विशाल प्रारंभिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाता है।
- मसौदे में प्रस्तावित विभिन्न श्रेणियों में खरीद के विभिन्न श्रेणियों में समर्थन के लिए लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्वदेशी सामग्री बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- 'मेक इन इंडिया' और पहली बार स्वदेशी सामग्री के सत्यापन के लिए एक सरल और यथार्थवादी पद्धति को शामिल किया गया था।
- इसमें 'देश में स्थापित एफएओ निर्माण इकाइयों से चिप्स तथा एयरो इंजन निर्माण इकाई से एकल विक्रेता आधार पर खरीद का आश्वासन शामिल था।'
- लंबे समय से रक्षा सौदों को देखते हुए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए तेजी से अप्रचलन के कारण सॉफ्टवेयर और सिस्टम से संबंधित परियोजनाओं की खरीद के लिए नए अध्याय पेश किए गए हैं।
- शुरू की गई एक और नई श्रेणी है 'खरीदें' (भारत में वैश्विक निर्माण) कुल अनुबंध मूल्य की लागत के आधार पर न्यूनतम 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ।

अभ्यास मिलन 2020

समाचार –

- भारतीय नौसेना ने कोरोनावायरस के निरंतर प्रसार के कारण अपने बहु–राष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास मिलन को स्थगित कर दिया है।
- मिलन (11 वां संस्करण) 18 से 28 मार्च 2020 तक विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाला था।

अभ्यास मिलन

- यह एक द्विवार्षिक, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो 1995 में शुरू हुआ था।
- नौसेना ने मिलान के 10 संस्करणों का आयोजन किया है 'सिनर्जी अक्रॉस द सी' के विषय के साथ अभ्यास, विदेशी नौसेनाओं के बीच पेशेवर बातचीत को बढ़ाने और 1995 से एक दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यास सीखने के लिए किया जाता रहा है।
- यह 2018 तक अंडमान और निकोबार कमान में आयोजित किया गया था।
- अब यह पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है।
- 2020 में 40 से अधिक देशों को अभ्यास में भाग लेने की उम्मीद थी।

प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020

समाचार –

- 'PRAGYAN सम्मेलन 2020', 4 मार्च 2020, नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज (CLAWS) द्वारा दो दिवसीय भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।
- यह आयोजन एक क्रॉस–डोमेन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को हपदह लैंड वारफेयर की बदलती विशेषताओं और सैन्य पर इसके प्रभाव 'के जटिल विषय पर विचार–विमर्श करने के लिए लाया गया था।
- संगोष्ठी ने उभरते विचारों, दृष्टिकोणों और आख्यानों पर विचार–विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया जो ।हम नव युग को परिभाषित करते हैं।
- वारफेयर 'जो कि अपने चरित्र में बदलाव के साथ–साथ नए' पदह साधनों के उपयोग के साथ युद्धपोत 'को' समाप्त करने के लिए बढ़ा रहा है।

83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान

समाचार –

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने भारतीय वायु सेना के लिए 83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भविष्य में भारतीय वायु सेना की रीढ़ बनने जा रहा है।
- जबकि 40 तेजस विमानों के आदेशों को प्रारंभिक विन्यास में एचएएल के साथ रखा गया था, डीएसी ने हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमीटेड (एचएएल) से विमान के अधिक उन्नत संस्करण के एक और 83 की खरीद का मार्ग प्रशस्त किया।
- यह खरीद मेक इन इंडिया के लिए एक प्रमुख बढ़ावा होगी क्योंकि विमान स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण के लिए लगभग 1,300 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

विस्फोटक पता लगाने का नया यंत्र

समाचार –

- विस्फोटक पता लगाने की राष्ट्रीय कार्यशाला (NWED–2020), पुणे में में विस्फोटक पता लगाने के एक नए यंत्र जिसका नाम राइडर–एक्स है का अनावरण किया गया।
- राइडर–एक्स में एक निश्चित दूरी से विस्फोटक का पता लगाने की क्षमता है।
- शुद्ध रूप तथा साथ ही दूषित पदार्थों के साथ कई विस्फोटकों का पता लगाने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए इसके सिस्टम में डेटा लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जा सकता है।
- यंत्र द्वारा छिपाकर रखे गए थोक विस्फोटक का पता भी लगाया जा सकता है। रायडर–एक्स को उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल) पुणे एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर द्वारा सह–विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस

समाचार –

- राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है।
- यह उस दिन को चिह्नित करता है जब 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) की स्थापना की गई थी।
- एनएससी एक तीन–स्तरीय संगठन है जो रणनीतिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों की देखरेख करता है। इसमें सामरिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) और संयुक्त खुफिया समिति का एक सचिवालय शामिल है।
- एनएसएबी के सदस्य आम तौर पर वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, नागरिक और साथ ही सैन्य, शिक्षाविद और नागरिक समाज के विशिष्ट सदस्य होते हैं जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, विदेशी मामलों, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आर्थिक मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं।
- NSC भारत के प्रधान मंत्री के कार्यकारी कार्यालय के भीतर काम करता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएससी की अध्यक्षता करते हैं।

भूगोल एवं पर्यावरण

दिल्ली में कुड़ा फैंकने के स्थान का प्रभाव

समाचार –

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली में कचरा फैंकने के स्थानों (विरासत अपशिष्ट) के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान की मात्रा का आकलन करने के लिए एक समिति का निर्देश दिया है।

- समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) और IIT दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- विरासत अपशिष्ट वे अपशिष्ट हैं जिन्हें कुछ बंजर भूमि या लैंडफिल (ठोस कचरे को फैंकने का एक क्षेत्र) के लिए समर्पित जगह पर वर्षों एकत्र रखा जाता है।
- विरासत प्रदूषण के प्रभावी निपटान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा बायोमिनिंग विधि प्रस्तावित की गई है।

सिक्किम में पिघलते ग्लेशियर

समाचार –

- देहरादून के वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) के वैज्ञानिकों ने पाया है कि सिक्किम में ग्लेशियर अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर पिघल रहे हैं।
- टोटल एनवायरमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन ने 1991–2015 की अवधि के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए सिक्किम के 23 ग्लेशियरों की प्रतिक्रिया का आकलन किया।
- इस अध्ययन ने कई ग्लेशियर मापदंडों, जैसे लंबाई, क्षेत्र, मलबे के आवरण, स्नोलाइन एल्टिट्यूड (SLA), ग्लेशियल झीलों, वेग, और डाऊनवेस्टिंग का अध्ययन किया।
- सिक्किम के ग्लेशियरों का अब तक खराब अध्ययन किया गया है, और क्षेत्र–आधारित द्रव्यमान संतुलन माप एक छोटी अवधि (1980–1987) के लिए केवल एक ग्लेशियर (चांगमेखंगपु) तक सीमित है।
- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG), देहरादून विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत हिमालय के भूविज्ञान के अध्ययन के लिए एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।

विश्व जल दिवस

समाचार –

- हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यह मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है।
- विश्व जल दिवस को मनाने की शुरूआत 1993 से हुई और इसके मनाने का उद्धेश्य सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- 2020 का विषय 'जल और जलवायु परिवर्तन' है जिसका उद्देश्य 'जल और जलवायु परिवर्तन' के बीच अंतर्संबंध का पता लगाना है।
- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 के तहत, विश्व जल दिवस का मुख्य फोकस – 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धि को प्राप्त करने में मदद करना है।
- इसके अलावा, सतत विकास के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक (2018–2028) मनाया जा रहा है।
- ये अवलोकन इस बात की पुष्टि करते हैं कि पानी और स्वच्छता के उपाय गरीबी में कमी, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विश्व गौरैया दिवस

समाचार –

- हर वर्ष 20 मार्च को इस पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'विश्व गौरैया दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- यह दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था।
- इस पहल की शुरुआत भारत के 'नेचर फॉरएवर सोसाइटी (एनएफएस)' द्वारा की गई थी।
- भारत में, गौरैया देश भर में, असम घाटी और असम पहाड़ियों के निचले हिस्सों तक पाई जाती है। पूर्वी हिमालय की ओर, प्रजाति को यूरेशियन ट्री गौरैया पाई जाती है।

गौरैया

- वैज्ञानिक नाम– पेसर डोमिस्टिकस
- संरक्षण की स्थिति– प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की रेड लिस्ट पर लिस्ट कर्न्सन्ड।
- अंटार्कटिका, चीन और जापान को छोड़कर, गौरेया विश्व के सभी महाद्विपों में पाई जाती है। यह यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका की मूल निवासी है।
- यह बिहार और दिल्ली राज्य का राज्य–पक्षी है।

CHAHAL ACADEMY

ग्रीन कंपनी (ग्रीनको) रेटिंग सिस्टम

समाचार –

- इसे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा विकसित किया गया है।
- सिस्टम 10 व्यापक पर्यावरणीय मापदंडों पर कंपनियों का मूल्यांकन करता है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) की कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग आदि शामिल हैं।
- तदनुसार, रेटिंग प्रदान की जाती हैं जो तीन वर्ष तक वैध रहती हैं।
- यह 'दुनिया में अपनी तरह का पहला' ढांचा है जो जीवन चक्र दृष्टिकोण का उपयोग करके कंपनी की गतिविधियों का पर्यावरण मित्रता के आधार पर मूल्यांकन करता है।
- जीवन चक्र दृष्टिकोण उत्पाद के डिजाइन, प्रयुक्त सामग्री, खरीद, विक्रेता प्रबंधन, रसद, पैकेजिंग, निर्माण, वितरण, उत्पाद उपयोग, निपटान और पुर्नचक्रण पर विचार करता है।
- इसका मिशन भारतीय उद्योग को उनके पर्यावरण प्रदर्शन में पर्याप्त सुधार करने की सुविधा प्रदान करना है, जिससे प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों की बचत होती है।
- इसे, 2015 में, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (युएनएफसीसी) द्वारा, भारत के इंटेंडेड नेशनल डिटरमाईड कंट्रीब्युशन (आईएनडीसी) के जलवायु परिवर्तन से निपटने के भारतीय उद्योग/निजी क्षेत्र की एक सक्रिय स्वैच्छिक कार्रवाई से निपटने के दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है।

लंबे पूंछ वाले मैकाक्स, समृद्ध उपकरणों के उपयोग के व्यवहार को प्रर्दशित करते हैं

समाचार –

- ग्रेटर निकोबार द्वीप में लंबे समय से पूंछ वाले मैकाक्स (मकाका फासिस्टिकिस उंब्रोसस), गैर–मानव प्राइमेट, वस्तुओं को संभालते हैं और अपने प्रयासों को सरल बनाने के लिए उपकरणों का उपयोग करते हैं।
- यह अध्ययन आईआईएसईआर मोहाली से प्रकाशित किया गया है।
- शोधकर्ताओं ने वस्तुओं के हेरफेर से संबंधित दिलचस्प व्यवहार और छह व्यवहार–संबंधी संदर्भों में उपकरण उपयोग को देखा जिसमें 8 विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल थीं।
- उन्होंने यह भी देखा कि मादाओं की तुलना में नर अधिक बार उपकरण के उपयोग में शामिल थे।
- वे अलग–अलग विशेषताओं वाले मनुष्यों की तरह हैं, उदाहरण के लिए, चेहरे के विभिन्न स्थानों में काले या सफेद धब्बे की उपस्थिति, शरीर का आकार, लिंग और व्यवहार।
- हालांकि लंबे पूंछ वाले मैकाक्स चिंपांजी या वानरों की तुलना में मनुष्यों से संबंधित हैं, लेकिन यह अध्ययन उपकरण उपयोग व्यवहार के विकासवादी उत्पत्ति पर एक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता है।

ओलिव रिडले टर्टल्स ने घोंसला बनाना शुरू किया

समाचार –

- ओडिशा के रूशिकुल्या रॉकरी तट पर ओलिव रिडले टर्टल्स का बड़े पैमाने पर घोंसला बनाना शुरू हुआ।
- लगभग 2000 कछुए अपने अंडे देने के लिए रेत में घोंसले खोदते हैं। प्रत्येक घोंसले में औसतन लगभग 100 अंडे होते हैं।
- आमतौर पर ये कछुए अंधेरे में घोंसला बनाते हैं, लेकिन अतीत में ऐसे उदाहरण भी हैं जब उन्होंने दिन में ऐसा किया हो।

ओलिव रिडले

- ओलिव रिडले कछुए दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर हैं।
- ये कछुए मांसाहारी होते हैं और अपने जैतून के रंग के कवच से अपना नाम प्राप्त करते हैं।
- वे प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं।
- वे एक वर्ष के दौरान भोजन और संभोग के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।
- वे अत्यधिक मात्रा में बनाए जाने वाले अपने अद्वितीय घोंसलों, जिन्हें अरीबदा कहा जाता है, तथा जहाँ अंडे देने के लिए हजारों मादाएँ एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं।
- प्रजातियों को IUCN रेड सूची में 'वल्नरेबल' के रूप में पहचाना जाता है, उन्हें CITES परिशिष्ट I के तहत संरक्षित किया जाता है। वे भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची – I में सूचीबद्ध हैं।
- भारत में आकस्मिक हत्या को कम करने के लिए, उड़ीसा सरकार ने ट्रैवेल्स के लिए टर्टल एक्सकलर डिवाइसेस (TED) का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है यह एक विशेष निकास कवर के साथ बनाया गया जाल होता है जो से कछुओं को बच निकलने देता है।

रेड पांडा का अवैध व्यापार

समाचार –

- व्यापार निगरानी नेटवर्क TRAFFIC ने हाल ही में 'भारत में रेड पांडा और चयनित पड़ोसी देशों में उसके अवैध व्यापार से संबंधित खतरों का आकलन' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
- रिपोर्ट में जुलाई 2010 से जून 2019 तक दस वर्ष की अवधि के लिए अवैध शिकार और प्रजातियों के अवैध व्यापार का विश्लेषण किया गया है।
- पूर्वी और उत्तर–पूर्वी हिमालयी उप–जल शंकुधारी जंगलों और पूर्वी हिमालय के विस्तृत जंगल के लिए लाल पांडा का अस्तित्व महत्वपूर्ण है।
- पालतू व्यापार के लिए अवैध कब्जे के अलावा, मांस और फर के लिए जानवर का शिकार किया गया है।
- पूरे नेपाल, भूटान, भारत, चीन और म्यांमार में लगभग 14,500 जानवरों को जंगल में छोड़ दिया जाता है।
- रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि लाल पांडा मांस और संबंधित उत्पादों की पारंपरिक मांग समय के साथ कम हो गई है।
- साथ ही, लाल पांडा के अवैध शिकार और अवैध व्यापार में कमी प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता अभियानों की सफलता का संकेत है।

दांतेदार पेट्रोसॉर

समाचार –

- वैज्ञानिकों ने दांतेदार पेट्रोसॉर – 100 मिलियन वर्ष पहले सहारा में रहने वाले सरीसृप, की तीन नई प्रजातियों की खोज की है।
- ये अफ्रीका के एक प्राचीन नदी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा थे जो मछली, मगरमच्छ, कछुए और कई शिकारी डायनासोरों सहित जीवन से भरा हुआ था।

सुखना झील

समाचार –

- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुखना झील (चंडीगढ़) को हाल ही में एक जीवित इकाई घोषित किया है।
- अदालत ने झील को कानूनी इकाई के रूप में घोषित करने, संरक्षण, तथा संरक्षण के विभिन्न अधिकारों के लिए 'पेरेंस पेट्रेई' क्षेत्र के रूप में घोषित किया है।
- केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी नागरिकों को इस झील को विलुप्त होने से बचाने के लिए लोको पेरेंटिस (माता–पिता की जगह) घोषित किया गया है।
- सुखना झील एक वर्षा आधारित झील है, जो चंडीगढ़ के भीतर स्थित है और इसका जलग्रहण क्षेत्र पंजाब और हरियाणा दोनों में पड़ता है।
- झील का निर्माण 1958 में किया गया था और यह 3 वर्ग किमी में फैली हुई है।
- चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा झील के चारों ओर 2 किमी से 2.75 किमी के क्षेत्र को पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।
- इस क्षेत्र की सभी गतिविधियाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं।
- न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ–साथ सुखना वेटलैंड और सुखना वन्यजीव अभयारण्य में पड़ने वाले जलग्रहण क्षेत्रों में नए निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
- इससे पहले, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यमुना और गंगा नदियों को एक जीवित व्यक्ति के सभी अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों का आनंद लेते हुए कानूनी या न्यायिक व्यक्ति घोषित किया है।
- एचसी पीठ 2014 में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई कर रही थी और कहा कि गंगा और यमुना से जीवित संस्थाओं के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

विश्व वन्यजीव दिवस

समाचार –

- विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन 1973 में जंगली जीवों और वनस्पतियों (CITES) के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- संयुक्त राष्ट्र ने सीआईटीईएस सचिवालय इस विशेष दिन को पूरे विश्व मे मनाने के लिए सहायक क तौर पर घोषित किया है।
- वर्ष 2020 में विषय–'सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ', के तहत जैव विविधता के विकास के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों 1, 12, 14 और 15 के साथ संरेखित करता है, और गरीबी को कम करने, संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए जमीन और पानी के नीचे दोनो ही जल के संरक्षण पर उनकी व्यापक प्रतिबद्धताएं हैं।

- इसके लक्ष्य निम्न प्रकार है
  1. लक्ष्य 1– गरीबी उन्मूलन
  2. लक्ष्य 12 – जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन
  3. लक्ष्य 14 – पानी के नीचे जीवन
  4. लक्ष्य 15 – जमीन पर जीवन
- हमारा ग्रह वर्तमान में तत्काल चुनौती का सामना कर रहा है जो जैव विविधता का नुकसान है और आने वाले दशकों में अगर मानव गतिविधि, जलवायु परिवर्तन और निवास स्थान की गिरावट को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो एक लाख प्रजातियों तक गायब हो सकती है।
- एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये प्रजातियां आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल वीडियो में ही रहें।

मछली पकड़ने वाली बिल्ली तथा ऊदबिलाव

समाचार –

- हाल ही में, चिलिका झील में मछली पकड़ने वाली बिल्ली की एक व्यवहार्य प्रजनन आबादी की उपस्थिति पाई गई है।
- इसके अलावा, एक चिकने–लेपित ऊदबिलाव और एक यूरेशियन ऊदबिलाव की उपस्थिति भी झील में दर्ज की गई है।

	मछली पकड़ने वाली बिल्ली	चिकने–लेपित ऊदबिलाव	यूरेशियन ऊदबिलाव
वैज्ञानिक नाम	पिरोनालिरस विवेरिनस	ल्युट्रोगेल पेरस्पीसीलाटा	लुत्रा लुत्रा
रहवास	सुंदरवन के मैंग्रोव जंगलों में, हिमालय के तलहटी ईलाकों तथा गंगा एवं ब्रहम्मापुत्र की नदी घाटियों में	हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तथा पश्चिम घाटो में, लगभग संपूर्ण भारत में	संपूर्ण यूरोप एवं एशिया में पश्चिम में आयरलैंड से लेकर पूर्व में रूस एवं चीन तक। वे उत्तरी अफ्रीका (मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया) तथा मध्य–पूर्व (इज़राईल, जॉर्डन, ईरान एवं इराक में भी पाए जाते हैं।
आईयूसीएन रेड लिस्ट	वल्नरेबल	वल्नरेबल	नियर थ्रेटन्ड
सीआईटीईएस	एपेंडिक्स II	एपेंडिक्स II	एपेंडिक्स I
इंडियन वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972	शेड्यूल I	शेड्यूल II	शेड्यूल II

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गणराज्य और बेल्जियम राज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी है।
- यह 1901 के ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच स्वतंत्रता–पूर्व प्रत्यर्पण संधि की जगह लेगी जो 1958 में पत्रों के आदान–प्रदान के माध्यम से भारत में लागू की गई थी।
- संधि आतंकवादियों, आर्थिक अपराधियों और बेल्जियम से और अन्य अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है।

भारत–अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम (IUSSTF)

समाचार –

- भारत–अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम (IUSSTF) मार्च 2000 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था।
- यह दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्त द्विपक्षीय संगठन है जो विज्ञान, तकनीक, यांत्रिकी एवं नवान्मेंष को सरकारों, शैक्षिक जगत तथा उद्योगों में गहन परस्पर संवाद द्वारा स्थापित करने के लिए निर्मित किया गया है।
- IUSSTF की दृष्टि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोगात्मक पहलों के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है।
- इसका मिशन व्यक्तिगत वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक संस्थानों और बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक समुदाय के बीच साझेदारी के माध्यम से भारत और अमेरिका के बीच दीर्घकालिक वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।
- इस कार्यक्रम के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत की सरकारें और अमेरिकी राज्य विभाग संबंधित नोडल विभाग हैं।

संयूक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- हाल ही में, चीन ने मार्च 2020 माह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है।
- सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग हैं – महासभा, न्यासी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
- इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
- परिषद में 15 सदस्य हैं – पांच स्थायी सदस्य और 10 गैर–स्थायी सदस्य दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
- पांच स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम हैं।
- सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय नौ सदस्यों के एक संप्रदायी वोट द्वारा किए जाते हैं, जिसमें स्थायी सदस्यों के वोट भी शामिल हैं। पांच स्थायी सदस्यों में से किसी भी एक के 'नहीं' वोट से प्रस्ताव पारित होने से रोका जा सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, अपने हितों के विशेष रूप से प्रभावित होने की दशा में, मतदान के बिना, सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है।
- परिषद की अध्यक्षता हर महीने अपने 15 सदस्यों के बीच घूमती है।
- परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।

वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से जी 7 बैठक

समाचार –

- अमेरिकी राष्ट्रपति कोविड–19 संकट के कारण वाशिंगटन में इस वर्ष के जी–7 शिखर सम्मेलन को रद्द कर रहे हैं और इसके बजाय 19 मार्च 2020 को घोषित किए गए वीडियोकांफ्रेंसिंग द्वारा इस आयोजन को आयोजित करेंगे।
- अमेरिका 2020 में 7 धनी लोकतंत्रों के समूह का प्रमुख है।
- शिखर सम्मेलन अब कोविड–19 की स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों के जवाब में अपने सभी संसाधनों को केंद्रित करने के लिए प्रत्येक देश के लिए दूरस्थ रूप से जगह लेगा।
- जी 7 देश – ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका – सभी वायरस के प्रसार को रोकने तथा अपनी अर्थव्यवस्थाओं के मंदी में जाने के डर के चलते समान रूप से प्रयास कर रहे है।।

आंतरिक सुरक्षा

अमेरिका में हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण सफल

समाचार –

- अमेरिकी रक्षा विभाग ने 20 मार्च 2020 को घोषणा की कि उसने एक निहत्थे हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, एक हथियार जो संभावित रूप से एक प्रतिकूल रक्षा प्रणाली को अभिभूत कर सकता है।
- एक परीक्षण मिसाइल ने हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरी– ध्वनि की गति से 5 गुना या मेक 5– एक निर्दिष्ट प्रभाव बिंदु पर।

जी20 वर्चुअल समिट

समाचार –

- जी 20 समूह के नेताओं ने 26 मार्च 2020 को एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया।
- शिखर सम्मेलन का नेतृत्व सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने किया, जो आर्थिक समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
- बैठक में आमंत्रित देशों, स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संयुक्त राष्ट्र, द वर्ल्ड बैंक समूह, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, एफएओ, आईएमएफ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नेतागण शामिल थे।
- इस समुह में दुनिया की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अलावा यूरोपीय संघ भी शामिल है।
- भारत के लिए, सार्क के वीडियो मीट के बाद यह दूसरा नेतृत्व शिखर सम्मेलन है।

परिणाम –

- भारतीय नेता ने नए कोरोनवायरस के सामाजिक और आर्थिक लागतों को ध्यान में रखते हुए, जी 20 नेताओं को बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक सहयोग के केंद्र में 'मनुष्य' नाकि 'आर्थिक लक्ष्यों' को रखने की सलाह दी।

- सभी नेताओं ने महामारी के सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय प्रभावों का मुकाबला करने के लिए लक्षित राजकोषीय नीति, आर्थिक उपायों और गारंटी योजनाओं के हिस्से के रूप में, 'वैश्विक अर्थव्यवस्था में '5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर' को डालने का निर्णय लिया।
- नेताओं ने स्वैच्छिक आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व वाले कोविड–19 सॉलिडैरिटी रिस्पॉन्स फंड में योगदान देने पर भी सहमति व्यक्त की।
- जी 20 शिखर सम्मेलन में संकट की उत्पत्ति का कोई संदर्भ शामिल नहीं था। यह अमेरिका और चीनी नेताओं के बीच संभावित तनाव के जवाब में था।
- भारत ने कहा कि कोविड–19 के 90 प्रतिशत मामले और 88 प्रतिशत मौतें जी 20 देशों में हुईं, ये दुनिया की जीडीपी का 80 प्रतिशत और दुनिया की आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं।
- एक संयुक्त बयान जारी किया गया है जो महामारी द्वारा उजागर देशों की अंतर्संबंध और कमजोरियां की वास्तविकता में एकजुटता की भावना, पारदर्शी, मजबूत, समन्वित, बड़े पैमाने पर और विज्ञान आधारित वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान करता है।
- सदस्य देशों ने समय–समय पर और पारदर्शी जानकारी साझा करने, महामारी विज्ञान और नैदानिक डेटा का आदान–प्रदान करने, अनुसंधान और विकास के लिए आवश्यक सामग्री साझा करने और डब्ल्यूएचओ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के पूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन करके विश्व स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है।
- नेता रियाद शिखर सम्मेलन से पहले अधिक बातचीत करने के लिए सहमत हुए जो नवंबर 2020 में होगा।

डब्ल्यूएचओ और लॉकडाउन द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा –

- डब्ल्यूएचओ को दिसंबर 2019 में चीन द्वारा वुहान में इसके फैलने की सूचना दिए जाने के बावजूद दुनिया को महामारी से संभावित खतरे के बारे में जल्दी से सचेत करने में विफल रहने के लिए आलोचना की गई थी।
- अमेरिका ने पारदर्शी होने और वायरस के बारे में जानकारी साझा करने के लिए चीन की आलोचना की है।
- सामाजिक भेद के माध्यम से फैली महामारी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन पर जी–20 देशों के बीच मतभेद रहे हैं।
- अमेरिका लॉकडाउन को उठाना चाहता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।
- ब्राजील के राष्ट्रपति ने राज्य द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को अपराध कहा है।
- भारत ने पूरे देश में 21 दिन का कड़ा लॉकडाउन किया है।

कला एवं संस्कृति

शहीद दिवस

समाचार –

- प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है।
- इस दिन को शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
- इस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथी के दिवस 30 जनवरी से भ्रमित नहीं करना चाहिए।
- भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई थी।
- उन्हें 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। उसे वे गलती से ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ बैठे थे।
- पुलिस अधीक्षक जॉन स्कॉट द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिये जाने के कारण अंततः लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
- उनके जीवन ने अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया और उनकी मृत्यु ने भी एक मिसाल कायम की। उन्होंने आजादी की लड़ाई का अपना राह बनाया तथा आक्रामकता की आवश्यकता समझी इस प्रकार उनकी राह कांग्रेस से अलग थी।

शेख मुजीबुरहमान

समाचार –

- मार्च 17, 2020 को बांग्लादेश में जतिर पिता 'बंगबंधु, शेख मुजीर्बुरहमान की 100 वीं जयंती मनाई गई।
- मुजीर्बुरहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को तुंगिपारा, भारत (अब बांग्लादेश में) में हुआ था तथा उनका निधन अगस्त 15, 1975 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ।
- वे एक बंगाली नेता थे जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री (1972–75) बने और 1975 में राष्ट्रपति बने।
- उन्होंने 1949 में अवामी लीग के सह–संस्थापक के रूप में अपने औपचारिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत की।
- उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के अलग किए गए पूर्वी हिस्से के राजनीतिक स्वायत्तता की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद शेख मुजीर्बुरहमान की बेटी हैं।

900 से अधिक यक्षगान लिपियों को डिजिटाइज किया गया

समाचार –

- 1905 और 1907 में छपी 900 से अधिक यक्षगान लिपियों को अब डिजिटल रूप दिया जा चुका है तथा इसे ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सकता है।
- विभिन्न यक्षगान जैसे कि प्रह्लाद चरित्र 1905, रामास्वामध 1907 में, पुटरकामेस्ति 1913 में, कनकंगी कल्याण 1929 में, कुमुधुवती कल्याण 1931 में तथा संपोर्ण रामायण 1938 में प्रकाशित हुए हैं।
- विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लिपियों को स्कैन करके गुगल ड्राइव में डिजिटल रूप में संरक्षित किया गया है तथा एप और वेबसाइटों पर इसे उपलब्ध कराया जा रहा है।
- मुद्रित और पांडुलिपि रूपों दोनों में लिपियों का संग्रह और डिजिटलीकरण, चार परियोजनाओं में से एक है।
- डिजिटाइज की गई लिपीयों में से 65 को सृष्टि फॉऊडेशन द्वारा डिजीटाईज्ड किया गया है।
- ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कर्नाटक में लगभग 8,000 यक्षगान लिपीयाँ थी।
- उनमें से, आधी विभिन्न कारणों से नष्ट हो गई है।

यक्षगान

- यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक थिएटर रूप है।
- यह एक मंदिर कला का रूप है जिसमें पौराणिक कथाओं और पुराणों को दर्शाया जाता है।
- इसे बड़े पैमाने पर सिर पर पहने जाने वाले मुकुट, चेहरे के विस्तृत मेकअप और जीवंत परिधानों तथा गहनों के साथ किया जाता है।
- इसे आमतौर पर कन्नड़ में सुनाया जाता है, यह मलयालम के साथ–साथ तुलु (दक्षिण कर्नाटक की बोली) में भी किया जाता है।
- यह चेंदा, मद्दलम, जगत् या चेंगिला (झांझ) और चक्रताल या इलाथलम (छोटे झांझ) जैसे ताल वाद्ययंत्रों के साथ किया जाता है।

ललित कला अकादमी पुरस्कार

समाचार –

- भारत के राष्ट्रपति ने 4 मार्च, 2020 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 मेधावी कलाकारों को 61 वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया।

विवरण –

- ललित कला अकादमी ने सम्मानित होने वाले कलाकारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए देश भर के प्रतिष्ठित कला चिकित्सकों, कलाकारों और आलोचकों की सात सदस्यीय चयन जूरी को नामित किया।
- ललित कला अकादमी हर वर्ष कला को बढ़ावा देने तथा प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए कला प्रदर्शनियों और पुरस्कार समारोहों का आयोजन करती है।
- पुरस्कार विजेता कलाकारों की कलाकृति 22 मार्च, 2020 तक नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की दीर्घाओं में कला की 61 वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जाएगी।

विश्व विरासत सूची 2020 के लिए नामांकन

समाचार –

- हाल ही में, संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया है कि भारत ने वर्ष 2020 में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए दो नामांकन डोजियर 'धोलावीरा – ए हड़प्पन सिटी' तथा 'मोन्युमेंटस एवं फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत' प्रस्तुत किए हैं।

धोलावीरा – एक हड़प्पा शहर

- कच्छ के रण (गुजरात) के खादिर द्वीप में स्थित धोलावीरा शहर परिपक्व हड़प्पा चरण का था।
- 1985 में आर एस बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन किया गया था।
- यहाँ पूर्ण अनुपात, सड़क–पैटर्न और एक कुशल जल संरक्षण प्रणाली के साथ शहर नियोजन की एक उच्च संगठित प्रणाली प्रदर्शित होती है जिसने कठोर गर्म शुष्क जलवायु में लगभग 1200 से अधिक वर्षों (3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व) तक यहाँ जीवन को संभव बनाए रखा।
- धोलावीरा के जल संरक्षण के तरीके अद्वितीय है तथा प्राचीन दुनिया के सबसे कुशल प्रणालियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं।
- तीन स्तरों पर बना धोलावीरा शहर, ऊपरी (गढ़, बेली), मध्य में (रास्तों की व्यवस्था, बड़े पैमाने पर बाड़े और एक पुजन स्थल) तथा सबसे नीचे (संकरी गलियों, छोटे बाड़ों और औद्योगिक क्षेत्र) के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महानगरों से अलग था।

डेक्कन सल्तनत के स्मारक और किले

- दक्खन सल्तनत के स्मारक इस्लामिक वास्तुकला की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैलियों तथा वर्तमान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्षिणी भारतीय काल के प्रचलित हिंदू वास्तुकला के के अभिसरण को प्रर्दशित करते हैं।
- इसमें चार घटक शामिल हैं, कर्नाटक के गुलबर्गा में बहमनी स्मारक, कर्नाटक के बीजापुर में आदिल शाही स्मारक, कर्नाटक के बीदर में बहमनी और बारिद शाही स्मारक तथा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में कुतुब शाही स्मारक।
- **कर्नाटक के गुलबर्गा में बहमनी स्मारक** – इसमें मुख्य रूप से किले में बड़ी मस्जिद के साथ गुलबर्गा किला, जामी मस्जिद और सात कब्रों के साथ हफ्ते गुम्बद परिसर शामिल हैं। गुलबर्गा बहमनी राजवंश की पहली राजधानी थी।
- **कर्नाटक के बीजापुर में आदिल शाही स्मारक** – इसमें बीदर में 15 वीं शताब्दी के अंत से 16 वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों तक के स्मारक शामिल हैं, जिसमें बिदर किला, मदरसा महमूद गवन, अष्टूर में बहमनी कब्रें और बारिद शाही मकबरे शामिल हैं।
- बीदर की महत्वपूर्ण विशेषता गेट्स और स्लुइस की परिष्कृत प्रणाली है (एक स्लुइस एक गेट द्वारा इसके ऊपर नियंत्रित एक जल प्रवाह है।) जिसका उपयोग मट के बाढ़ खंडों में आवश्यक होने पर किया जा सकता है और इस प्रकार यह पानी को संरक्षित करता है।
- **कर्नाटक के बीजापुर में आदिल शाही स्मारक** – ये स्मारक 15 वीं शताब्दी के अंत से 17 वीं शताब्दी के अंत तक हैं। ये किलेबंदी, द्वार सहित 80 छोटे और बड़े स्मारकों के समूह हैं, पानी की व्यवस्था और टैंक, कई मस्जिद और मकबरे और महलनुमा संरचनाएँ। किले के भीतर सबसे उल्लेखनीय स्मारकों में गोल गुम्बज शामिल है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है।

- **हैदराबाद आंध्र प्रदेश में कुतुब शाही स्मारक** – इसमें गोलकोंडा किला, कुतुब शाही मकबरे और चारमीनार शामिल हैं जो कुतुब शाही राजवंश का प्रतीक हैं। गोलकोंडा कुतुब शाही वंश की प्रारंभिक राजधानी है। कुतुब शाहियों के मकबरों में शाही परिवार तथा उन अधिकारीयों की जो ईमानदारी से उनकी सेवा करते थे की कब्रें शामिल हैं। चारमीनार एक औपचारिक गेटवे है, जिसे 1591 इस्वी में हैदराबाद की स्थापना के समय बनाया गया था।

बीएचयू की टीम ने वाराणसी में 4,000 वर्ष पुराने शिल्प गांव का पता लगाया

समाचार –

- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम ने वाराणसी में लगभग 4,000 वर्ष पुरानी शहरी बसाहट का खुलासा किया है। यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शिल्प गांवों में से एक हो सकता है।
- विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर बभनियाव गाँव में इस स्थल का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया।
- इसमें पवित्र शहर के बारे में प्राचीन साहित्य में वर्णित बस्तियों में से एक के अवशेष मिले हैं। सर्वेक्षण में 5 वीं से 8 वीं शताब्दी के दौरान बने मंदिरों तथा 2000 से 4,000 वर्ष पुराने बर्तनों के अवशेष मिले हैं।

कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना

समाचार –

- संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने 2 मार्च 2020 को सूचना दी कि सरकार वृद्ध कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए "कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायतायोजना" नाम से एक योजना लागू कर रही है। विभिन्न लोक कलाकारों सहित विद्वानों ने कला, पत्र आदि के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन एक दयनीय जीवन जी रहे हैं।
- प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 4000 रूपये दिये जाएंगे जिसमें से न्यूनतम 500 रुपये राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। यदि मंत्रालय से जीवनसाथी से इस तरह का अनुरोध अपेक्षित दस्तावेजों के साथ लाभार्थी कलाकार की मृत्यु की तारीख के छह महीने के भीतर प्राप्त होता है तो, लाभार्थी की मृत्यु की दशा में, वित्तीय सहायता को जीवन पर्यंत लाभार्थी के पति या पत्नी के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकता है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

समाचार –

- संसद ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के साथ–साथ तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है।
- इससे पहले, राज्य सभा ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पारित किया गया था। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने उच्च सदन में इसके पारित होने के लिए प्रस्तुत किया था। लोकसभा ने दिसंबर 2019 में विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी।
- संस्कृत के विद्वान और शिक्षाविद् लंबे समय से तीन संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग कर रहे थे।
- तीन संस्कृत संस्थानों, जिन्हें एवं डिम्ड विश्वविद्यालयों राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा ग्रेड 'ए' संस्थानों के रूप में प्रमाणित किया गया है को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।
- इन विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का उद्देश्य अन्य भाषाओं को समाप्त करना है।

चत्र जात्रा महोत्सव

समाचार –

- ओडिशा के तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर में 17 मार्च 2020 को होने वाला वार्षिक चैत्र जात्रा उत्सव को कोविड–19 संक्रमण काल में एहतियाती उपाय के रूप में रद्द कर दिया गया।
- यह त्योहार चैत्र माह में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च–अप्रैल में आता है।
- रशिकुल्या नदी के तट पर तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर, ओडिशा में शक्ति पूजा का एक प्रमुख केंद्र है।
- जुड़वां देवी तारा और तारिणी एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और गंजम जिले (ओडिशा) की मुख्य देवता हैं।
- तारा महायान बौद्ध संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण देवता है।
- इस मंदिर का निर्माण ओडिया मंदिर वास्तुकला की पारंपरिक रेखा शैली के अनुसार किया गया था, जिसके अनुसार पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर बनाया गया है।
- अन्य मंदिरों के विपरीत, यह एक राजा या कुलीन के संरक्षण में नहीं बनाया गया था, मंदिर की स्थापना बसु प्रहाराज नामक एक ब्राह्मण द्वारा की गई थी, जो कि प्रसिद्ध किंवदंती थी।
- अपनी स्थापना के बाद से यह तंत्रवाद की एक स्थापित सीट रही है।
- भारतीय नौसेना की सेलबोट 'आईएनएसवी तारिणी' का नाम तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर के नाम पर रखा गया था। पहली भारतीय संपूर्ण महिला क्रू ने 'आईएनएसवी तारिणी' संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया है।

सामान्य अध्ययन I

(भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इतिहास एवं विश्व एवं समाज का भूगोल)

मरक्कड फिल्म विवाद

समाचार –

- हाल ही में केरल उच्च न्यायालय में फिल्म मरक्कड़ – द लायन ऑफ द अरेबियन सी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी।
- यह आरोप लगाया गया था कि यह फिल्म 'इतिहास को विरूपण' की ओर ले जाती है इसके रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कहा जाता है कि यह अब तक की सबसे महंगी मलयालम फिल्म है।

मरक्कड कौन थे?

- कुछ खातों के अनुसार, मरक्कड़ अरब मूल के थे और वर्तमान में कोझीकोड में कोइलंदी के पास ट्यूनीशिया से पंथालययानी तक चले गए थे।
- मरक्कड बाद में पय्योली के पास वर्तमान कोट्टक्कल और थिक्कोडी के आसपास के क्षेत्र में चले गए।
- अन्य खातों के अनुसार, मरक्कड कोचीन साम्राज्य के संपन्न व्यवसायी के वंशज थे जो बाद में कालीकट चले गए।
- मरक्कड ज्यादातर मुस्लिम थे, लेकिन कुछ हिस्सों में, वे हिंदू भी पाए गए हैं।

फिल्म का विवरण

- यह फिल्म कुंजली मरक्कड चतुर्थ पर आधारित है, जिसने पुर्तगाली जहाजों पर अपने उग्र हमले, पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ने वाले लोगो की सहायता करके, और कोट्टक्कल में किले को मजबूत करने के अपने प्रयासों से प्रतिष्ठा अर्जित की थी।
- यह एक युद्ध फिल्म है, जिसमें मरक्कड कबीले के नायकों को दर्शाया गया है, जिसके नेता 16 वीं और 17 वीं शताब्दी के दौरान कालीकट के जमोरिन के नौसेना प्रमुख थे।
- मलयालम में जमोरिन, समथिरी, मालाबार तट पर कालीकट साम्राज्य के शासकों को दी गई उपाधि थी। लगभग एक शताब्दी तक उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
- उनकी रणनीति गुरिल्ला युद्ध के समान थी। पुर्तगालियों के पास बड़े पैमाने पर जहाज थे जो समुद्र में आसान युद्धाभ्यास नहीं कर सकते थे।
- मरक्कड़ों ने छोटे जहाजों का इस्तेमाल किया, जो पुर्तगाली जहाजों को आसानी से घेर सकते थे, जिससे लड़ाके इच्छानुसार हमला कर सकते थे।
- कहा जाता है कि, 100 वर्षों की अवधि में, मरक्कड़ों के कार्तिकों ने कालीकट के नौसैनिक बेड़े को सौराष्ट्र से लेकर सीलोन तक सभी राज्यों की नौसेनाओं में सुधार किया। युद्ध प्रौद्योगिकियों और गोला बारूद में भी बहुत सुधार हुआ।

मुद्दा –

- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि घटनाओं के फिल्म संस्करण छात्रों और शोधकर्ताओं को गुमराह कर सकते हैं। हालांकि, उच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और फिल्म प्रमाणन बोर्ड से पूछा कि क्या उसने केंद्र को शिकायत सौंप दी है।
- बोर्ड ने संदेश दिया कि विषय कला से संबंधित है और यह फिल्म निर्माताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

अट्टुकल पोंगाल

समाचार –

- केरल के तिरुवनंतपुरम में 9 मार्च 2020 को वार्षिक अट्टुकल पोंगाल उत्सव शुरू हुआ।
- यह कोविड– 19 वायरस के खतरे के बीच हाल ही में शुरू हुई सबसे बड़ी सभी महिला धार्मिक सभाओं में से एक है।
- अट्टुकल भगवती मंदिर के पुजारी मुख्य चूल्हे – 'पंडारा अडुप्पु' जलाते है और इसकी ज्योति से तिरुवनंतपुरम में हजारों चुल्हे जलाए जाते हैं।
- हालाँकि कोविड–19 के खिलाफ केरल की एक नई लड़ाई शुरू होने के बाद भी महिला भक्तों ने हजारों के झुंड में पोंगल के अट्टुकल भगवती मंदिर के पीठासीन देवता के दर्शन किए।
- अट्टुकल पोंगल को महिलाओं की सबसे बड़ी मंडली के रूप में वर्णित किया जाता है, इसे महिलाओं के सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है।
- अट्टुकल पोंगल को अट्टुकल मंदिर, तिरुवनंतपुरम में में आयोजित किया जाता है।
- एक धार्मिक गतिविधि के लिए महिलाओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होने के लिए यह त्योहार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है।

प्रथाएँ

- पोंगल, जिसका अर्थ है 'उबालना', वह अनुष्ठान है जिसमें महिलाएं मीठे पयसेम तैयार करती हैं (चावल, गुड़, नारियल और साथ में पकाए गए हलवे) तथा इसे देवी या 'भगवती' को नेवैद्य चढ़ाती है।
- ऐसा कहा जाता है कि इस नेवैद्य से त्यौहार की देवी 'अटुकलाम्मा' प्रसन्न हो जाती है।
- पोंगल दस–दिवसीय त्योहार है।
- यह त्योहार 'कप्पू केतु समारोह' के दौरान देवी (कन्नकी चरित्रम) की कहानी के संगीतमय प्रतिपादन के साथ शुरू होता है।
- कहानी कोडुंगल्लूर भगवती की उपस्थिति और पांडियन राजा के वध को दर्शाती है। यह त्यौहार पांडियन राजा के वध के द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है।
- देवी द्वारा पंड्यायन राजा को नष्ट करने की घटना मंदिर के ढोल और भजनों द्वारा बहुत अधिक ध्वनि और रोष के साथ होती है, देवी के लिए प्रसाद की तैयारी के लिए भक्तों द्वारा तुरंत ज्योति डाली जाता है।

समाज और स्वास्थ्य प्रणाली पर कोविड–19 का प्रभाव

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने हाल ही में कहा है कि कोविड–19 महामारी वैश्विक बेरोजगारी में भारी वृद्धि करेगी, जिससे 25 मिलियन से अधिक लोग बेरोजगार होंगे या उनकी आय में कमी आएगी।
- भारत में कोविड–19 के प्रकोप की बढ़ती लहर ने देश में कॉरपोरेट जगत ने व्यापक रूप से अपने कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी है।
- भारत के श्रम कानून और प्रस्तावित श्रम संहिता घर से काम को एक व्यवहार्य कार्य व्यवस्था के रूप में मान्यता नहीं देते हैं।
- कोविड–19 ने न केवल वैश्विक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न किया है, बल्कि श्रम बाजार और आर्थिक विश्व पर भी इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा है।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अनुमानों के अनुसार, कोविड–19 प्रकोप के कारण दुनिया की छात्र आबादी लगभग आधा (49.22 प्रतिशत) स्कूलों और विश्वविद्यालयों में नही जा पा रहा है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) इन्फ्लूएंजा महामारी को कम करने के लिए 'गैर–फार्मास्युटिकल हस्तक्षेप (एनपीआई)' में से एक के रूप में स्कूल बंद करने (पूर्वस्कूली और उच्च शिक्षा सहित) की सिफारिश करता है।

स्वास्थ्य प्रणाली

- अधिकांश क्षेत्रों में महामारी के समय में मांग, आपूर्ति से अधिक रहेगी। यहां सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रीय और राज्य की स्वास्थ्य प्रणालियां बच्चों की जांच के लिए, अस्पताल के बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, बढ़ती मांगों का सामना कर सकेंगी।
- इस असाधारण मांग में पारंपरिक उत्पादन और वितरण चेकिंग की प्रणालियाँ हैं और अधिकतर, माँग की आपूर्ति से मेल नहीं खाती हैं।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की सिफारिश लंबे समय से चली आ रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्गों की स्थापना की सिफारिश उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (HLEG) यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर योजना आयोग को दी गई अपनी 2011 की रिपोर्ट द्वारा की गई थी। ।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडरों के स्थापना की बात भी करती है। अभी केवल तमिलनाडु और ओडिशा के पास ऐसे परिभाषित कैडर हैं।

सामाजिक मुद्दे

- प्रवासी श्रमिक, सड़क विक्रेता, अनुबंध श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग सभी कर्मचारी कोविड–19 द्वारा लाई गए आर्थिक सूनामी से प्रभावित हो रहे हैं।
- परिवहन मार्गों के अव्यवस्थित होने के साथ, यहां तक कि आने वाली गेहूं की फसल, उत्तर भारत में लाखों मजदूर परिवारों के जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण स्रोत, बहुत राहत नहीं ला सकता है।
- महामारी को धीमा करने के लिए लॉकडाउन लगाए गए थे, लेकिन गरीब लोग घर पर बेकार नहीं रह सकते। भारत और समृद्ध देशों (जहाँ एक अच्छी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है) के बीच इस संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतर है।
- देश में इस सख्ती से लगाए गए लॉकडाउन के बीच बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ और इसने अस्थायी श्रमिकों या गैर–संगठित श्रमिकों को अपने गृहनगर या गांवों में जाने के लिए मजबूर किया।
- आवश्यक सेवाओं को बंद करने की प्रवृत्ति से लोगों की कठिनाइयां बढ़ेंगी।

- कोई काम नहीं है और संसाधन समाप्त हो रहे हैं। अमीरों द्वारा वस्तुओं की जमाखोरी एवं भोजन की कीमतें बढ़ने से हालात और अधिक खराब ही होंगे।
- 21 दिन का लॉकडाउन का कोविड–19 बिमारी से लड़ने के लिए सही साबित होगा, लेकिन यह गरीब परिवारों की आय को प्रभावित कर रहा है।

कोविड–19 को रोकने के लिए उठाए गए कदम –

- 22 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस ने नए कोरोनोवायरस के प्रकोप के मद्देनजर 31 मार्च 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी में एक स्थान पर चार या अधिक लोगों के विरोध प्रदर्शन और असेंबली पर प्रतिबंध लगाने की सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी। लेकिन केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल 2020 तक देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की।
- देश भर में सभी ट्रेन, मेट्रो और अंतरराज्यीय परिवहन सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया था।
- बैंक नकद जमा और निकासी, चेक की निकासी, प्रेषण और सरकारी लेनदेन जैसी सेवाएं जारी रही हैं।
- सरकार ने एक मंच विकसित किया है जो देश भर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) डॉक्टरों द्वारा वेबिनार की मेजबानी करेगा।
- इसने एक ऐप भी विकसित किया है जो कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों के मार्ग का पता लगाएगा, जो संभावित संपर्कों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है।
- फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैट बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा कोविड–19 के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं।
- अस्पतालों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पोर्टल, और उन लोगों के साथ क्रॉस–रेफरिंग करना, जिन्होंने उपकरणों के साथ मदद की पेशकश की है, सरकार द्वारा भी स्थापित किया जा रहा है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर एक वेबिनार मंच विकसित किया गया है।
- डीआरडीओ ने सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी (SBMT) के साथ एक वेंटिलेटर विकसित किया था और अब इस तकनीक को मैसूरु के एक उद्योग में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- डीआरडीओ प्रयोगशालाओं ने 20,000 लीटर सेनेटाईज़र का निर्माण किया है और दिल्ली पुलिस जैसे विभिन्न संगठनों ने इसकी आपूर्ति की है।
- इसने एन–99 और 3–लेयर्ड मास्क विकसित किए हैं और दिल्ली पुलिस कर्मियों को 10,000 मास्क की आपूर्ति की है।
- यह निजी सुरक्षा उपकरण जैसे बॉडी सूट और वेंटिलेटर बनाने के लिए कुछ निजी कंपनियों के साथ गठजोड़ कर रहा है।
- यह रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर जो पहले से ही सशस्त्र बलों को भोजन की आपूर्ति करता है, के माध्यम से सरकार और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है।
- ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) ने सैनिटाइटर, मास्क और बॉडीसूट्स के उत्पादन में भी वृद्धि की है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को "व्यापक विकलांगता समावेशी दिशानिर्देश" जारी किए हैं।
- यह दिशानिर्देश महामारी कोविड–19 के प्रकाश में विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए है।
- सरकार ने कोविड–19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (राहत–सहायता कोष) में राहत की स्थापना की है।
- यह कोष कोविड–19 आपातकाल के मद्देनजर लोगों द्वारा सरकार को समर्थन देने के लिए किए गए कई अनुरोधों के कारण स्थापित किया गया है।
- सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) के साथ वे एंड मिन्स एडवांस (डब्ल्यूएमए) सीमा को 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।
- डब्ल्यूएमए सीमा को संशोधित कर 1.20 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है और इसकी समीक्षा आवश्यकता के आधार पर की जाएगी (पिछले वर्ष 75,000 करोड़ रुपये से)।
- यह कोविड–19 के प्रसार का मुकाबला करने के वित्तीय वर्ष 2021 के अपेक्षित उच्च व्यय के बेमेल नकदी प्रवाह की क्षतिपूर्ति करना है।

प्रधानमंत्री–कोष

- **पीएम केयर्स** फंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अलग है, जिसे 1948 में बनाया गया था।
- यह विभाजन से उत्पन्न स्थिति की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थापित किया गया था और पाकिस्तान से जो शरणार्थियों भारत आए थे उनके राहत और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया गया था।
- इसे 1973 में एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था लेकिन ट्रस्टियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था।
- प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को राहत देने के लिए अब मुख्य रूप से पीएमएनआरएफ के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। दोनों फंडों में दान करने पर कर में 100 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है।

उठाए जाने वाले कदम –

- चूंकि समय ही कुँजी है, इसलिए पहला कदम गरीब लोगों को – पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मध्याह्न भोजन और मनरेगा के अलावा अन्य लोगों के लिए मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अच्छा उपयोग करना है।
- प्रारंभिक उपायों में पेंशनों का अग्रिम भुगतान, स्कूलों और आंगनवाड़ियों में घर ले जाए जाने वाले राशन का वितरण शामिल हो सकता है।
- इसके बदले में केंद्र सरकार से बड़े धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार को कॉर्पोरेट बेलआउट्स पर अपने संसाधनों को बढ़ाने से बचने की भी आवश्यकता है – अर्थव्यवस्था के अधिकांश संकट प्रभावित क्षेत्र जल्द ही बचाव पैकेजों की पैरवी करेंगे।
- पीडीएस इस स्थिति में देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। यह अधिकांश लोगों की आय की हानि को नहीं रोकेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि घर में भोजन की कमी ना हो।
- राशन की दुकान पर भीड़ और धोखे से बचने के लिए वितरण को डगमगाते हुए और कसकर देखरेख करने की आवश्यकता है।
- लेकिन कई लोगों को पीडीएस से बाहर रखा गया है और उस मामले में, बड़े पैमाने पर नकद हस्तांतरण की भी आवश्यकता होती है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अग्रिम भुगतान और पेंशन राशियों में बड़ी वृद्धि के साथ शुरू होती है।
- आगे, खाद्य राशन भूख को रोक सकते हैं लेकिन लोगों को कई अन्य बुनियादी जरूरतें हैं, उन्हें बेरोजगारी के इस चक्र से निपटने के लिए धन की आवश्यकता होगी।
- पहला कदम राहत उपायों को लॉकडाउन योजना का एक अभिन्न अंग बनाना है। असफल होने पर, यह अधिक नुकसान कर सकता है। एक भूखी आबादी के वायरस से प्रभावी ढंग से लड़ने की संभावना नहीं है। रचनात्मक लॉकडाउन को लोगों को एक साथ वापस लड़ने के लिए सशक्त बनाना चाहिए, न कि उनके साथ भेड़ों जैसा व्यवहार करना चाहिए।
- अंत में, केंद्र–राज्य सहयोग आवश्यक है। कई राज्य सरकारों ने पहले ही मूल्यवान सामाजिक–सुरक्षा उपायों की शुरुआत की है, लेकिन वे पर्याप्त से कहीं दूर हैं।
- इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को अकथनीय पक्षाघात मार गया है।
- पर्याप्त राहत उपायों के लिए केंद्र सरकार से बड़े धन की आवश्यकता होती है। राज्यों द्वारा कार्यान्वयन का नेतृत्व किया जाना चाहिए। उन सभी की अपनी परिस्थितियाँ और विधियाँ हैं। केंद्र सरकार के अपनी ओर से बेहतर प्रदर्शन की संभावना नहीं है।
- सरकार का प्राथमिक लक्ष्य निःशुल्क परीक्षण की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना है। हर जिले के सामान्य अस्पताल में डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
- यात्रा प्रतिबंध और संगरोध अनिवार्य उपाय हैं, लेकिन केवल परीक्षण से ही समुदाय में बीमारी की सीमा का पता चल सकता है।
- सरकार कार्यशील पूंजी ऋण की गारंटी प्रदान कर सकती है और इसे संबंधित उधारकर्ताओं से आश्वासन के साथ जोड़ सकती है कि वे अपनी कंपनियों में नौकरियों को सुरक्षित करेंगे।
- भारतीय रिजर्व बैंक को विभिन्न उद्योगों के लिए बैंकों के लिए परिसंपत्ति मान्यता के मामले में विनियामक निषेध दिखाना चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह केवल अस्थायी सुविधाएँ है जब तक कि संकट खुद नहीं टलता है।
- सरकार को व्यापार पर अस्थायी कर राहत की पेशकश को देखना पड़ सकता है।

- ऐसे अन्य सहायक कार्य हैं जो सरकार अपने बिलों का तुरंत निर्वहन करने, बिना देरी के करों को वापस करने, तुरंत लाभान्वित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए ले सकती है, और यदि आवश्यक हो, तो भी प्रभावित व्यवसायों को भविष्य निधि और ईएसआई के रूप में सांविधिक देय राशि के भुगतान में अस्थायी रूप से विलंबित भुगतान की अनुमति दे सकती है।
- सरकार को सहायता उपायों को समर्पित करते हुए निजी क्षेत्र के साथ जुड़ना है।

पोक्सो के नए नियम अधिसूचित

समाचार –

- केंद्र सरकार ने 'यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण नियमों, 2020' को अधिसूचित किया है, जो अधिनियम में हालिया संशोधनों को लागू करने में सक्षम बनाता है, जिसके तहत बाल उत्पीड़न के लिए सजा के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है। पोस्को के नए नियम 9 मार्च 2020 से प्रभावी हो गए।

विवरण –

- नए नियमों में स्कूलों और देखभाल घरों में कर्मचारियों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन, यौन शोषण सामग्री (अश्लील साहित्य) की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, तथा अन्य कानूनों के बीच आयु–उपयुक्त बाल अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधान शामिल हैं।
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि, 'कोई भी व्यक्ति जिसने किसी अश्लील जिसमें बच्चे शामिल हैं या उसे ऐसी किसी भी अश्लील सामग्री के संग्रहण, वितरण, परिचालन, प्रसारण, सुगम प्रचार या प्रर्दशन की जानकारी या उसके होने की संभावना की जानकारी हो तो उसे इसे विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) या पुलिस, या साइबर क्राइम पोर्टल को रिपोर्ट करना होगा।
- रिपोर्ट में उस उपकरण का विवरण शामिल होगा जिसमें ऐसी अश्लील सामग्री देखी गई थी और संदिग्ध उपकरण जिसमें से ऐसी सामग्री प्राप्त हुई थी, जिस पर वह सामग्री प्रदर्शित की गई थी।
- नियमों के तहत, राज्य सरकारों को बच्चों के खिलाफ हिंसा के लिए 'शून्य सहिष्णुता' के सिद्धांत के आधार पर एक बाल संरक्षण नीति तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसे सभी संस्थानों, संगठनों या या बच्चों के संपर्क में आने वाली किसी अन्य एजेंसी द्वारा अपनाया जाएगा।
- केंद्र एवं प्रत्येक राज्य सरकार समय–समय पर बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों चाहे वे नियमित हों या संविदात्मक, बाल सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूक करने तथा शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिसमें, अभिविन्यास कार्यक्रम, संवेदीकरण कार्यशालाएं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों के लिए आयु–उपयुक्त शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है, जो उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचित करते हैं, तथा जिसमें उनकी शारीरिक और डिजीटल पहचान की सुरक्षा के उपाय भी शामिल हैं। टोल फ्री नंबर – 1098 के माध्यम से चाइल्डलाइन हेल्पलाइन सेवाओं सहित यौन अपराधों और रिपोर्टिंग तंत्र से उनकी भावनात्मक और मानसिक भलाई, रोकथाम और सुरक्षा करना भी इसमें शामिल है।
- नियमित आधार पर अपनी–अपनी भूमिकाओं में अपनी क्षमता निर्माण के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ तथा पुलिस कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और गहन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं।
- नए नियमों के तहत, कोई भी संस्था जो बच्चों को आवास प्रदान कर रही है या बच्चों के साथ नियमित संपर्क में आ रही है, जिनमें स्कूल, क्रेच, खेल अकादमियां या बच्चों के लिए कोई अन्य सुविधा शामिल है के प्रत्येक स्टाफ के आवधिक आधार पर पुलिस सत्यापन और पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करें।

विश्लेषण –

- बाल यौन शोषण से निपटने के लिए नए नियम इस अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी नीतिगत उपलब्धि है। यह पोक्सो को और अधिक प्रभावी और हमारे देश को बाल अनुकूल बना देगा।
- स्कूलों और देखभाल घरों में कर्मचारियों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन का प्रावधान, पीड़ितों के लिए तत्काल राहत, यौन शोषण सामग्री (पोर्न) की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, उपयुक्त बाल अधिकार शिक्षा प्रदान करना और राज्य बाल अधिकार निकायों के लिए निगरानी संकेतक महत्वपूर्ण कदम हैं।
- नए पोक्सो नियमों में प्रमुख प्रावधानों में से एक पीड़ित को समय पर मुआवजा प्रदान करना है। यह यह सुनिश्चित करने में पोक्सो अदालतों की भूमिका को दोहराता है कि 30 दिनों के भीतर ऐसा किया जाता है।

- कई कार्यों के लिए समयसीमाएँ हैं जिन्हें पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत निष्पादित करने की आवश्यकता है, और अब पोक्सो नियम 2020 उस पर जोर देता है अर्थात समयबद्धता पर जोर दिया गया है।
- हालांकि, एक प्रमुख मुद्दा जो बाल पीड़ित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, वह गैर–अनुपालन और जवाबदेही है, जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और ठीक से इसकी निगरानी की जानी चाहिए।

सामान्य अध्ययन II

(सरकार, संरक्षण, नीति, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

दलबदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य से थोऊनोजम श्यामकुमार सिंह को हटा दिया। कैबिनेट ने उन्हें 'अगले आदेश तक विधान सभा में प्रवेश करने से रोक दिया'।
- मंत्री के खिलाफ एक अयोग्य याचिका 2017 के बाद से अध्यक्ष के पास लंबित थी लेकिन अध्यक्ष उचित समय अवधि के भीतर निर्णय लेने में विफल रहे।
- अध्यक्ष 21 जनवरी 2020 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई 4 सप्ताह की निर्धारित समयावधि के भीतर भी कोई भी निर्णय लेने में विफल रहे।
- संविधान का अनुच्छेद 212 न्यायालयों को विधानमंडल की कार्यवाही में दखल देने से रोकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, अध्यक्ष का आचरण को कई अवसरों पर प्रश्नों के दायरे में आया है, अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत की असाधारण शक्तियों को लागू करने के लिए उसे 'विवश' किया गया है।
- इससे पहले, मणिपुर उच्च न्यायालय ने इस मामले को, दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य पाया था लेकिन निर्देश जारी नही किए गए थे।
- निर्देश जारी ना करने के पीछे कारण यह था कि क्या एक उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लंबित एक समय सीमा के भीतर एक अयोग्य ठहराव याचिका पर फैसला करने के लिए अध्यक्ष को निर्देश दे सकता है या नहीं।

जनवरी 21, 2020 आदेश

- अदालत ने सामान्य रूप से कहा कि 'अध्यक्ष, दसवीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए, एक उचित अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं का फैसला करने के लिए बाध्य है', जो 'प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।'
- शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिकाओं को संसद या विधानसभाओं के बाहर एक तंत्र द्वारा स्थगित किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने एक स्थायी न्यायाधिकरण का सुझाव दिया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एक नए तंत्र के रूप में की है। हालाँकि, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी।
- वर्तमान में, एक सदन/विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता सदन/विधानसभा के अध्यक्ष को संदर्भित की जाती है।
- न्यायालय के सुझाव के पीछे तर्क यह सुनिश्चित करना था कि इस तरह के विवादों को तेजी से और निष्पक्ष रूप से तय किया जाता है, इस प्रकार यह दसवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों को वास्तविक दाँव देता है।

दसवीं अनुसूची के बारे में –

- संविधान के 52 वें संशोधन के माध्यम से 1985 में एंटी–डिफेक्शन कानून पारित किया गया, जिसने भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया। कानून का मुख्य उद्देश्य 'दलबदल की राजनीतिक बुराई' का मुकाबला करना था।
- संविधान की दसवीं अनुसूची अवसरवाद की राजनीति से निपटने के लिए बनाई गई थी।
- यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तथा संसद या विधानमंडल में कार्यवाही के दौरान पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हिप के खिलाफ वोट करता है तो इसमें संसद और विधान सभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान है।

- यदि एक राजनीतिक दल के एक तिहाई सदस्य उस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को बदल देते थे जिसके प्रतीक पर वे चुने जाते थे और दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाते थे तो शुरू में अयोग्यता सिद्धांत लागू नहीं होता था।
- इससे बड़े पैमाने पर चूक हुई, जिससे चुनी हुई सरकारें अस्थिर हो गईं।
- दसवीं अनुसूची में संशोधन किया गया और एक तिहाई प्रावधान को खत्म कर दिया गया।
- अब दसवीं अनुसूची तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि एक राजनीतिक दल के दो–तिहाई सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय नहीं करते।
- छोटे राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में दो–तिहाई नियम को दरकिनार करना मुश्किल है, जहां विधानसभाओं की ताकत ऐसे विलय की अनुमति देती है।
- इस अनुसूची की प्रयोज्यता से बचने के लिए, विधानसभाओं के सदस्य अब चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए दूसरे मार्ग का उपयोग कर रहे हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (बी) के तहत, कोई भी विधायक सदन से इस्तीफा देने का हकदार होता है।
- निस्संदेह, अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वे इस तरह का इस्तीफा न तो स्वैच्छिक और न ही वास्तविक रूप में दे सकते हैं। अध्यक्ष, जांच पर, ऐसे इस्तीफे को अस्वीकार करने की शक्ति रखता है।

दलबदल कानून के पक्ष में दलीलें	दलबदल कानून के विपक्ष में दलीलें
दलों के प्रति वफादारियों बदलने पर रोक लगाकर सरकार को स्थायित्व प्रदान करता है।	सरकार की लोगों और संसद के प्रति उत्तरदायित्वों को कम करता है।
पार्टी के सहयोग से चुने गए प्रतिनिधी पार्टी के मेनीफेस्टो तथा नीतियों के प्रति वफादार बनाता है। पार्टी अनुशासन को बढ़ाता है।	सदस्यों की बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।

सुझाव –

- चुनाव सुधारों (1990) पर दिनेश गोस्वामी समिति ने सुझाव दिया कि अयोग्यता के मुद्दे पर भारत के चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।
- दलबदल विरोधी कानून पर बनी हलीम समिति ने सुझाव दिया कि शब्द 'स्वेच्छा से एक राजनीतिक पार्टी सदस्यता ले रहे हैं' तथा 'राजनीतिक दल' को अच्छी तरह से परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है।
- विधि आयोग (170 वाँ रिपोर्ट, 1999) ने सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों को व्हिप तभी जारी करने चाहिए जब सरकार खतरे में हो।
- भारत के चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि दसवीं अनुसूची के तहत निर्णय राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग की बाध्यकारी सलाह पर किया जाना चाहिए।
- संविधान समीक्षा आयोग (2002) ने सुझाव दिया कि एक सरकार को गिराने के लिए वोट डाले जाने वाले को अवैध माना जाना चाहिए और यह कि दोषियों को शेष पद की अवधि के लिए सार्वजनिक पद संभालने से रोक दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- यह एक और वायरस है जिसने राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित किया है।
- दवा केवल उन लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की जा सकती है जो कानून के शासन में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए प्रतिबद्ध हैं और संवैधानिक मूल्यों को गले लगाते हैं।
- सच्चाई इसके ठीक उलट है। गवर्नर, राजनीतिक दल, अन्य संवैधानिक प्राधिकारी, पुलिस और राज्य सरकारें लोकतंत्र को नष्ट करने में साजिश के सूत्रधार और हॉटबेड हैं।
- हम जो देख रहे हैं वह संवैधानिक अराजकता है। अदालतें इस तरह की कार्रवाइयों को तोड़–मरोड़ कर देखती हैं। फ्लोर टेस्ट एक फरेब बन गया है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश की राज्य सभा में नियूक्ति

समाचार –

- पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन या राज्य सभा के लिए नामित किया गया।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने से कुछ समय पहले, उन्होंने दूरगामी राजनीतिक परिणामों के साथ कई ऐतिहासिक फैसले दिए, जिसने सरकार को खुश कर दिया तथा बमुश्किल ही कोई ऐसा मामला रहा जिसमें सरकार की इच्छा के विरुद्ध निर्णय आया हो।

विवरण –

- संविधान सभा में, के टी शाह ने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सरकार के साथ एक कार्यकारी कार्यालय नहीं बनाना चाहिए, 'ताकि किसी न्यायाधीश (एक न्यायाधीश के रूप में) को उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले प्रलोभन या परिलब्धियाँ उपलब्ध न हो।
- हालांकि, इस सुझाव को बी आर अंबेडकर ने खारिज कर दिया था। उनके अनुसार "न्यायपालिका ऐसे मामलों में निर्णय लेती है जिसमें सरकार के हित यातो क्षीण होते हैं या नही होते हैं।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 (7) प्रदान करता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश 'भारत क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में या किसी भी अधिकारी के अंर्तगत कार्य नहीं कर सकते हैं।
- हालांकि, यह प्रावधान केवल न्यायपालिका में ही सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों को प्रतिबंधित करता है, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य आदि के पदों पर नहीं।
- इस प्रकार, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्ति न्यायिक स्वतंत्रता को कम कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि – सभी न्यायाधीशों को सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद के रोजगार की पेशकश नहीं की जाती है।
- 1958 में अपनी 14 वीं रिपोर्ट में, विधि आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सेवानिवृत्ती के बाद दो तरह के कामों में संलग्न होते थे – सबसे पहले, 'चैम्बर प्रैक्टिस' (एक शब्द, जो आज, निजी विवादों में मध्यस्थ राय देने और सेवा करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त होता है) और दूसरा, 'सरकार के तहत महत्वपूर्ण पदों पर रोजगार'।

जस्टिस गोगोई का कार्यकाल –

1. अयोध्या के फैसले से पहले, उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान सौदे की समीक्षा को खारिज कर दिया था, जिसमें बिना आधार के महत्वपूर्ण निर्णय के साथ एक स्वतंत्र जांच को नकारते हुए मूल निर्णय को चुनौती दी गई थी। मूल निर्णय सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को अवगत कराई गई कई झूठी और भ्रामक जानकारी के कई टुकड़ों पर निर्भर करता है।
2. अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने असम में एनआरसी कार्यक्रम की अध्यक्षता की और यह एक ऐसी कसरत साबित हुई जिसमें 19 लाख से अधिक लोगों को नागरिकता रजिस्टर के अंतिम संस्करण से बाहर रखा गया, और जिसकी कई आधारों पर आलोचना की गई। इस अभ्यास के परिणामस्वरूप भारी मानवीय संकट और विभाजनकारी राजनीति हुई।
3. सबरीमाला मंदिर की समीक्षा – उच्चतम न्यायायल की एक संविधान पीठ ने यह माना कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाए – भेदभावपूर्ण और इसलिए 'संवैधानिक नैतिकता' के खिलाफ।

- सीजेआई बनने के तुरंत बाद उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया था।

न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता के 16 बिंदु

- जजों के लिए 16–सूत्रीय आचार संहिता को 'मानों का प्रतिबंध' कहा जाता था (मई 1997 में एक मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में अपनाया गया) सेवानिवृत्ति के बाद के आचरण का आधार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई न्यायाधीश विशेष रूप से राजनीतिक दलों या राजनेताओं से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों का फैसला करने के बाद, जल्द ही सेवानिवृत्ति पाता है और उन बहुत से राजनेताओं या पार्टियों द्वारा राज्यसभा नामांकन के रूप में एक पद प्राप्त करता है, तो यह जाहिर तौर पर उसके बारे में गंभीर सवाल उठाएगा। एक न्यायाधीश के रूप में स्वतंत्रता पर जब उन्होंने उन मामलों का फैसला किया था।

निष्कर्ष –

- यह नामांकन न्यायपालिका के सदस्य को उसके कार्यकाल के दौरान उसकी अपेक्षाओं को पुरस्कृत करने वाले शासन के एक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा।
- यह तर्क देना निरर्थक होगा कि यह एक प्रख्यात न्यायविद् के लिए एक पुरस्कार है।
- उनकी सेवानिवृत्ति और नामांकन के बीच 4 महीने का अंतर और तथ्य यह है कि उनके न्यायालय में वर्तमान सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णयों की एक श्रृंखला लग रही थी।
- वे अब न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और उनका योगदान संसद में बहस करने के लिए विशेषज्ञता और ज्ञान तक सीमित होगा।
- दो पंखों के बीच सामंजस्य बनाने का कोई भी प्रयास आवश्यक रूप से कार्यपालिका और विधायिका पर निरोधक बल के रूप में न्यायपालिका की भूमिका का अतिक्रमण करेगा।

- उन्हें अयोध्या विवाद और राफेल जाँच में दिए गए जजों के स्वभाव को देखते हुए, प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिए था।
- प्रशासनिक मामलों में उन्होंने ऊपर के कुछ मामलों को प्राथमिकता दी है, जैसे कि चुनावी बांड की वैधता और कश्मीर की परिवर्तित स्थिति।
- यौन उत्पीड़न मामले में न्यायमूर्ति गोगोई और सरकार की कार्रवाइयां और सरकार द्वारा राज्यसभा सीट की पेशकश, कई महत्वपूर्ण निर्णयों की निष्पक्षता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करते हैं।
- मिसाल है कि उसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ प्रहार किया है। यह आशा की जा सकती है कि इस शर्मनाक कृत्य से सार्वजनिक रूप से विरोध पैदा होगा जो अन्य न्यायाधीशों को ऐसे आचरण का अनुकरण करने से रोक देगा।
- जैसा कि सरकार के लिए, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए इस तरह की पेशकश करना केवल पागलपन नहीं है। यह न्यायिक प्राधिकरण को कमजोर करने के एक खतरनाक इरादे को इंगित करता है ताकि निर्वाचित कार्यकारी को सभी शक्तिशाली के रूप में देखे।

आराम का समय

- संवेदनशील पदों से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सामान्य रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी अन्य नियुक्ति को स्वीकार करने से रोक दिया जाता है।
- पदों में इन कूलिंग–ऑफ पीरियड्स का कारण पिछले पद एवं नई नियुक्ति के बीच सांठगांठ को पर्याप्त समयांतराल द्वारा समाप्त करने के लिए होता है।

लोकपाल (शिकायत) नियम, 2020

समाचार –

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 59 के तहत एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें लोकपाल के लागु होने के एक वर्ष बाद लोकपाल के पास भ्रष्टाचार विरोधी शिकायतें दर्ज करने के लिए लोकपाल (शिकायत) नियम, 2020 नामक नियमों और निर्धारित प्रारूप को लागू किया है।

लोकपाल (शिकायत) नियम, 2020

- एक शिकायतकर्ता को पहचान का एक वैध प्रमाण देना होगा, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट है।
- विदेशी नागरिक भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहचान के प्रमाण के रूप में केवल उनके पासपोर्ट की एक प्रति स्वीकार की जाएगी।
- शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से, पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से दर्ज की जा सकती है। यदि शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती है, तो इसकी हार्ड कॉपी 15 दिनों के भीतर लोकपाल को प्रस्तुत करनी होगी।
- एक लोक सेवक के खिलाफ सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायु सेना अधिनियम और तटरक्षक अधिनियम के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है।
- अंग्रेजी में आमतौर पर एक शिकायत की जा सकती है, बशर्ते कि लोकपाल संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में शिकायत का उपयोग कर सकता है।
- आरोपी अधिकारी (यों) के विवरण, आरोप और उस पर निर्भर साक्ष्य के अलावा, शिकायतकर्ता या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को भी एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।
- यदि शिकायत एक बोर्ड, निकाय, निगम, कंपनी, सीमित देयता भागीदारी, प्राधिकरण, समाज या व्यक्तियों की ओर से है तो संस्था जिसकी ओर से शिकायत की गई है का पंजीकरण/निगमन प्रमाण पत्र, और हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, प्रस्तुत किया जाना है।
- लोकपाल पीठ पहली बार में प्रवेश चरण में शिकायत का फैसला करेगी। यदि आवश्यक हो तो लोकपाल अन्य विवरण या शपथ पत्र मांग सकता है।
- शिकायतकर्ता या आरोपी अधिकारी की पहचान लोकपाल द्वारा जांच या जांच के निष्कर्ष तक की जाएगी। हालाँकि, उन मामलों में संरक्षण लागू नहीं होगा जहाँ शिकायतकर्ता स्वयं लोकपाल को शिकायत करते हुए किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकरण को अपनी पहचान बताता है।
- वे शिकायतें, जिनकी सामग्री गैरकानूनी, अस्पष्ट या तुच्छ हैं, जिनमें कोई आरोप नहीं है, सात वर्ष की सीमा अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती हैं, या किसी अन्य अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं, 30 दिनों के भीतर निस्तारण किया जाएगा।

लोकपाल

- 1963 से, भारत लोकपाल नियुक्त करने की महत्वाकांक्षा को पोषित कर रहा है, जो एल.एम सिंघवी द्वारा गढ़ा गया है। स्वीडन के लोकपाल से कॉपी किया गया और 1967 में यू.के. में इसका अनुकूलन, 'कुशासन' के विचार को उजागर करना था।
- लोकपाल ने भारत में मार्च 2019 में अपने अध्यक्ष (न्यायमूर्ति पी.सी. घोष) और 8 सदस्यों की नियुक्ति के बाद काम करना शुरू किया। इसने अब तक 1,100 से अधिक शिकायतें प्राप्त की हैं, जिनमें से अधिकांश का निपटारा कर दिया गया है।

क्रिप्टोकरेंसी व्यापार पर प्रतिबंध अवैध था

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापार पर अंकुश लगा दिया। क्रिप्टो करेंसी ट्रेड पर अंकुश लगाने के उच्चतम न्यायलय के नियम अवैध हैं और वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन में ट्रेडिंग पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।
- भारिबैं ने 6 अप्रैल 2018 को भारत में लगभग क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह निर्देश दिया कि इसके द्वारा विनियमित (बैंकिंग चैनल) सभी आभासी मुद्राओं में सौदा नहीं करेंगे या उन से निपटने या बसने में किसी व्यक्ति या इकाई की सुविधा के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे।
- विनियमित संस्थाएं जो पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान कर रही थीं, उन्हें तीन महीने के भीतर इस से बाहर निकलने के लिए कहा गया था।
- भारिबैं ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसे खाते की खराब इकाई माना जाता था, जैसा कि उनके लगातार और उच्च उतार–चढ़ाव से प्रदर्शित होता है।
- उन्होंने कई जोखिमों का हवाला दिया, जिसमें धन–शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की चिंता भी शामिल है।
- उपभोक्ताओं के परिप्रेक्ष्य में, क्रिप्टोकरंसीज से जुड़े मुद्दों को उनके डिजाइन, उपयोग और संचालन और बाजार में हेरफेर के संकेत पर जानकारी की हड़ताली गंभीरता से बढ़ाया जाता है।
- उस प्रतिबंध ने उद्योग को एक गंभीर झटका दिया और भारत में एक दर्जन से अधिक एक्सचेंजों को बंद कर दिया।
- इस प्रतिबंध को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमए) ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी और कहा था कि क्रिप्टोकरंसी में लेनदेन करना और व्यापार करना एक वैध व्यावसायिक गतिविधि थी और भारिबैं के पास इस पर अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि इन परिसंपत्तियों को मुद्रा के बजाय वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

हाल का निर्णय –

- शीर्ष अदालत ने आरबीआई की कार्रवाइयों को उन जोखिमों के लिए 'अनुपातहीन' पाया, जो इसे संबोधित करने के लिए मांगे थे और इसलिए, रोक को असंवैधानिक माना गया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) द्वारा गारंटीकृत व्यापार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
- निर्णय के अनुसार भारिबैं के पास आभासी मुद्राओं के व्यवहार करने की शक्ति है, किंतु इस पर रोक अत्यधिक है क्योंकि इससे अन्यथा वैध व्यापार की जीवन रेखा कट जाएगी।

आभासी मुद्रा पर प्रतिबंध हटाने का प्रभाव –

- सत्तारूढ़ भारत में आभासी मुद्रा निवेशकों और व्यवसायों के लिए एक संशयपूर्ण सरकार द्वारा योजनाबद्ध किए जा रहे कड़े नियमों के खिलाफ धकेलने का एक अवसर है, और शक्तिशाली।
- सत्तारूढ़ भारत में आभासी मुद्रा निवेशकों और व्यवसायों के लिए एक संशयपूर्ण सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही सख्त नियमों के खिलाफ धक्का देने का एक अवसर है, और संभवतः फेसबुक इंक की तुला क्रिप्टोक्यूरेंसी जैसी परियोजनाओं के लिए उम्मीद जगाता है।
- इस आदेश के साथ, क्रिप्टोकरेंसी के अधिक परिपक्व और संतुलित विनियमन और समग्र रूप से फिनटेक क्षेत्र की संभावना है।
- प्रतिबंध के इस उठाने से ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद मिलेगी।
- उच्चतम न्यायालय के फैसले से औपचारिक वित्तीय प्रणाली को फिर से खोलकर एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
- क्रिप्टोकरंसी की अनुमति देने से भारत इस वैश्विक सौदे का हिस्सा बन सकेगा।

आगे को राह –

- SC अलग से एक अन्य मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें यह डिजिटल मुद्राओं के लिए नियमों पर फैसला करेगा, और यह निर्णय सख्त मानदंडों के लिए मामले को कमजोर करता है।
- इसके आधार पर, सरकार को क्रिप्टोकरेंसी पर अपने प्रस्तावित कानून को संशोधित करना होगा। यह निर्णय नए युग के लेन–देन को अपनाने में भारत की छवि को बदलने की दिशा में काम करने वाला है।
- भारत के लिए, एक डिजिटल इकोनॉमी पावरहाउस बनने का लक्ष्य रखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचैन जैसी उभरती हुई तकनीकों को अपनाना जरूरी है।

विश्व में स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020

समाचार –

- विश्व में स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 लोकतंत्र समर्थक गैर–स्वतंत्रता फ्रीडम हाउस, एक यू.एस.–आधारित प्रहरी द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट है, जो लगभग आधी शताब्दी से वैश्विक राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता पर नजर रख रही है।
- फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग स्वतंत्र श्रेणी में शीर्ष पाँच देश हैं।
- भारत दुनिया के सबसे कम मुक्त लोकतंत्रों में से एक बन गया है। भारत ने राजनीतिक अधिकार श्रेणी में 40 में से 34 अंक बनाए, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता श्रेणी में 60 में से केवल 37 अंक, कुल स्कोर 71 के, पिछले वर्ष के स्कोर 75 से कम है।
- यह रिपोर्ट भारत को तिमोर–लेस्ते और सेनेगल के साथ 83 वें स्थान पर रखती है। यह 'स्वतंत्र' के रूप में वर्गीकृत, देशों के ढेर में नीचे है और केवल ट्यूनीशिया को ही इससे कम अंक प्राप्त हुए हैं।
- रिपोर्ट 'भारतीय कश्मीर' को एक अलग क्षेत्र के रूप में मानती है, जिसने इस वर्ष अपना कुल स्कोर 49 से 28 तक घटाया था, इसे 'आंशिक रूप से मुक्त' की स्थिति से 'नॉट फ्री' में स्थानांतरित किया गया है।
- स्वायत्तता की घोषणा और कश्मीर के बाद के शटडाउन, नागरिक रजिस्टर और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को भारत में स्वतंत्रता की गिरावट के मुख्य संकेत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- इन तीन कार्यों ने भारत में कानून के शासन को हिला दिया है और इसकी राजनीतिक प्रणाली के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी स्वरूप को खतरा पैदा कर दिया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को लंबे समय से चीन के लिए एक लोकतांत्रिक प्रतिकार के रूप में देखा जाता है और इसलिए इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक रणनीतिक साझेदार है। हालाँकि, यह नजरिया बदल रहा है, भारत चीन के खिलाफ की गई आलोचना के समान है।
- रिपोर्ट ने कश्मीर में इंटरनेट ब्लैकआउट को एक लोकतंत्र द्वारा लगाया गया सबसे लंबा बंद करार दिया। इसने कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में थी, पत्रकारों, शिक्षाविदों और अन्य लोगों को जब राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों को संबोधित करते हुए उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ रहा था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 'लोकतंत्र और बहुलवाद पर हमला हो रहा है' जो अमेरिका और भारत की गिरावट को उजागर करता है।
- यह नकली समाचारों के प्रसार और सामग्री में हेरफेर करने पर भी प्रकाश डालता है, जिससे राजनीतिक विभाजन होता है।
- पिछले वर्ष की तुलना में, 2019 में, 64 देशों में व्यक्तियों ने अपने राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट का अनुभव किया, जबकि सिर्फ 37 अनुभवी सुधारों में। 2009 में 'स्वतंत्र' घोषित किए गए आधे से अधिक देश अब 'स्वतंत्र नहीं' है। पिछले एक दशक में यह शुद्ध गिरावट आई है।

रिपोर्ट के बारे में –

- यह रिपोर्ट 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा से इसकी कार्यप्रणाली का पता लगाती है।
- यह 195 देशों को कवर करता है, चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद और भागीदारी और सरकारी कामकाज के साथ–साथ नागरिक स्वतंत्रता संकेतक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नागरिक स्वतंत्रता संकेतक और कानून और व्यक्तिगत के नियम जैसे राजनीतिक अधिकारों तथा स्वायत्तता और व्यक्तिगत अधिकार के संकेतक के आधार पर स्कोर प्रदान करती हैं।

भूमि अधिग्रहण

समाचार –

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, यदि क्षतिपूर्ति इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में राजकोष में जमा करके की गई है तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।
- पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के तहत पहले के 2014 के फैसले को भी खारिज कर दिया।

विवरण –

- इस नवीनतम फैसले में, बेंच ने 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) की व्याख्या की, जिसमें कहा गया है कि अगर जमीन का भौतिक कब्जा नहीं किया गया है तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो अधिग्रहण खत्म हो जाएगा।
- हाल के फैसले ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को बनाए रखने के लिए अदालत में कोई दायित्व नहीं था तथा राशि जमा की जाए। यदि कोषागार में राशि डाल दी जाती है तो मुआवजे को भुगतान माना जाएगा।
- इस प्रकार, यदि कब्जा कर लिया गया है तो यह कोई चूक नहीं है और मुआवजा का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी तरह, यदि कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है।
- उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की संपन्न कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म नहीं देती है।
- इस अधिनियम के अनुसार यदि भौतिक अधिकार नहीं लिया गया है या मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है तो सरकार को 2013 के अधिनियम के तहत 'ताजा कार्यवाही' शुरू करनी है।
- यह मुद्दा था कि क्या सरकार द्वारा राजकोष में मुआवजे का भुगतान 2013 के भूमि अधिग्रहण की धारा 24 (2) के अनुसार भूस्वामी को भुगतान के रूप में किया जा सकता है।
- शीर्ष अदालत ने 2014 (पुणे नगरपालिका मामले) और 2018 (इंदौर विकास मामले) में दिए गए दो विरोधाभासी निर्णयों यदि सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि पांच वर्ष के भीतर मुआवजे को जमा करने में विफल रहती है तो क्या जमीन का कब्जा चला जाएगा या नहीं पर पर विवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा था।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 (2013 अधिनियम) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

- इस अधिनियम ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 अधिनियम) को प्रतिस्थापित किया।
- नया अधिनियम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की दोनों परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा भूमि से वंचित लोगों को उच्च मुआवजा प्रदान करता है।
- यह भूमि के अधिकांश मालिकों की सहमति को भी अनिवार्य करता है और इसमें पुनर्वास और पुनर्वास के प्रावधान शामिल हैं।

मुद्दा –

- किसानों और जमींदारों के मुआवजे से इनकार करने के मामले हैं जो सरकार द्वारा कब्जे में देरी करते हैं।
- ऐसे मामलों में, मुआवजा सरकारी खजाने में जमा किया जाता है और एक व्याख्या के अनुसार अधिग्रहण की प्रक्रिया को बचाया जाता है।
- यह व्याख्या इस आधार पर की गई है कि ऐसे मामले नए अधिनियम के तहत आएंगे क्योंकि भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है,

और धारा 24 में लैप्सिंग क्लॉज लागू किया जाना चाहिए।

- यदि पुराने कानून के तहत लंबे समय से लंबित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बंद हो जाती है और नए के तहत नए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होती है, तो जमीन के मालिकों को लाभ होगा और परियोजना के प्रस्तावकों को उच्च मुआवजा देना होगा।
- पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद मिसिरिमल सोलंकी मामले 2014 में, तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अधिग्रहण की कार्यवाही 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, जो 2013 के कानून (2014 में) लागू होने से पांच वर्ष पहले शुरू की गई थी, अगर जमीन में जमीन का कब्जा चला जाएगा प्रश्न का नियंत्रण नहीं लिया गया था या विस्थापित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया था।
- फैसला भूस्वामियों के लिए राहत के रूप में आया।
- हालांकि, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम शैलेन्द्र (डी) एलआरएस एंड ऑर्सेस केस 2018 के माध्यम से, एक और तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने 2014 के फैसले को 'पर इंक्येरियम' घोषित किया।
- यह माना जाता है कि यदि कोई जमीन मालिक डेवलपर द्वारा दिए गए मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, तो वे अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकते हैं और पुराने कानून के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही में चूक कर सकते हैं।
- यह निर्णय डेवलपर्स के लिए एक राहत थी।

बिना राजनीतिक लक्ष्य के किसी संगठन दंडित नहीं किया जा सकता

समाचार –

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार किसी संगठन को 'राजनीतिक' ब्रांड नहीं दे सकती है। तथा ऐसा करके वह "असंतोष के वैध रूपों" जैसे कि बंद, हरताल, सड़क रोको या जेल सार्वजनिक कारण की सहायता के लिए के लिए उसे विदेशी धन प्राप्त करने के अपने अधिकार से वंचित नही कर सकती है।

विवरण –

- कोई भी संगठन जो किसी राजनीतिक लक्ष्य या उद्देश्य के बिना अपने अधिकारों के लिए आंदोलनरत नागरिकों के एक समूह के कारण का समर्थन करता है, उसे राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित करके दंडित नहीं किया जा सकता है।
- लेकिन उनकी विदेशी फंडिंग तब तक जारी रह सकती है जब तक ये संगठन 'समाज के सामाजिक और राजनीतिक कल्याण' के लिए काम करते हैं।

राजनीतिक उद्देश्य –

- अदालत ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की 'संघ या उप–कानूनों के ज्ञापन में' राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले संगठनों को विदेशी निधियों तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे संगठन स्पष्ट रूप से 'राजनीतिक प्रकृति' के थे।
- यह निर्णय भारतीय सामाजिक कार्य मंच द्वारा दायर याचिका पर आया था, जिसमें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के कुछ प्रावधानों और 2011 के विदेशी अंशदान (नियमन) नियमों को चुनौती दी गई थी, दोनों ही केंद्र को 'अघोषित और अघोषित शक्ति' से सम्मानित करते हैं। 'ब्रांड संगठनों के लिए 'राजनीतिक' और विदेशी निधियों तक उनकी पहुँच को बंद करें।
- एफसीआरए 2010 ने राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग पर रोक लगा दी।
- जिस उद्देश्य के लिए कानून एक राजनीतिक प्रकृति के संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकता है, वह यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासन विदेशी निधियों से प्रभावित न हो।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी सहायता प्राप्त करने पर प्रतिबंध, सक्रिय राजनीति में शामिल लोगों द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों की रक्षा की जाए। दूसरी ओर, ऐसे स्वैच्छिक संगठनों का, जिनका या तो दलगत राजनीति या सक्रिय राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उन्हें विदेशी योगदान से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अदालत के सामने चुनौती के तहत प्रावधान –

- अदालत के समक्ष चुनौती के प्रावधानों में एफसीआरए की धारा 5 (1) शामिल थी। इस प्रावधान ने केंद्र को यह तय करने की अनुमति दी कि क्या यह प्रतीत होता है कि गैर–राजनीतिक संगठन वास्तव में प्रकृति में राजनीतिक था।
- INSAF ने तर्क दिया कि धारा 5 (1) अस्पष्ट थी और इस प्रकार असंवैधानिक थी। दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसने पहले INSAF से संपर्क किया था, ने कहा कि यह प्रावधान 'विस्तार' है और अस्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से सहमत था।

- माइक्रोस्कोप के तहत अगला प्रावधान एफसीआरए की धारा 5 (4) था। INSAF ने कहा कि प्रावधान ने उस प्राधिकरण की बिल्कुल पहचान नहीं की है जिससे पहले कोई संगठन अपनी शिकायत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन शीर्ष अदालत ने इस विवाद को खारिज कर दिया।
- INSAF ने 2011 के नियमों के नियम 3 के विभिन्न खंडों को भी चुनौती दी थी। यह प्रावधान उन विभिन्न प्रकार की 'राजनीतिक' गतिविधियों की पहचान की जिनके लिए/संगठन जिनके विदेशी धन को सरकार द्वारा रोका जा सकता था।

कोविड–19 एवं मल्टीलेटरिज्म (बहुपक्षीय)

समाचार –

- वैश्विक नेता इस आम सहमति पर पहुंच गए हैं कि महामारी कोविद–19 और इससे उत्पन्न संकट आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
- संकट दुनिया को वैश्वीकरण की एक नई मानव–केंद्रित अवधारणा बनाने का अवसर प्रदान करती है।
- कोरोनावायरस ने अमेरिका और चीन के बीच तनाव को गहरा करने के एक समय के रूप में दिखाया है।
- गंभीर सामूहिक चुनौती कि वायरस के गठन ने ना केवल संघर्ष को तेज किया है। अमेरिका ने चीन को इस वायरस को वैश्विक राक्षस बनने देने का दोषी ठहराया और बीजिंग यह सब करने से इनकार कर रहा है कि यह वायरस चीन से बाहर आया था।

संघर्ष विराम में डब्ल्यूएचओ फँस गया –

- यह आरोप कि डब्ल्यूएचओ का नेतृत्व 'चीनी प्रचार का उपकरण' बन सकता है, यह दर्शाता है कि कैसे बीजिंग और विश्व निकाय के संबंध नाटकीय रूप से हाल के वर्षों में बदल गए हैं।
- सांस्कृतिक क्रांति के कारण एक राष्ट्र के रूप में, चीन ने 20 वीं सदी के अंतिम दशकों में खुद को फिर से बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक संस्थानों का इस्तेमाल किया।
- अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने वैज्ञानिक और तकनीकी आधार को उन्नत करने के बाद, चीन अब वैश्विक शासन को फिर से चलाने और एक नियम–निर्माता बनने के लिए तैयार है।
- प्रभाव वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। डब्लूएचओ के साथ चीन के विस्तार की वैश्विक व्यस्तता, इसके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम और एक प्रभावशाली घरेलू स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र, 'ग्लोबल सिल्क रोड फॉर हेल्थ' बनाने के लिए चीन की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं।
- अमेरिका–चीन के कोरोनोवायरस पर हावी होने के हताहतों में से एक डब्ल्यूएचओ है, जो महामारी से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास के बहुत मध्य में माना जाता है।
- WHO पर आरोप लगाया गया है कि वह वायरस के प्रसार के खिलाफ दुनिया को तैयार करने के बजाय चीन के हितों की सेवा कर रहा है।
- इन आरोपों का आधार डब्ल्यूएचओ का जनवरी के मध्य में चीनी दावे का समर्थन है, जिसमें वायरस के मानव–से–मानव संचरण का कोई सबूत नहीं था, बीजिंग के संकट और अन्य देशों की आलोचना के लिए निरंतर समर्थन, यात्रा पर प्रतिबंध और चीन से प्रतिबंध।
- डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक आपातकाल कहने के फैसले में देरी करके दुनिया को शालीनता में उलझा दिया।
- बहुपक्षवाद के नए भू–राजनीति की ओर यह सभी बिंदु, संयुक्त राष्ट्र में चीन की भूमिका पर पश्चिम और भारत दोनों की धारणाओं को खारिज करते हैं और अपने राष्ट्रीय लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का लाभ उठाने में चीन की सफलता को रेखांकित करते हैं।
- लगभग 2 दशक पहले, SARS संकट के दौरान, WHO सामने वाले केंद्र पर था और चीन पर दबाव डालने वाली महामारी पर सफाई करने के लिए दबाव डाला।
- 2003 में, इसने दक्षिणी चीन में महामारी के उपरिकेंद्र से यात्रा करने के लिए संगठन की पहली यात्रा सलाहकार जारी की थी।
- जैसा कि SARS संकट बढ़ा है, चीन की राज्य संप्रभुता की केंद्रीयता के बारे में पारंपरिक तर्क WHO के साथ काम करने और दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ोसियों को आश्वस्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए एक नई जगह की उपज है।
- कुछ चीन और WHO के बीच चीन के बढ़ते वित्तीय योगदान के बीच संबंधों में बदलाव का श्रेय देते हैं। दूसरों का सुझाव है कि 2017 में टैड्रोस के चुनाव में चीन का राजनीतिक समर्थन महत्वपूर्ण था।

- संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक बहुपक्षीय प्रणाली में अपने विस्तार के एक जागरूक और परिणामी चीनी प्रयास की कुछ अधिक मौलिक बात करते हैं।
- चीन, जिसे 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भर्ती किया गया था, 1980 के दशक में अपना रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, 1990 के दशक में सावधानी से अपना प्रोफाइल उठाया, सहस्राब्दी के मोड़ पर कुछ राजनीतिक पहल की और आखिरी में नेतृत्व को जब्त कर लिया।
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली पर चीन के उदय के प्रभाव से निपटने के लिए न तो पश्चिम और न ही भारत तैयार हुआ है। उन्हें उम्मीद थी कि चीन पश्चिम द्वारा निर्धारित नियमों से खेलेंगा।

कोविड–19 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया –

- कोविड–19 संकट से निपटने के लिए हस्तक्षेप अब तक लगभग पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर है, जो संगरोध और सामाजिक भेद पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुतः कोई समन्वय नहीं है।
- चीन और अमेरिका के बीच दोषपूर्ण खेल दिखाई दे रहा है जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नेतृत्व के लिए अच्छा नहीं है।
- यह खेल की वर्तमान स्थिति है, दीर्घकालिक प्रभाव वैकल्पिक रास्ते का अनुसरण कर सकता है। एक, अधिक आशावादी परिणाम देशों के लिए अंततः यह महसूस करने के लिए होगा कि राष्ट्रीय विकल्प से दूर जाने और पुनर्जीवित और मजबूत बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तर्क को गले लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
- अन्य अधिक निराशाजनक परिणाम यह हो सकता है कि राष्ट्रवादी रुझान अधिक तीव्र हो जाते हैं, देशों ने अपने चारों ओर दीवारें बनाना शुरू कर दिया है और यहां तक कि मौजूदा बहुपक्षवाद को और कमजोर किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूएचओ जैसे संस्थान, जो पहले से ही हाशिए पर हैं, तेजी से अप्रासंगिक हो सकते हैं।
- निरंकुश आर्थिक और व्यापार नीतियों और इससे भी गहरी और अधिक व्यापक विरोधी वैश्वीकरण भावना पर वापसी हो सकती है। जब तक बहुपक्षवाद के पुर्नपुष्टि के माध्यम से इस पर ध्यान देने का एक सचेत प्रयास नहीं होता है, हम बहुत कुछ देख सकते हैं।
- यह तब है जब दुनिया को लघु आपूर्ति में नेतृत्व और राज्य कौशल की आवश्यकता है। आज दुनिया–इंटर–कनेक्टेड, इंटर–रिलेटेड और भी अन्योन्याश्रित है, फिर भी यह आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को कैसे संभालना है, जैसे वैश्विक लक्ष्यों पर एक मंच पर आने या ग्लोबल एजेंडा को फ्रेम करने में सक्षम नहीं है।

भारत –

- भारत, जिसने 1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर अमेरिकी प्रभुत्व को एक बड़ा खतरा माना, ने 'बहुध्रुवीय दुनिया' को बढ़ावा देने में चीन के साथ गठबंधन करने का विकल्प चुना। भारत ने खुद को आश्वस्त किया कि सीमा, पाकिस्तान और अन्य मुद्दों पर मतभेद के बावजूद, चीन के साथ सहयोग के लिए बहुत बड़ा स्थान है।
- भारत ने पाया कि चीनी वैश्विक आधिपत्य अमेरिकी प्रधानता की तुलना में बहुत अधिक समस्याग्रस्त हो सकता है। आखिरकार, यह चीन है जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारत की योजनाओं को जटिल करता है, सीमा पार आतंकवाद पर अंतरराष्ट्रीय दबावों के खिलाफ पाकिस्तान की रक्षा करता है और कश्मीर का सवाल उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लगातार धक्का देता है।
- भारत अब संयुक्त राष्ट्र में अपने कुछ हितों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर रुख करता है।
- अगर कोई ऐसा सबक है जो भारत चीन के अनुभव डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र के साथ सीख सकता है, तो यह है कि बहुपक्षवाद प्रमुख शक्तियों के लिए अपने आप में एक अंत नहीं है।
- किसी के राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को आकार देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन है।
- अपनी ओर से, भारत को भारत के बहुपक्षवाद के पुनर्संरचना को तेज करने की आवश्यकता है, भारत के आंतरिक आधुनिकीकरण और उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसे संयुक्त राष्ट्र में अपने राजनयिक लेक्सिकॉन को फिर से लिखना, और एक साथ नए राजनीतिक गठबंधन बनाना होंगे।
- कोरोना संकट भारत के अपने स्वास्थ्य कूटनीति के लिए एक नई पटकथा लिखने का एक अच्छा क्षण है।

- भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) सॉलिडैरिटी ट्रायल में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका उद्देश्य कोविड–19 के इलाज के लिए दवाओं के लिए तेजी से वैश्विक खोज करना है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम –

- गुटनिरपेक्षता की पूर्व की नीति के विपरीत सभी देशों के साथ दोस्ती करने की भारत सरकार की नीति प्रशंसनीय थी। जब ये खतरे में होते हैं तो यह अपने हितों की रक्षा करने में समान रूप से दृढ़ होता है।
- गुटनिरपेक्षता एक रक्षात्मक नीति थी जिसने 'हर देश से समान दूरी' की वकालत की थी।
- भारत अभी भी तटस्थ, अकल्पनीय अर्थ गुटनिरपेक्ष था, लेकिन दूरी के आधार पर नहीं बल्कि मित्रता के आधार पर।
- भारत की पारंपरिक विदेश नीति घनी अंर्तसंबंधित दुनिया से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर देती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पारंपरिक सक्रियता को बनाए रखते हुए, वैश्विक सहयोग जुटाने में विशेष रूप से कोविड–19 से लड़ने में नेतृत्व की भूमिका सही साबित हुई है।
- हाल ही में, भारत ने कोविड–19 पर एक क्षेत्रीय सहयोगात्मक प्रयास के लिए सार्क सदस्य देशों के साथ पहली वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग करके सक्रिय भागीदारी दिखाई है। इसके बाद जी–20 के माध्यम से या यूएन के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय पहल होनी चाहिए।

टीके का निशान –

- एक कोविड 19 टीके की खोज अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का विषय बन गया है।
- अमेरिका, यूरोप और चीन के लिए, इस दौड़ में राष्ट्रीय गौरव दांव पर है। आरोप लगाया गया है कि अमेरिका यूरोपीय, विशेष रूप से जर्मनी को हराने का प्रयास कर रहा है, जो अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के प्रयास में एक टीका खोजने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- अमेरिका और चीन जैसी स्व–कथित महान शक्तियां विशेष रूप से चिंतित हैं कि वायरस को नियंत्रित करने में असमर्थता और इसके लिए एंटीडोट्स न केवल उनके चेहरे के लिए नुकसान हो सकते है, बल्कि लंबे समय तक उनकी छवि को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक एजेंडा सेट करने की क्षमता के साथ महान शक्तियों के रूप में उनकी छवि को नष्ट भी कर सकते है।
- अमेरिकी टिप्पणीकार और नीति निर्धारक विशेष रूप से चिंतित हैं कि संकट का समाधान खोजने के लिए दुनिया में तेजी से कार्य करने और नेतृत्व करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप अमेरिकी पीक के साथ वैश्विक पेकिंग क्रम में उलटफेर हो सकता है, जो चीन के लिए अपनी प्रमुख स्थिति खो देता है।
- राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे इस प्रकार कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए खोज के साथ अनियमित रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं।

निष्कर्ष –

- व्यावसायिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर सीमाओं और प्रतिबंधों को बंद करने जैसे कदम इस सरल कारण से समझ में आते हैं कि शासन की प्रभावी संरचना बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सीमाओं द्वारा परिचालित है। राज्य अधिकारियों द्वारा कानून बनाए और लागू किए जाते हैं।
- वैश्विक शासन की सभी बातों के बावजूद, प्रादेशिक निकायों, चाहे क्षेत्रीय हों या वैश्विक, में मनुष्यों के दैनिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए बहुत सीमित क्षमताएं हैं।
- कोविड–19 महामारी भारत को बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का एक मजबूत और विश्वसनीय चौंपियन बनने और एक ऐसी दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है जो आडम्बर है।
- इसके लिए प्रेरणा अपनी आजादी के बाद से भारत की अच्छी विदेश नीति से आना चाहिए।

सार्क बैठक

समाचार –

- यह बैठक 15 मार्च 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, इस क्षेत्र को स्थिर करने के लिए इसकी मुखर अभिव्यक्ति के रूप में, 8 देशों के नेताओं के बीच जिसमें भारत ने 10 मिलियन अमरीकी डालर के पेशकश की घोषणा की।
- कोविड–19 के प्रकोप के इस क्षण में SAARC (साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन) की मदद के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम (डॉक्टरों, विशेषज्ञों, परीक्षण उपकरण और परिचर बुनियादी ढांचे) का गठन।
- भारत ने कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के सदस्य देशों की मदद के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म स्थापित करने का निर्णय लिया है।

- इस निर्णय से क्षेत्र के आठ देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के एक आभासी सम्मेलन के दौरान अवगत कराया गया है।
- नेपाल ने सार्क कोविड–19 आपातकालीन कोष के लिए 10 करोड़ नेपाली रुपये के योगदान की भी घोषणा की है।
- आभासी शिखर सम्मेलन 2014 के बाद पहली उच्च स्तरीय सार्क बैठक है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कॉरपोरेट निकायों, फाउंडेशन और यूएन फाउंडेशन की मदद से कोविड–19 सॉलिडैरिटी रिस्पॉन्स फंड का भी गठन किया है।
- दक्षिण एशिया ने विश्व स्तर की तुलना में बहुत कम मामले है, लेकिन इसकी अधिक जनसंख्या घनत्व को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रकोप से कहीं अधिक हताहत होंगे।
- अफगानिस्तान और पाकिस्तान में विशिष्ट चुनौतियां हैं क्योंकि वे ईरान के साथ लंबी सीमाओं को साझा करते हैं, जो चीन और इटली के बाद, वायरस के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है।
- भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका पर्यटन पर प्रभाव के बारे में चिंता करते हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य आधार है।
- अन्य चिंताएं अंडर–रिपोर्टिंग के बारे में हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया के बहुत से लोगों का परीक्षण किया जा रहा है, और क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं इसका सामना कर सकती हैं। यह देखा जाना बाकी है कि सार्क देश वायरस से निपटने के लिए कितना निकट सहयोग करेंगे।

दक्षिण एशिया की भूमिका –

- दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है। सार्क देशों के व्यापार का 5 प्रतिशत से भी कम है।
- एक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर 2006 में सहमति व्यक्त की गई थी, जो वास्तव में एक कल्पना है।
- नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाला 19 वां सार्क सम्मेलन, उरी में आतंकवादियों के हमले के बाद स्थगित कर दिया गया था। तब से, भारत, जो कि सबसे बड़ा सार्क देश है, ने माना है कि समूहीकरण में अंतर्निहित समस्याएं हैं और इसके बजाय सार्क के विकल्प के रूप में बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) के लिए बंगाल की खाड़ी जैसे नए संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।
- SAARC में कुछ समय के लिए गति नहीं थी, इसके बाद BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) और BIMSTEC और BCIM (बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार) शुरू किए गए।

सार्क –

- यह 1980 के दशक में आशा के क्षण में पैदा हुआ था। इस विचार का संकेत बांग्लादेश के जनरल जिया उर रहमान ने दिया, जिन्होंने कई अन्य नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और क्षेत्र के देशों की राजधानियों में विशेष दूत भेजे।
- ढाका की दृढ़ता के कारण 1985 में इस क्षेत्र के 7 नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। अफगानिस्तान 2007 में शामिल हो गया।

सार्क का धुँधला होना –

- सार्क की विफलता के कारणों को भी कई बार बताया गया है। सार्क आतंकवाद के एक क्षेत्रीय खतरे से निपटने में सफल नहीं रहा है। जाहिर है, अधिकांश छोटे राज्यों और बाहरी खिलाड़ियों का मानना है कि भारतीय पाकिस्तान संघर्ष ने सार्क को कमतर कर दिया है।
- सार्क में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन चूंकि संगठन सभी प्रमुख निर्णयों के लिए सर्वसम्मति के सिद्धांत पर निर्भर करता है, पाकिस्तान ने अक्सर सबसे कमजोर पहल की भी अवहेलना की है, ऐसा नहीं है कि यह भारत को एक लाभ देता है – भारत द्वारा सापेक्ष लाभ पाकिस्तान के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं पूर्ण लाभ की तुलना में यह स्वयं के लिए सुरक्षित है।
- भारत के लिए, विदेश नीति के एक साधन के रूप में पाकिस्तान के आतंक के उपयोग ने सामान्य व्यापार को असंभव बना दिया है।
- भारत और पाकिस्तान के दो सबसे बड़े सदस्यों के बीच खराब संबंधों को देखते हुए सार्क का यह हालिया पुनरुत्थान आसान नहीं होगा। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि नई दिल्ली महामारी से निपटने के लिए राजनीति को अलग रखने की कोशिश करने के लिए तैयार दिख रही है।

विश्लेषण –

- साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (सार्क) ने 15 मार्च 2020 से अचानक जीवन का नया पट्टा प्राप्त कर लिया है।
- यह 'आउट–ऑफ–द–बॉक्स' सोच का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि दुनिया कोविड–19 कोरोनावायरस महामारी का सामना कर रही है।
- भारतीय पीएम द्वारा एक जवाबी सहज पहल के माध्यम से, SAARC 'आभासी मंच' बन गया है, जिसके माध्यम से क्षेत्र के 8 देशों के नेताओं ने लोगों के लिए अनजाने सबसे बड़े तात्कालिक खतरे का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
- इस हालिया सार्क बैठक की सफलता काफी हद तक भारत – क्षेत्र की प्रमुख शक्ति, पर निर्भर करेगी।
- नई दिल्ली यह प्रदर्शित करती है कि उसमें क्षमता है, संस्थागत रूप से राजनीतिक इच्छाशक्ति और क्षेत्र में एक पारस्परिक रूप से लाभकारी सहकारी शासन का नेतृत्व करने के लिए, पाकिस्तान की 'कर्कश' व्यवहार सार्क के लिए मामूली हो जाएगा। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतकार इसे 'हेमेजोनिक स्थिरता' के कार्य के रूप में देखते हैं।
- इस हालिया बैठक में भारत द्वारा घोषित प्रारंभिक कदम प्रशंसनीय हैं, जिसमें सार्क देशों के लिए एक कोविड–19 आपातकालीन कोष स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
- भारत ने सभी सदस्य देशों के लिए परीक्षण किट और अन्य उपकरणों के साथ, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम का भी प्रस्ताव दिया है।
- भारत ने वायरस वाहक और उनसे संपर्क करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए एक एकीकृत रोग निगरानी पोर्टल की स्थापना की है। भारत ने इसे सदस्य देशों के साथ साझा करने की पेशकश की है।

आगे की राह –

- व्यक्तिगत देशों को विकसित नहीं किया जा सकता है क्योंकि हम वैश्वीकरण के युग में हैं। आर्थिक एकीकरण और विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक और शैक्षिक विकास और एकीकरण का समर्थन करना कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो भारत कर सकता है।
- भारत द्वारा शुरू की गई बैठक का स्वागत किया गया। बांग्लादेश के लोगों ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। इसके अलावा, इन सभी देशों में समस्या को लेकर चिंता है। यह निश्चित रूप से तनाव को कम करेगा और मजबूत सहयोग पैदा करेगा।
- भारत को यह स्थापित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस एक मात्र घटना नहीं थी, बल्कि हमारे सामान्य भविष्य के लिए सहकारी तंत्र के माध्यम से इस क्षेत्र को स्थिर करने की अपनी नई इच्छा की मुखर अभिव्यक्ति थी।
- पाकिस्तान को यह महसूस करना चाहिए कि क्षेत्र का भविष्य भारत के सहयोग से है। भारत ही नहीं, अफगानिस्तान सरकार को भी पाकिस्तान से निपटने का बहुत कड़वा अनुभव है क्योंकि वे कहते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहे हैं। फिर भी, पाकिस्तान एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और इसीलिए यह आवश्यक है कि पाकिस्तान बोर्ड पर आए।
- यह भारत के लिए इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ने और हमारे साझा भाग्य के लिए एक स्थायी साझेदारी को सुरक्षित करने के लिए के लिए एक दुर्लभ अवसर का क्षण है।

सामान्य अध्ययन III

(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव–विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रबंधन)

चावल के पौधों में मीथेन शमन के लिए सक्षम बैक्टीरिया

समाचार –

- हाल ही में, पुणे के अघारकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई) के वैज्ञानिकों ने 45 विभिन्न प्रकार के मेथनोट्रोफिक बैक्टीरिया को अलग किया है।
- एआरआई विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- जो उपभेद पाए गए हैं वे चावल के पौधों से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम हैं।
- मेथेनोट्रोफ्स चयापचय करते हैं और मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं।
- वे प्रभावी रूप से मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, जो कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) है।

- कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मिथेन 26 गुना अधिक शक्तिशाली है।
- इससे चावल में मीथेन शमन के लिए माइक्रोबियल इन्ऑक्यूलेंट्स का विकास हो सकता है।
- एआरआई टीम ने पहली स्वदेशी मेथनोट्रोफ संस्कृति बनाई है।
- उन्होंने पश्चिमी और दक्षिणी भारत से स्वदेशी मेथनोट्रोफ को अलग किया।
- पृथक स्वदेशी मेथनोट्रोफ मुख्यतः चावल के खेत की मिट्टी और ताजे पानी कीचड़ से है।
- पश्चिमी भारत में चावल के खेतों से दो नए जेनेरा और छह उपन्यास प्रजातियां मेथनोट्रोफ का दस्तावेजीकरण किया गया है।
- पॉट परीक्षणों में, चावल के पौधों में कुछ उपभेदों को जैव–इनोकुलेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

चावल के खेत किस तरह से मीथेन उत्पन्न करते हैं?

- चावल के खेतों में, मेथनोट्रोफ जड़ों या मिट्टी–पानी इंटरफेस के पास सक्रिय होते हैं।
- चावल के खेत मानव निर्मित आर्द्रभूमि हैं और काफी अवधि के लिए जल से भरे होते हैं।
- कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षरण के परिणामस्वरूप मीथेन की उत्पत्ति होती है।
- चावल के क्षेत्र वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में लगभग 10: योगदान करते हैं।

मेथनोट्रोफ्स का अनुप्रयोग –

- मीथेन शमन अध्ययनों के अलावा, मीथेनोट्रॉफ्स का उपयोग मीथेन मूल्य संवर्धन (वेलोराइजेशन) अध्ययनों में भी किया जा सकता है।
- कचरे से उत्पन्न बायो–मीथेन का उपयोग मेथनोट्रोफ द्वारा किया जा सकता है और इसे एकल–सेल प्रोटीन, कैरोटेनॉइड, बायोडीजल, और जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- टीम आगे चलकर अलग–अलग मेथनोट्रोफ से मीथेन वैलेरीकरण अध्ययन पर काम कर रही है।
- इस तरह के अध्ययन से जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है, विशेष रूप से मानवजनित या मानव निर्मित उत्सर्जन।

SIRT1 की भूमिका

समाचार –

- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई (टीआईएफआर) के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है जिसमें पता चला है कि ग्लूकोज सीधे SIRT1 के कार्य को नियंत्रित करता है।
- शोध को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की कार्यवाही में प्रकाशित किया गया है।
- इस नियंत्रण की कमी या अनुपस्थिति एक मधुमेह जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, जबकि SIRT1 के अधिक खाने और निरंतर निम्न स्तर से मोटापा और बढ़ती उम्र की समस्याएँ हो सकती है।
- SIRT1 नामक एक एंजाइम चयापचय गतिविधियों और उम्र बढ़ने को भी को नियंत्रित करता है। SIRT1 का अर्थ sirtuin होता है।
- शरीर में उच्च कैलोरी सामग्री से संबंधित कई बीमारियां हैं, जैसे चयापचय संबंधी विकार।
- मेटाबोलिक रोग मनुष्यों में भी गलत फीडिंग आहार से जुड़े होते हैं।
- प्रत्येक जीव को खिलाने के लिए विकसित किया गया है और फिर वैकल्पिक रूप से तेजी से, इसलिए इस चक्र को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।
- यह चक्र, जिसे फीड–फास्ट चक्र के रूप में जाना जाता है, एक बुनियादी पैटर्न है और इससे संबंधित चयापचय को काफी हद तक जिगर द्वारा ध्यान रखा जाता है।

ग्लूकोज की भूमिका –

- ग्लूकोज एक प्रोटीन SIRT1 के कार्यों को नियंत्रित करता है जो बदले में प्रतिदिन फीड–फास्ट चक्र बनाए रखता है और दीर्घायु के साथ भी जुड़ा हुआ है।
- सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों में, SIRT1 प्रोटीन का स्तर उपवास के दौरान और फीड के दौरान कम होने के लिए जाना जाता है, जो ग्लूकोज और वसा चयापचय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- ग्लूकोज खिलाया जाने की स्थिति में SIRT1 की गतिविधि पर एक जांच डालता है।
- इस जांच की अनुपस्थिति में, SIRT1 गतिविधि बढ़ जाती है और उपवास की अवस्था में हाइपरग्लाइकेमिया के परिणामस्वरूप, मधुमेह की स्थिति की नकल करता है।

- लगातार भोजन या उच्च कैलोरी सेवन जो SIRT1 (ग्लूकोज द्वारा) के स्तर में निरंतर कमी की ओर जाता है, यह उम्र बढ़ने और मोटापे से जुड़ा हुआ है।
- दूसरे शब्दों में, इस अध्ययन से पता चलता है कि इस दीर्घायु कारक के अति–सक्रियण और कम–सक्रियण दोनों बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

आगे को राह –

- यह अध्ययन इस संशोधन को विनियमित करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो जीवनशैली संबंधी विकारों और बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों से निपटने में लाभदायक हो सकता है।

स्टार्च–आधारित हेमोस्टैट सामग्री

समाचार –

- नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (INST) के वैज्ञानिकों ने एक स्टार्च–आधारित हेमोस्टैट सामग्री विकसित की है।
- यह सामग्री दुर्घटनाओं के दौरान तेजी से खून की कमी को रोकती है।
- INST विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- गंभीर चोट लगने के बाद, कुछ चुनौतियाँ जीवन के लिए खतरा बनने वाले रक्तस्राव को रोकने की तुलना में अधिक आवश्यक हैं।
- हेमोस्टैट सामग्री रक्त में प्राकृतिक थक्के के कारकों को केंद्रित करके एक्सेल द्रव को अवशोषित करती है जो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- हालांकि, जब गैर–बायोडिग्रेडेबल सामग्री हटा दी जाती है, तो रक्तस्राव फिर से शुरू हो सकता है।
- उत्पाद के माइक्रोपार्टिकल्स, जिन्हें कैल्शियम–संशोधित कार्बोक्सिमिथाइल–स्टार्च के रूप में जाना जाता है।
- सूक्ष्म रूप से प्राकृतिक स्टार्च को माइक्रोप्रोटिकल्स बनाने के लिए संशोधित करके, एक आसन्न जेल बनाते हैं जो घाव पर रह सकते हैं जब तक कि धीरे–धीरे हीलिंग विघटित न हो जाए।
- स्टार्च पर कुछ रासायनिक हाइड्रॉक्सिल समूहों को कार्बोक्सिमिथाइल समूहों में संशोधित करके माइक्रोप्रर्टल्स तैयार किए जाते हैं।
- ऐसा करते समय माइक्रोपार्टिकल्स भी लाभकारी कैल्शियम आयनों को शामिल करते हैं।
- कैल्शियम आयन लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करते हैं और एक स्थिर रक्त का थक्का बनाने वाले फाइब्रिन प्रोटीन नेटवर्क को उत्पन्न करने की उनकी सक्रियता को बढ़ाते हैं।
- यह संशोधन पानी के साथ अणुओं की क्रिया करने की क्षमता को बढ़ाता है।
- यह रक्त से तरल पदार्थ को अवशोषित करने की इसकी प्रभावशाली क्षमता का आधार है और इसलिए थक्के के कारकों को केंद्रित करता है।

इस विकास का महत्व –

- वर्तमान में, कोई एकल हेमोस्टैटिक एजेंट मौजूद नहीं है जो सभी स्थितियों में काम कर सकता है। वर्तमान हेमोस्टैट सामग्री बहुत महंगी है और ज्यादातर विकसित देशों में उपलब्ध है।
- कुछ स्टार्च–आधारित बायोडिग्रेडेबल विकल्प वर्तमान में उपलब्ध हैं।
- लेकिन वे अपने अपेक्षाकृत धीमी गति से तरल अवशोषण और घायल ऊतकों को खराब आसंजन द्वारा सीमित हैं।
- इसके अलावा, कठोर होने के नाते, अपूर्ण बायोकंपैटिबिलिटी वर्तमान में उपलब्ध विकल्पों में समस्याएँ हैं।
- सामग्री का प्रारंभिक चरण विकास संभवतः जीवन रक्षक और सस्ती उत्पाद है। यह दुनिया भर में कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक यथार्थवादी समाधान होगा।
- उत्पाद में अवशोषण क्षमता, बेहतर अवशोषण, सस्ती, बायोकम्पैटिबल और बायोडिग्रेडेबल जैसे क्षेत्रों वृद्धि हुई है।
- वास्तविक घावों के साथ जानवरों के अध्ययन में, एक मिनट से भी कम समय में मध्यम से भारी रक्त प्रवाह को रोक दिया गया था।
- जानवरों के अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि सामग्री गैर विषैली है और इसकी जैवअवक्रमणशीलता की पुष्टि की है।

आगे की राह –

- ये उत्साहजनक परिणाम हमारे संशोधित स्टार्च माईक्रोपार्टिकल्स नैदानिक अनुप्रयोगों में आगे की खोज के लिए एक बहुत ही आशाजनक उम्मीदवार हैं।

गर्भनाल रक्त की बैंकिंग

समाचार –

- पूना नागरिक डॉक्टर फोरम (PCDF) वाणिज्यिक गर्भनाल रक्त बैंकिंग पर विश्वास को दूर करता है। इसने स्टेम सेल बैंकिंग कंपनियों द्वारा भावनात्मक विपणन रणनीति के शिकार होने के खिलाफ माता–पिता को चेतावनी दी।
- PCDF एक निकाय है जिसका उद्देश्य नागरिकों और डॉक्टरों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना है, और नैतिक तर्कसंगत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना है।
- गर्भनाल रक्त बैंकिंग में गर्भनाल से रक्त को लेना और भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित करना शामिल है।
- गर्भनाल रक्त स्टेम सेल का एक समृद्ध स्रोत है।
- यह गर्भनाल में बच्चे के जन्म के बाद छोड़े गए रक्त और प्लेसेंटा है।
- निजी कंपनियां इस क्षेत्र में कोशिकाओं को स्टोर और संरक्षित करने के लिए 50,000 रूपये से लेकर 1 लाख रूपयों तक ले रही हैं।
- जैसा कि, इसमें हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल होते हैं जिनका उपयोग कुछ प्रकार के रोगों के इलाज के लिए किया जा सकता है।
- ये कोशिकाएँ शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं में परिपक्व हो सकती हैं।
- विश्व स्तर पर, हेमटापोएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण के लिए हेमटोलॉजिकल कैंसर और विकारों के स्रोत के रूप में कॉर्ड रक्त बैंकिंग की सिफारिश की जाती है। अन्य सभी स्थितियों के लिए, स्टेम कोशिकाओं के स्रोत के रूप में गर्भनाल रक्त का उपयोग अभी तक स्थापित नहीं है।

मुद्दा –

- पिछले एक दशक में, स्टेम सेल बैंकिंग को आक्रामक रूप से विपणन किया गया है। यहां तक कि इसका उपयोग अभी भी प्रायोगिक चरणों में है, लेकिन ये कंपनियां माता–पिता से कोशिकाओं को संरक्षित करने के लिए भारी शुल्क लेती हैं।
- यह केवल भावनात्मक विपणन द्वारा है कि कंपनियां कई वर्षों के लिए माता–पिता को कोशिकाओं को बैंक करने के लिए मनाती हैं।
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (प्ड्ड) वाणिज्यिक स्टेम सेल बैंकिंग की सिफारिश नहीं करता है।
- चूंकि भविष्य में आत्म–उपयोग के लिए गर्भनाल रक्त के संरक्षण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।
- यह प्रथा नैतिक और सामाजिक सरोकारों को जन्म देती है।
- गर्भनाल रक्त का निजी भंडारण उचित है जब परिवार में एक बड़ा बच्चा है, जो इन कोशिकाओं के साथ इलाज योग्य स्थिति में है और मां अगले बच्चे की उम्मीद कर रही है।
- अन्य स्थितियों में, माता–पिता को इस समय बैंकिंग की सीमाओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।
- इस तरह के दिशानिर्देशों के बावजूद, डॉक्टरों और स्टेम सेल बैंकिंग कंपनियों की सांठगांठ पनपती है और इन कंपनियों को अभिभावकों के डेटा तक पहुंच मिलती है।
- सुधारकों का कहना है कि स्टेम सेल बैंकिंग कंपनियां डिलीवरी से पहले अपने संभावित ग्राहकों से संपर्क करना शुरू कर देती हैं और प्रतिस्पर्धी पैकेज पेश करती हैं।

दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का प्रभाव

समाचार –

- दुनिया भर में कोविड–19 के वैश्विक प्रकोप के कारण, उद्योगों का एक विविध सेट प्रभावित हुआ है। प्रमुख प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दिखाई देता है। जो आगे चलकर मंदी में बदल सकता है।

अर्थव्यवस्था क्यों प्रभावित होनी चाहिए? –

- बाहरी दुनिया के साथ कम जुड़ाव। काम, शिक्षा, फिटनेस और मनोरंजन से बचने का मतलब है कि बहुत कम आर्थिक गतिविधि होगी।
- व्यवसाय उत्पादों को बनाने के लिए घटकों की बाधित आपूर्ति की चुनौती का सामना कर रहे हैं।
- व्यवसायों को अपने कुछ कारखानों को अस्थायी रूप से बंद करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
- कार्यबल के बड़े हिस्से का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसे अलग किया जाना है।
- 4 चैनलों के माध्यम से कोविड–19 के आर्थिक प्रभाव का पता लगाया जा सकता है – बाहरी मांग, घरेलु मांग, आपूर्ति में व्यवधान, और वित्तीय और बाजार की गड़बड़ी।

- **बाहरी घरेलू मांग** – जैसे–जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था धीमी होगी, माल के आयात की उनकी मांग कम होती जाएगी। न केवल माल निर्यात, बल्कि सेवा निर्यात को भी नुकसान होगा। आईटी उद्योग, यात्रा और परिवहन और होटल उद्योग प्रभावित होंगे। बाहरी क्षेत्र में एकमात्र रिडीमिंग सुविधा तेल की कीमतों में गिरावट है। भारत के तेल आयात बिल में भारी कमी आएगी। लेकिन यह तेल निर्यातक देशों को प्रभावित करेगा जो भारतीय श्रम को अवशोषित करते हैं। प्रेषण धीमा हो सकता है। गैर–स्थायी कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो चुकी है। इनपुट आयात करने या प्राप्त करने में असमर्थता के कारण आपूर्ति में व्यवधान हो सकता है। घरेलू आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हो सकती है क्योंकि माल की अंतर–राज्य आवाजाही भी धीमी हो गई है।
- **वित्तीय बाजार के मुद्द** – भारत में शेयर बाजार ध्वस्त हो गया है। इससे धन प्रभावित होता है और विशेष रूप से उच्च धन धारकों के व्यवहार पर प्रभाव पड़ेगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बड़ी घबराहट दिखाई है। डॉलर के संदर्भ में रुपये का मूल्य भी गिर गया है। सरकार को मिलने वाले दो प्रमुख उपकरण मौद्रिक नीति और राजकोषीय क्रियाएं हैं। इस तरह की स्थिति में मौद्रिक नीति केवल तरलता और ऋण की अधिक से अधिक मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर सकती है। लेकिन नीतिगत दर में कोई भारी कमी से बचतकर्ताओं पर भी असर पड़ सकता है। ब्याज एक दोधारी तलवार है। RBI को नीतिगत दर में कटौती करने की आवश्यकता है। बैंकों को ऋण देने के लिए कुछ निश्चित नियामक विनियमावली की आवश्यकता होती है। गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की मान्यता के बारे में नियमों में कोई ढील पूरे व्यावसायिक क्षेत्र में होनी चाहिए। राजकोषीय कार्यों की प्रमुख भूमिका होती है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अधिक हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियों में वायरस से संबंधित मंदी के कारण राजस्व में और गिरावट आने की संभावना है। वायरस से लड़ना और उसे नीचे लाना है। परीक्षण और रोगियों की देखभाल करने के लिए सभी व्यय किए जाने चाहिए। इसलिए, पहली प्राथमिकता सभी स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना है, जिसमें सहायक उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइटर और परीक्षणों के लिए सामग्री की आपूर्ति शामिल है। चुनौती न केवल राजकोषीय है, बल्कि संगठनात्मक भी है।
- **नौकरी क्षेत्र** – दैनिक वेतन भोगी, अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार से बाहर कर दिया गया है। प्रवासी मजदूर घर वापस चले गए हैं। इस मामले में, व्यावसायिक इकाइयों को अस्थायी कर्मचारियों को अपने रोल पर रखना चाहिए और उन्हें न्यूनतम आय प्रदान करनी चाहिए। आतिथ्य और यात्रा जैसे क्षेत्रों के मामले में, सरकार सरकार को देय राशि के भुगतान को स्थगित करने के माध्यम से राहत का विस्तार कर सकती है। इस समय जब वायरस से निपटने के लिए सरकार की सभी ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है, सार्वभौमिक नकदी हस्तांतरण की एक प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयासों का एक मोड़ होगा। सरकार पर बोझ प्रति व्यक्ति नकद हस्तांतरण की अवधि और अवधि की अवधि पर निर्भर करेगा।

भविष्यवाणियां –

- वर्तमान भविष्यवाणियों के साथ समस्या यह है कि यह अज्ञात है कि वायरस कितनी देर तक शक्तिशाली रहेगा। रबोबैंक ने 2020 के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि 1.6 प्रतिशत होने की भविष्यवाणी की। यह आंकड़ा पिछले साल 2.9 प्रतिशत था।
- मार्च 2020 में, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस ने भविष्यवाणी की थी कि वैश्विक आर्थिक विकास 1 प्रतिशत से कम हो सकता है। ओपेक क्लब और रूस स्थिर तेल की कीमतों को बनाए रखने के लिए उत्पादन समझौतों पर आ गए, इससे पहले भी यह था।
- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने कहा कि वायरस का प्रकोप इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक खर्च कर सकता है। महामारी कुछ देशों में मंदी का कारण बन सकती है, जिसके कारण वैश्विक आर्थिक विकास 2.5 प्रतिशत से कम हो सकती है। (जब अर्थव्यवस्था में संकुचन के लगातार दो तिमाहियों का पता चलता है)
- यह अनुमान लगाया गया है कि कोविड–19 का प्रकोप और 21 दिन की लॉकडाउन 2020 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी को 10.33 लाख करोड़ रुपये तक कम कर देगी, जिससे वित्त वर्ष 2019 के लिए जीडीपी की वृद्धि 4.8 प्रतिशत तक गिर जाएगी और वित वर्ष 2020–21 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत संकुचन होगा।
- रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कोविड–19 के प्रसार के कारण, अगले वित्त वर्ष के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को 5.2 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तक कम कर दिया है।

वैश्विक परिदृश्य –

- विश्व स्तर पर शेयर बाजारों में गिरावट आई है।
- वैश्विक मंदी और ऊर्जा की मांग में गिरावट की आशंका के कारण कच्चे तेल की कीमतें भी घटने लगीं।
- दुनिया के बड़े हिस्से में यात्रा और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

भारत में कौन से उद्योग प्रभावित हैं?

- ऐसा कोई उद्योग नहीं है जिसने प्रभाव का अनुभव किया हो। जब वुहान में बीमारी के उपरिकेंद्र के साथ चीन, अपने घुटनों पर आया था, तो भारतीय फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और मोबाइल फोन उद्योग, उदाहरण के लिए, तुरंत लड़खड़ा गए। भारत उन क्षेत्रों के लिए घटकों की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर करता है जो ये क्षेत्र बनाते हैं।
- भारतीय फार्मा उद्योग, जो यहां दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक 70 प्रतिशत कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर करता है, फरवरी 2020 तक इनपुट लागत में 50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
- कीटनाशक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है क्योंकि निर्माता कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं।
- वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के लिए यह आवश्यक है कि या तो भारतीय उत्पादन में वृद्धि हो, जहाँ विदेश में आपूर्ति के संभावित या वैकल्पिक स्रोत मिलें। लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि सस्ते चीनी सामानों से पिछले 20 वर्षों में उत्पादन की बहुत सारी वैकल्पिक संभावनाएं बाधित हुई हैं, ऐसे उत्पादकों को खोजना जो उत्पादन को तेजी से बढ़ा सकते हैं, आसान नहीं है। अगर भारत में आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत मिलते हैं, तो भी उनकी कीमतें अधिक होंगी, इसलिए मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी।
- यह मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति वैश्विक मांग में गिरावट और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के समान होगी, जो ऊर्जा के मामले में देखी जा रही है।
- मंदी के परिदृश्य में, मुद्रास्फीति में गिरावट के बावजूद आय में कमी और मांग में कमी है।
- स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण पर व्यय बढ़ेगा, लेकिन मंदी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
- छोटे उत्पादकों पर प्रभाव इस तथ्य के कारण तेज होने की संभावना है कि उनके पास छोटी कार्यशील पूंजी है।
- मांग में गिरावट के कारण, उन्होंने इन्वेंट्री को छोड़ दिया गया और उन्हें मजदूरी का भुगतान भी करना पड़ा। इससे उनकी कार्यशील पूंजी समाप्त हो जाती है। यदि उनकी इकाइयाँ कुछ महीनों के लिए भी बंद हो जाती हैं, तो उन्हें वापस जीवन में लाना मुश्किल हो जाता है।
- वित्तीय क्षेत्र उनकी मांग को पूरा करने के लिए बहुत अधिक नहीं है और इसलिए, उन्हें निजी निधियों के अधिक महंगे स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है।
- इसके अलावा, जैसा कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, भारत में पहले से ही पर्याप्त एनपीए बैंकों और एनबीएफसी में हैं। RBI ने पहले ही गिरते हुए व्यापार और उपभोक्ता विश्वास और अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों में क्षमता उपयोग में गिरावट की सूचना दी है। इन कारकों को वायरस से संबंधित प्रभाव, आगे के डेंटिंग निवेश द्वारा बढ़ाया जा रहा है।
- गर्मी की शुरुआत के साथ वायरस के प्रसार की तीव्रता के बाद भी उपभोक्ता का विश्वास थोड़ी देर के लिए कम ही रहेगा।
- भविष्य के अनिश्चित होने पर लोग अधिक बचत करते हैं। इसलिए, मांग तुरंत बढ़ने की संभावना नहीं है।
- लॉकडाउन और कमी के डर के कारण, यह संभावना है कि लोग अपने घरों में अधिक नकदी और आवश्यक वस्तुएं रखेंगे।
- अधिक मुद्रा जारी करने के लिए केंद्रीय बैंकों को तैयार रहना होगा।
- उन्होंने ब्याज दरों में कमी की है, लेकिन वैश्विक मंदी के प्राथमिक कारण और स्टॉक मार्केट की अस्थिरता वायरस के प्रसार के बाद भावना में गिरावट के कारण कम प्रभाव होगा। यह एक चक्रीय मंदी नहीं है।
- मास मीडिया के माध्यम से मनोरंजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है। बहुत प्रसिद्ध आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है।
- सिनेमा हॉल का बंद होना। भारतीय फिल्म रिलीज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है।
- यात्रा को गंभीर चोट लगी है क्योंकि देशों ने अनावश्यक यात्रा को खत्म करने और लॉकडाउन मोड में जाने के लिए सलाह जारी की है।
- आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, निर्यात में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को रद्द करने के कारण कपड़ा और वस्त्र निर्यातकों ने प्रभाव महसूस करना शुरू कर दिया है।

- 11 देश भारत के 41 प्रतिशत सूती धागे के निर्यात को खरीदते हैं और इन देशों ने कोविड–19 मामलों की सूचना दी है।
- चीन, ईरान, कोरिया और वियतनाम के लिए सूती धागे के निर्यात में भारी गिरावट है।

निष्कर्ष –

- संक्षेप में, समस्या पूरी तरह से समझ में नहीं आई है लेकिन एक बड़े प्रभाव की आशंका बढ़ गई है।
- चीन से निकलने वाले आपूर्ति के झटके फैल गए हैं और उत्पादन पर प्रभाव के कारण, आय में कमी आ रही है, जिससे वैश्विक मंदी की मांग और खतरे में गिरावट आ रही है।
- भारत में गरीबों के अधिक प्रभावित होने की संभावना है।
- वर्तमान में, केवल अल्पावधि का अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन चूंकि अनिश्चितता बढ़ गई है, इसलिए सरकारों को लंबे समय में सबसे खराब अनुमान लगाने वाले राजकोषीय कदम उठाने होंगे।
- सरकार को सभी व्यावसायिक इकाइयों को सलाह देना चाहिए कि श्रमिकों को पीछे न रखें और श्रमिकों को बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ राहत प्रदान करें।
- तत्काल समस्या हल होने पर सभी गरीबों के लिए एक पूरक आय योजना के बारे में सोचा जा सकता है।
- बाढ़ या सूखे के समय प्रभावित लोगों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक चीजों का प्रावधान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- राजकोषीय घाटा काफी हद तक बढ़ने के लिए बाध्य है। उच्चतर उधार कार्यक्रम के लिए त्ठप् के समर्थन की आवश्यकता होगी, ब्याज दर को कम रखा जाना है।
- घाटे का मुद्रीकरण अपरिहार्य है। तरलता का मजबूत इंजेक्शन अगले साल के लिए समस्याओं को संग्रहीत करेगा।

केरल ने FRBM नियमों में छूट मांगी

समाचार –

- केरल 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाऊन सहित कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए उठाए गए व्यापक कदमों से आजीविका और समग्र आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव को कम करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने वाला सबसे पहले राज्यों में से एक बन गया।
- यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, तेलंगाना, और राजस्थान सहित कई राज्यों ने इस राह का पालन किया।

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज

- वित्त मंत्रालय द्वारा कमजोर वर्गों – किसानों, महिलाओं, निर्माण श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों के लिए 1.7 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से भी कम है।
- हाथ में मुद्दा सिर्फ जीडीपी के सापेक्ष पैकेज का आकार नहीं है, बल्कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मौद्रिक हस्तांतरण की तात्कालिकता का भी है, जिन्होंने न केवल अपनी नौकरी और आय खो दी है, बल्कि जिन्हें एक बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य डर का सामना करना पड़ता है।
- इसमें कमजोर वर्ग के विभिन्न वर्गों को शामिल किया गया है, जिसमें किसानों से लेकर महिला जन धन खाताधारक तक, संगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं, जिन्हें अब 50 लाख रुपये का एक बड़ा बीमा कवर मिलेगा।

विवरण –

- भारत की आबादी में गरीबों की एक उच्च हिस्सेदारी है, जिनमें से अधिकांश कई आर्थिक और सामाजिक अभावों से पीड़ित हैं।
- वे अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों से अपनी आजीविका कमाते हैं, जहां न तो नौकरी की सुरक्षा है और न ही आय प्रवाह की निरंतरता है। उनकी आजीविका को लॉकडाउन अवधि के माध्यम से संरक्षित किया जाना है।
- आपातकालीन राहत पैकेज की सहायता के लिए, राज्य रुपये के रूप में उधार लेने का प्रस्ताव करता है। अप्रैल में ही बाजार से 12,500 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री ने केंद्र से राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के तहत लचीलापन प्रदान करने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य का वित्त शेष वित्तीय में प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।

FRBM अधिनियम क्या है?

- अगस्त 2003 में अधिनियमित किया गया, यह कानून केंद्र सरकार को 'राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालीन मैक्रो–आर्थिक स्थिरता' में अंतर–सरकारी इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से है।

- दूसरे शब्दों में, देश के प्रशासकों की वर्तमान पीढ़ी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के वित्त का उनका प्रबंधन, भविष्य की पीढ़ियों को विरासत में मिले ऋण के उच्च स्तर के बोझ से दुखी नहीं करना चाहिए।
- जो बदले में समकालीन समाज के लिए एक स्थिर आर्थिक वातावरण प्रदान करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करेगा।
- इसे प्राप्त करने के लिए, 1. अधिनियम केंद्र सरकार के ऋण और घाटे पर सीमा की स्थापना की परिकल्पना करता है, 2. केंद्र सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता लाना और 3. मध्यम अवधि के ढांचे में राजकोषीय नीति का संचालन, करने की आवश्यकता है।
- अधिनियम को लागू करने के नियमों को जुलाई 2004 में अधिसूचित किया गया था।
- तब से केंद्र सरकार के हर बजट में मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण शामिल है।
- मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण तीन साल के क्षितिज पर वार्षिक राजस्व और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को निर्दिष्ट करता है।
- सरकार एक निर्धारित समय सीमा के भीतर राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत तक कम करने के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि के ग्लाइड पथ को वर्तनी के लिए बजट का उपयोग करती है।
- राजकोषीय घाटा 31 मार्च, 2009 से 31 मार्च, 2021 के प्रारंभिक लक्ष्य से स्थानांतरित हो गया, जब 2018 में नियमों में संशोधन किया गया था, और हाल ही में मार्च 2023 के लिए 3.1: के लक्ष्य की स्थापना के लिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य भी आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण हैं, 2004 में 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों को समान कानूनों के अधिनियमन के साथ ऋण राहत से जोड़ा।
- राज्यों ने अपने स्वयं के वित्तीय उत्तरदायित्व विधान को लागू किया है, जो अपने वार्षिक बजट घाटे पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) कैप का 3 प्रतिशत सेट करता है।

FRBM के तहत लचीलापन क्यों चाह रहा है केरल?

- केरल की वर्तमान राजकोषीय स्थिति का अर्थ है कि यह वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान लगभग 25,000 करोड़ रुपये उधार ले सकता है।
- यह देखते हुए कि यह नए वित्तीय वर्ष के पहले महीने में ऋण की आधी राशि जुटाने का प्रस्ताव करता है।
- राज्य सरकार इस बात से काफी चिंतित है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों के तहत कड़े उधार की सीमा शेष 11 महीनों में उसकी उधार लेने और खर्च करने की क्षमता को बाधित नहीं करना चाहिए।
- इस 11 महीने की अवधि में इसे न केवल अपने COVID–19 शमन उपायों को जारी रखने की आवश्यकता होगी, बल्कि राज्य के सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों के संचालन और महामारी से बाहर निकलने से संबंधित नियमित मामलों के लिए अन्य खर्चों को भी पूरा करना होगा।

FRBM की छूट कैसे काम करती है?

- कानून में इसे आमतौर पर 'एस्केप क्लॉज' कहा जाता है।
- अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत, केंद्र वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, कृषि का पतन, संरचनात्मक सुधार और कम से कम एक तिमाही के वास्तविक उत्पादन वृद्धि में पिछली चार तिमाहियों के औसत से तीन प्रतिशत नीचे गिरावट शामिल हैं।
- यह देखते हुए कि चल रही महामारी को राष्ट्रीय आपदा के रूप में माना जा सकता है – जिसके चल रहे लॉकडाउन के साथ मिलकर आर्थिक उत्पादन में एक गंभीर संकुचन का कारण बनने की संभावना है।
- वर्तमान परिस्थितियां केंद्र के और राज्यों के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य दोनों को निलंबित करने के लिए उपयुक्त होंगी।
- यह केरल सहित केंद्र सरकार और राज्यों दोनों को असाधारण परिस्थितियों को पूरा करने के लिए खर्च में बहुत अधिक वृद्धि करने की अनुमति देगा।

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक राहत पैकेज

- केंद्र, व्यक्तिगत जोखिम पर वायरस के प्रसार से लड़ने वाले सरकारी अस्पतालों में लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अगले तीन महीनों के लिए 50 लाख चिकित्सा बीमा कवर रुपये प्रदान करेगा।
- स्वास्थ्य कर्मचारियों में आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ता, सरकारी अस्पतालों, पैरामेडिक्स, नर्सों और डॉक्टरों में चिकित्सा स्वच्छता कार्यकर्ता शामिल हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आता है, उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से पहले से प्रदान किए गए 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा, अतिरिक्त पांच किलो गेहूं या चावल मुफ्त में मिलेगा।
- क्षेत्रीय वरीयताओं के अनुसार, एक किलो दाल एक घर को भी मुफ्त में प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।
- 60 वर्ष से अधिक के लगभग 3 करोड़ गरीब पेंशनरों, विधवाओं और विकलांगों को 1000 रुपये दो किस्तों में।
- जन धन योजना खातों को रखने वाली 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह।
- उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाले 8.3 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत मजदूरी 182 रुपये से 202 रूपये तक बढ़ाई जा रही है।
- केंद्र रुपये का उपयोग करने के लिए राज्यों को निर्देश दे रहा है। 31,000 पंजीकृत श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा 31,000 करोड़।
- राज्य मेडिकल स्क्रीनिंग, परीक्षण और उपचार के लिए जिला खनिज निधि के तहत उपलब्ध धन का उपयोग भी कर सकते हैं।
- 2000 रुपये की पहली किस्त पीएम–किसान आय सहायता योजना के तहत उन्हें वित्तीय वर्ष के पहले महीने अप्रैल में भुगतान किया जाएगा।
- 100 कर्मचारियों या उससे कम वाली छोटी कंपनियों के लिए, जिनमें से 90 प्रतिशत रुपये से कम कमाती हैं। 15,000 प्रति माह, केंद्र नियोक्ता और कर्मचारी योगदान (कुल 24 प्रतिशत) की लागत को अगले तीन महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में वहन करेगा। इससे 80 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे और 4 लाख प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रदान किए गए संपार्श्विक मुक्त ऋण को दोगुना कर 20 लाख रूपये, संभावित रूप से सात करोड़ परिवारों को लाभ।

यस बैंक संकट

समाचार –

- भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के चौथे सबसे बड़े निजी ऋणदाता बैंक को स्थगन के तहत रखा था।
- बैंक के ग्राहकों ने 3 अप्रैल 2020 तक प्रति दिन 50,000 रुपये से अधिक तथा असाधारण मामलों में अधिकतम 5 लाख रूपये के अधीन की नियमित निकासी नहीं की और यह स्थगन 16 मार्च 2020 को हटा दिया गया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मार्च 2020 को पुनर्निर्माण की योजना के मसौदे को मंजूरी दी। यह भारतीय स्टेट बैंक की पूंजी को 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निवेश करता है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सहित चार निजी क्षेत्र के ऋणदाता भी बैंक में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं।
- आरबीआई ने अपने बोर्ड को सौंप दिया और एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को नया प्रशासक नियुक्त किया।

येस बैंक संकट में कैसे पड़ा?

- यह वित्त वर्ष 2014 और 2019 के बीच 334 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एक ऋण की होड़ में चला गया।
- कई उधारकर्ताओं ने बैंक की सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति प्रतिशत को डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, जो कि 90 दिनों से अधिक के लिए ऋण अतिदेय का प्रतिशत है, जो कि सितंबर 2019 तक 7.39 प्रतिशत तक जूम किया, तुलनीय बैंकों में सबसे अधिक है।
- जबकि बुरा ऋण समाप्त हो गया, बैंक ने अपने मुनाफे में पर्याप्त प्रावधान नहीं किए। इसके प्रावधान तुलनीय बैंकों में सबसे कम थे।
- ग्राहकों ने बड़ी मात्रा में निकासी की, जिसके परिणामस्वरूप 2018–19 में क्रेडिट–जमा अनुपात 100 प्रतिशत को पार कर गया अर्थात् यह प्राप्ति की तुलना में अधिक उधार देता है।
- लोन की होड़ और उच्च एनपीए का मतलब खराब था एसेट्स पर यस बैंक के डूबते रिटर्न से लाभ हुआ।
- पिछले वर्ष बैंक के शेयर की कीमत में लगातार गिरावट आई।
- बैंक ने हाल के वर्षों में शासन के गंभीर मुद्दों और प्रथाओं का भी अनुभव किया है जिसके कारण बैंक में लगातार गिरावट आई है।

- यस बैंक की मुसीबतें बिल्कुल नई या अनोखी नहीं हैं और बढ़ते बुरे और घटिया कर्जों के साथ इसकी समस्याएं उधारकर्ता उद्योगों में अचल संपत्ति से लेकर बिजली और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में अंतर्निहित संकटों को दर्शाती हैं।
- अपने ऋणों को चुकाने के लिए कई कॉरपोरेट्स की निरंतर अक्षमता के परिणामस्वरूप कई इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही में उतरने का मतलब यह है कि उधारदाताओं को सबसे कठिन मारा पड़ी है।
- यस बैंक की परेशानी लंबे समय से जानी जाती थी। यह संरचनात्मक कमजोरियों की पहचान के बाद भी जल्दी और निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए आरबीआई की अनिच्छा है।
- यस बैंक के मामले में, जो मुद्दा एक बहस का मुद्दा बन गया है वह मसौदा संकल्प योजना में अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) पूंजी बांड का पूर्ण परिसमापन है।
- AT1 बॉन्ड्स को एक विशेष पूंजी बफर के रूप में BASEL-III द्वारा पेश किया गया था, जो कि एक बैंक के संचालन को जारी किए बिना और पूरी तरह से इक्विटी (तथाकथित जा रही चिंता पूंजी) को नष्ट किए बिना कुछ ट्रिगर बिंदुओं पर बुझाया जा सकता है।

यह ग्राहक को कैसे प्रभावित करेगा?

- निकासी पर प्रतिबंध ने न केवल यस बैंक खाता धारकों के लिए, बल्कि गैर–यस बैंक खाताधारकों के वित्तीय जीवन को भी बाधित कर दिया।
- यस बैंक के ग्राहक अपने खातों तक नहीं पहुंच सके और भुगतान नहीं कर पा रहे थे जैसे उनके ऋण ईएमआई, बीमा प्रीमियम, बिल भुगतान आदि।
- इसका उन ग्राहकों पर प्रभाव पड़ेगा जिनका वेतन खाता यस बैंक से जुड़ा हुआ है।
- ऋण को नवीनीकृत करने या देने और बैंक द्वारा निवेश करने की संभावना कम हो जाएगी।
- इससे पहले पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के लिए जमाकर्ताओं के लिए कैपिंग निकासी काफी खराब थी। यस बैंक के लिए एक ही सिद्धांत का उपयोग केवल निजी बैंकों में जमाकर्ताओं के विश्वास को खत्म करने के लिए काम करेगा।
- सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए, आरबीआई को खजाने को खुला रखने की आवश्यकता है, और धन तक पहुंच को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। जमाकर्ताओं को बताएं कि वे वह सब वापस ले सकते हैं जो वे चाहते हैं। जब एक बड़े, निजी बैंक के बारे में 2008 में आतंक था, तो सरकार ने यही किया था।
- यस बैंक जमाकर्ताओं के लिए कैपिंग आहरण दो विशिष्ट कारणों से मूर्खतापूर्ण है, खासकर जब अर्थव्यवस्था लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ लहरा रही है।
- पहला, लोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर रुख करेंगे, जो क्रेडिट से प्रभावित हैं, और दुसरा, निजी बैंकों को क्रेडिट की लागत को अधिक रखते हुए उच्च जमा दरों की पेशकश करने के लिए मजबूर किया जाएगा।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 के तहत, सरकार सीमाओं को शिथिल कर सकती है। बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास को वापस लाने के लिए, और नियामक के रूप में भारिबैं में विश्वास में सुधार के लिए, सरकार को तुरंत निकासी की सीमा बढ़ानी चाहिए, और इन मामलों में जल्द से जल्द सीमा को हटा देना चाहिए।

हिमालय पर भूजल स्तर बदलने के प्रभाव

समाचार –

- हाल ही में, भारतीय भू–विज्ञान संस्थान (IIG) के शोधकर्ताओं ने पाया है कि हिमालय की सीमा में परिवर्तन होता है जो मौसमी परिवर्तनों, भूजल, सामान्य और सामान्य कारणों के आधार पर बढ़ रहा है।
- IIG विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट (GRACE) डेटा का उपयोग हाइड्रोलॉजिकल द्रव्यमान की विविधताओं को निर्धारित करने के लिए किया गया था।
- 2002 में अमेरिका द्वारा लॉन्च किए गए GRACE के उपग्रह, महाद्वीपों पर पानी और बर्फ के भंडार में बदलाव की निगरानी करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को स्थलीय जल विज्ञान का अध्ययन करने में सक्षम बनाया गया है।
- संयुक्त जीपीएस और GRACE डेटा उपसतह पर्ची की दर में 12 प्रतिशत की कमी का सुझाव देता है।
- सबसिडेंस दर भूजल खपत से जुड़ा है।
- सबसर्फ स्लिप से तात्पर्य है कि पैर और लटकती दीवार के सापेक्ष गलती कितनी तेजी से फिसल रही है।
- स्लिप मेन हिमालयन थ्रस्ट (MHT) में होती है, जो हाइड्रोलॉजिकल विविधताओं और मानवीय गतिविधियों के कारण होती है, जिसके ऊपर संचित तनाव का आवधिक विमोचन होता है।

घटते भू–जल स्तर के कारण –

- पानी एक चिकनाई एजेंट के रूप में कार्य करता है और शुष्क मौसम में, क्षेत्र में गलती की दर कम हो जाती है।
- भूजल स्तर के अलावा हिमालय को प्रभावित करने वाले सामान्य कारण भी हैं।
- हिमालय की तलहटी और भारत–गंगा का मैदान डूब रहा है क्योंकि इसके समीपवर्ती क्षेत्र भूस्खलन आंदोलन या महाद्वीपीय बहाव से जुड़ी विवर्तनिक गतिविधि के कारण बढ़ रहे हैं।
- हिमालय में, हिमनदों के साथ–साथ मानसून की वर्षा में मौसमी पानी, क्रस्ट की विकृति और इससे जुड़ी भूकंपीयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- एक हाइड्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से बढ़ते हिमालय को देखने के लिए यह पहला अध्ययन है।

इस अध्ययन का महत्व –

- चूंकि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस अध्ययन से जलवायु पर जल विज्ञान के प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी।

जल संकट –

- अंटार्कटिका, आर्कटिक और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित दुनिया की प्रमुख मीठे पानी की आपूर्ति तेजी से कम हो रही है। अंतर्देशीय हिमनद और कई बड़ी झीलें भी दुनिया भर में लगभग हर जगह घट रही हैं।
- 'हिंदू कुश हिमालय के अनुसार आकलन रिपोर्ट – 2019', 2100 तक हिमालय अपने ग्लेशियरों के कम से कम दो–तिहाई खो सकता है, जो हिंदू–कुश–हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लगभग 250 मिलियन लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एक संयुक्त निगरानी रिपोर्ट, 'पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान – असमानताओं पर विशेष ध्यान' (2019) में देखा कि लगभग दो बिलियन लोग दुनिया में पीने के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं तक पहुंच नहीं है।
- वाटर एड (2019) की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पानी के बिगड़ते संकट के बावजूद, विश्व स्तर पर हम आज के पानी का छह गुना उपयोग करते हैं जैसा कि हमने 100 वर्ष पहले किया था और यह आंकड़ा हर वर्ष लगभग एक प्रतिशत बढ़ रहा है।
- 2019 में चेन्नई में जलाशयों के सूखने, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 'डे जीरो' पानी बंद करने से बचना, और दुर्लभ संसाधनों के संरक्षण के लिए रोम में पानी की राशनिंग, आगे स्पष्ट संकेत भेजती है कि आज दुनिया में पानी की स्थिति वास्तव में प्रत्येक गुजरते दिन के साथ बहुत बुरा हो रही है।

कारक जिम्मेदार

1. अनियोजित शहरीकरण
2. जलवायु परिवर्तन

- इस क्षेत्र में, प्राकृतिक जल निकायों (स्प्रिंग्स, तालाबों, झीलों, नहरों, और नदियों) का अतिक्रमण और क्षरण और पारंपरिक जल प्रणालियों (पत्थर के टोंटी, कुओं और स्थानीय जल टैंकों) के बढ़ते लुप्त होने के प्रमाण स्पष्ट हैं।
- हालांकि कुल हिंदू कुश हिमालयी आबादी का केवल 3 प्रतिशत बड़े शहरों में और 8 प्रतिशत छोटे शहरों में रहता है, लेकिन अनुमानों से पता चलता है कि 2050 तक 50 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरों में रह रही होगी, जो पानी की उपलब्धता पर जोर देगी।
- वर्तमान रुझानों के तहत, मांग–आपूर्ति अंतर 2050 तक दोगुना हो सकता है।

भारत का जल संकट –

- सकल घरेलू उत्पाद के प्रति यूनिट सबसे बड़े जल उपयोगकर्ताओं में से एक होने के नाते, भारत में लगभग चार प्रतिशत है।
- दुनिया के मीठे पानी के संसाधन और असंख्य छोटे और बड़े जल निकायों से संपन्न है। केंद्रीय जल आयोग ने 'स्पेस इनपुट्स का उपयोग करके भारत में जल उपलब्धता पर पुनर्मूल्यांकन' (2019) के बारे में अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वार्षिक उपयोग योग्य जल संसाधन प्रति वर्ष 1,123 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm) है, जिसमें सतही जल और भूजल की हिस्सेदारी क्रमशः 690 और 433 बीसीएम अनुमानित है।
- प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से देश में लगभग 305 बीसीएम की कुल भंडारण क्षमता बनाई गई है।

- जल संसाधनों के इतने मजबूत बैकअप के बावजूद, जल संसाधन मंत्रालय (2017) ने कहा है कि देश वास्तव में जल–तनावग्रस्त है, औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के साथ क्रमशः 2025 और 2050 तक 1,341 घन मीटर और 1,140 घन मीटर तक कम होने की संभावना है।
- पिछले वर्ष, नीति आयोग ने घोषणा की कि देश 'अपने इतिहास के सबसे बुरे जल संकट से पीड़ित है और लाखों लोगों की आजीविका खतरे में है'। गंभीर जल संकट भविष्यवाणी की तुलना में निश्चित रूप से बहुत पहले आ गया है।

निष्कर्ष

- यह संदेश विभिन्न रिपोर्टों से और स्पष्ट है कि दुनिया में जलसंकट है और जलवायु परिवर्तन इसे बदतर बना रहा है।
- जलवायु परिवर्तन का अधिकांश प्रभाव पानी की उपलब्धता के बदलते पैटर्न, सिकुड़ती नदियों और वर्षा के पैटर्न में बदलाव के साथ महसूस किया जा रहा है।
- हमें उपयोग की दक्षता में सुधार (और पुर्नउपयोग) और जल निकायों को बहाल करने के लिए आपूर्ति–अधिक जल मानसिकता से हटना चाहिए।
- यह समय है कि सभी राज्यों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया जाए और वर्षा जल संचयन संरचनाओं को लागू करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए।
- भूजल के लापरवाह दोहन की जाँच करने के लिए फसलों की खेती में सूक्ष्म सिंचाई, पानी की उचित आपूर्ति और पानी के उचित मूल्य निर्धारण जैसी पानी की बचत तकनीकों का व्यापक रूप से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। ऐसी फसलें जो कम पानी का उपभोग करती हैं, लेकिन अधिक उत्पादन देती हैं, उन्हें प्रोत्साहन योजनाओं द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और जल निकायों पर अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए एक नए कानून की तत्काल आवश्यकता है।
- जैसे–जैसे शहरी बाढ़ अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही है, भारत बाढ़ के पानी को संग्रहित करने वाले शहर के नीचे एक बड़े भूमिगत टैंक के निर्माण के जापान के प्रयासों का अच्छी तरह से अनुकरण कर सकता है और इसे बाद में जारी कर सकता है। जब तक इन जलवायु लचीला तंत्रों को जल्द से जल्द अपनाया नहीं जाता है, तब तक एक स्थायी जल भविष्य का निर्माण एक दूर की वास्तविकता बन जाएगा।

गंगोत्री ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन का संकेंद्रण

समाचार –

- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से कृषि और जंगल की आग के कारण गंगोत्री ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन की एकाग्रता लगभग दोगुनी हो गई है।
- वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ वर्षों से गंगोत्री ग्लेशियरों के रास्ते पर दो मौसम स्टेशनों के माध्यम से ब्लैक कार्बन की निगरानी की है – अर्थात् चिरबासा स्टेशन 3,600 मीटर की ऊंचाई पर, और भोजबासा स्टेशन 3,800 मीटर की ऊंचाई पर।
- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्यालय देहरादून (उत्तराखंड) में है।

मौसमी परिवर्तन –

- विभिन्न कारकों के कारण गर्मियों के महीनों में ब्लैक कार्बन की सांद्रता बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने 4.62 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक ब्लैक कार्बन की एक सीमा पाई है।
- गैर–गर्मी के महीनों में, एकाग्रता लगभग 2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक कम हो जाती है।
- गर्मियों के मौसम में ब्लैक कार्बन एकाग्रता में वृद्धि के कारण
- अप्रैल से जून तक की अवधि मुख्य रूप से पर्यटन से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियों के कारण ब्लैक कार्बन एकाग्रता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।
- साथ ही, जंगल की आग काला कार्बन सांद्रता बढ़ाने में योगदान करती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, फॉरेस्ट फायर एक्टिविटी आमतौर पर उत्तराखंड में फरवरी से जून तक रिपोर्ट की जाती है, जिसमें मई और जून में आग की घटनाओं में अधिकता होती है।
- मानव निर्मित के अलावा, राज्य में जंगल की आग के अन्य कारणों में बिजली गिरना, चट्टानों का गिरना और बंदरों द्वारा गलती से पत्थर फेंकना शामिल है जो जंगल की आग की चिंगारी पैदा करते हैं।
- उत्तराखंड के 2000 में बनने के बाद से वन क्षेत्र में 44,554 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है।

- अगस्त के दौरान सबसे कम ब्लैक कार्बन सांद्रता दर्ज की गई है, दिसंबर के बाद इन महीनों के दौरान पर्यटकों की गतिविधियों और जंगल की आग की घटनाओं के कारण होने की संभावना है।

ब्लैक कार्बन के स्थानीय स्रोत –

- जंगल की आग, घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन की लकड़ी जलना, फसल अवशेषों का मौसमी जलना और विकासात्मक गतिविधियाँ।
- स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्रोतों से प्रदूषण जो हिमालय क्षेत्र में जमा होते हैं और काले कार्बन की सांद्रता को बढ़ाते हैं।

संभावित प्रभाव –

- काले पदार्थ अधिक प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इन्फ्रा–रेड विकिरण का उत्सर्जन करते हैं जो तापमान को बढ़ाता है। इसलिए, जब उच्च हिमालय में ब्लैक कार्बन में वृद्धि होती है, तो यह हिमालय के ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने में योगदान देगा।
- लंबे समय में, उच्च हिमालयी की वायुमंडलीय संरचना में परिवर्तन मौसम के पैटर्न (जैसे बारिश और बर्फ वर्षा पैटर्न), और तदनुसार प्राकृतिक संसाधनों और हिमालयी समुदायों की सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करेगा।

आगे का राह –

- ब्लैक कार्बन (BC) एरोसोल अपने हल्के अवशोषित प्रकृति के कारण ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हिमालयी ग्लेशियर घाटियों जैसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में उनकी उपस्थिति गंभीर चिंता का विषय है और इस पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने की आवश्यकता है।

पशु संरक्षण सूचकांक 2020

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चौरिटी, विश्व पशु संरक्षण द्वारा निर्मित पशु संरक्षण सूचकांक (एपीआई) 2020 द्वारा जारी किया गया था।
- विश्व स्तर पर, भारत बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। 2014 में भारत में जानवरों पर परीक्षण किए गए कॉस्मेटिक उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत एशिया का पहला देश था।
- एपीआई का उद्देश्य यह दिखाना है कि जहां देश अच्छा कर रहे हैं, और जहां वे पशु कल्याण नीति और कानून पर कम हैं, इसलिए वे सुधार के लिए कदम उठा सकते हैं।
- सूचकांक अपनी नीति और कानून के अनुसार देशों को । (उच्चतम स्कोर) से ळ (सबसे कमजोर स्कोर) होने का दर्जा देता है।
- भारत ने सूचकांक में सी रैंकिंग प्राप्त की है, साथ ही न्यूजीलैंड, मैक्सिको, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में।
- हालांकि, पशु कल्याण से संबंधित कई डोमेन में सुधार की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले जानवर हैं।
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में क्रूरता संबंधी विचारों से छूट।
- इसके अलावा, खेत जानवरों के पालन के संबंध में नियमों की कमी है, विशेष रूप से अनियमित शहरी डेयरी प्रणालियों के साथ विशेष रूप से बहुत कल्याणकारी मानकों के साथ जल्दी से विकसित हो रहा है।

विश्लेषण –

- इस नए शोध से जंगली जानवरों और पशुओं के व्यापार और खेती में गरीब पशु कल्याण प्रथाओं का पता चलता है, जो वायरस के उत्परिवर्तन और प्रसार के लिए सही प्रजनन मैदान प्रदान करता है। यदि पशु कल्याण कानूनों में सुधार नहीं किया गया, तो बीमारी के प्रकोप का खतरा अधिक हो जाएगा।
- विश्व पशु संरक्षण ने 50 देशों की पशु कल्याण नीतियों और कानून का आकलन किया और स्पष्ट रूप से पर्याप्त पशु कल्याण कानूनों की कमी की पहचान की। यह जरूरी सुधारों पर जोर दे रहा है।
- सूचकांक देशों को अच्छे पशु कल्याण प्रथाओं जैसे कि जानवरों को स्वच्छ, स्वस्थ रखने और प्राकृतिक व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त जगह के साथ रखने में मदद करेगा।
- अधिक देशों को अपने नेतृत्व का पालन करने की आवश्यकता है और विश्व पशु संरक्षण सभी सरकारों से अपने पशु कल्याण मानकों में सुधार करने के लिए बुला रहा है, न केवल जानवरों के लाभ के लिए, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करने के लिए भी।

CHAHAL ACADEMY

रक्षा निधि की कमी

समाचार –

- हाल ही में, रक्षा मामलों पर एक संसदीय स्थायी समिति ने रक्षा बजट में अनुमानों और आवंटन के बीच व्यापक अंतर पर चिंता व्यक्त की है।

विवरण –

- समिति ने उल्लेख किया कि 2015–16 के बाद से, तीन सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) में से किसी को भी प्रक्षेपण के अनुसार मिलान आवंटन नहीं दिया गया है।
- कैपिटल हेड में आवंटन में काफी कमी है, जो कि प्रक्षेपण से 35 प्रतिशत कम है।
- समिति ने उल्लेख किया कि प्रतिबद्ध देनदारियां कैपिटल हेड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अपर्याप्त आवंटन निश्चित रूप से संविदात्मक दायित्वों पर 'डिफॉल्ट स्थिति' का कारण बनेगा।
- पिछले वर्षों में संपन्न अनुबंधों के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान किया जाता है।
- ऐसी स्थिति देश को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने के लिए अनुकूल नहीं है, जहां पूंजी गहन आधुनिक मशीनों का कब्जा युद्ध के परिणाम को पक्ष में झुकाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है और एक विश्वसनीय निरोध भी है।
- नौसेना और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) दोनों के पास एक ऐसी स्थिति है जहां बजट में पूंजी आवंटन में उनकी प्रतिबद्ध देनदारियां उनके हिस्से से अधिक हैं।
- इसकी भरपाई के लिए, सेवाओं को अन्य उपायों के बीच रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) की प्रतिबद्ध देनदारियों के भुगतान को स्थगित करने के लिए मजबूर किया गया है।

इस कमी का असर –

- तीन त्रि–सेवा संगठनों यानी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए), रक्षा साइबर एजेंसी (DCYA) और सशस्त्र बल विशेष परिचालन प्रभाग (AFSOD) का संचालन।
- अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) की संचालन तत्परता।
- सिग्नेट (सिग्नल इंटेलिजेंस) उपकरणों का रखरखाव।
- प्रशिक्षण संस्थानों और परिचालन इकाइयों का प्रशासन।

अनुशंसाएँ –

- कमेटी ने अगले बजट (2021–22) के बाद से, आधुनिकीकरण के प्रभावों को कम करने से पहले प्रतिबद्ध देनदारियों और खरीद के लिए एक समर्पित फंड की सिफारिश की है।

भारत, फ्रांस रीयूनियन द्वीप से संयुक्त गश्ती दल का संचालन करते हैं

समाचार –

- भारत और फ्रांस ने पहली बार रीयूनियन द्वीप से संयुक्त गश्ती दल का संचालन किया है, जिससे संकेत मिलता है कि नई दिल्ली पूर्वी हिंद समुद्र तट और मलक्का जलडमरूमध्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हिंद महासागर में अपने विदेशी पदचिन्हों का विस्तार करने के लिए अनुकूल विदेशी भागीदारों के साथ जुड़ने का इरादा रखती है।

विवरण –

- भारत ने अभी तक केवल समुद्री पड़ोसियों के साथ समन्वित गश्त किया है और अमेरिका द्वारा इसी तरह की पेशकश को अस्वीकार कर दिया था।
- भारतीय नौसेना ने रीयूनियन द्वीप से फ्रांसीसी नौसेना के साथ एक संयुक्त गश्ती दल का संचालन किया।
- गश्ती दल का संचालन फ्रांसीसी नौसेना कर्मियों के साथ P8I विमान द्वारा किया गया था।
- भारत और फ्रांस के बीच एक–दूसरे की चिंताओं पर विशेष रूप से समुद्री डोमेन में अधिक समझ थी।
- वर्तमान में, नेबरहुड फर्स्ट 'नीति और व्यापक समुद्री सहयोग के तहत, भारतीय नौसेना बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ मालदीव, सेशेल्स और मॉरीशस और समन्वित गश्ती (कॉर्पेट) के साथ संयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) निगरानी करती है।
- कॉरपोरेट्स का उद्देश्य लॉ ऑफ द सी (यूएनसीएलओएस) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।
- यूएनसीएलओएस प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संरक्षण, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण, अवैध, अनियंत्रित मछली पकड़ने की गतिविधि, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री डकैती, तस्करी की रोकथाम में सूचनाओं के आदान–प्रदान, अवैध आव्रजन और खोज और बचाव कार्यों के संचालन के बारे में नियमों को निर्दिष्ट करता है।

- फ्रांस के साथ संयुक्त गश्त, पूर्वी अफ्रीकी तट रेखा और मलक्का जलडमरूमध्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हिंद महासागर में अपने पदचिह्न का विस्तार करने में अनुकूल विदेशी भागीदारों के साथ जुड़ने के भारत के इरादे को दर्शाता है।
- भारत हाल ही में हिंद महासागर आयोग का पर्यवेक्षक बन गया है। इसके सदस्यों में से एक के रूप में रीयूनियन शामिल हैं।
- भारत ने अब तक केवल समुद्री पड़ोसियों के अलावा कॉरपेट्स के साथ नौसेना सहयोग किया है और 2016 में अमेरिका द्वारा इसी तरह की पेशकश को अस्वीकार कर दिया था।

भारत– फ्रांस रक्षा संबंध –

- मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (एमडीए) में सुधार के प्रयासों के तहत भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR) में पहला अधिकारी तैनात करने वाला देश फ्रांस है।
- फ्रांस बड़े टिकट रक्षा सौदों के साथ भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में तेजी से उभरा है और सैन्य भागीदारी में वृद्धि हुई है।
- भारतीय नौसेना वर्तमान में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत भारत में बनाई जा रही फ्रेंच स्कॉर्पीन पारंपरिक पनडुब्बियों को शामिल कर रही है, और भारतीय वायु सेना को जल्द ही अपने 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों का पहला बैच मिलेगा।
- भारत फ्रांस के साथ काम कर रहा है ताकि हिंद महासागर क्षेत्र के उस हिस्से में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए मेडागास्कर, रीयूनियन आइलैंड्स–कोमोरोस को शामिल किया जाए।
- भारत और फ्रांस के बीच रक्षा अभ्यास –
  1. वरुण – नौसेना व्यायाम
  2. गरुड़ – वायु व्यायाम
  3. शक्ति – सेना अभ्यास

भारत ने IOC में पांचवें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश किया

समाचार –

- भारत हिंद महासागर आयोग के पांचवें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है – अंतर–सरकारी संगठन जो सेशेल्स में मंत्रियों के आईओसी सम्मेलन की बैठक में दक्षिण–पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री शासन का समन्वय करता है। यह कदम दिल्ली की इंडो–पैसिफिक दृष्टि को प्रभावित करेगा।
- निर्णय ने भारत को पाँचवाँ पर्यवेक्षक बना दिया। अन्य चार पर्यवेक्षक चीन, माल्टा, यूरोपीय संघ और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ ला फ्रांसोफोनी (ओआईएफ) हैं।
- आईओसी 1982 में पोर्ट लुइस, मॉरीशस में बनाया गया था, और बाद में 1984 में संस्थागत हुआ।
- इसके पांच सदस्य राष्ट्र हैं– कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, रीयूनियन (फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र) और सेशेल्स।
- सभी 5 सदस्य राज्यों को पूर्व में फ्रांसीसी उपनिवेश या आंशिक रूप से ब्रिटिश, आंशिक रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में जाना जाता है। फ्रांस के साथ रीयूनियन द्वीप समूह के कारण आईओसी का एक सदस्य के रूप में भारत के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- पांच–सदस्यीय समूह के लिए पश्चिमी हिंद महासागर (डब्ल्यूआईओ) में विस्तार करने की भारत की योजना जो रणनीतिक रूप से हिंद महासागर को अफ्रीका के दक्षिण–पूर्वी तट और उससे आगे जोड़ता है, महत्वपूर्ण है।
- यह हिंद महासागर– मोजांबिक चैनल के प्रमुख स्थानों में से एक है।
- जबकि कोमोरोस मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी मुहाने पर स्थित है, मेडागास्कर चैनल को इसके पश्चिम में सीमाबद्ध करता है। जबकि चैनल ने स्वेज नहर के उद्घाटन के बाद अपना महत्व खो दिया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास हाल ही की शत्रुता ने चैनल को बड़े वाणिज्यिक जहाजों (विशेष रूप से तेल टैंकरों के लिए) के मूल मार्ग के रूप में वापस लाया।
- इसके अतिरिक्त, मोजाम्बिक चैनल में संभावित प्राकृतिक गैस भंडारों के साथ संयुक्त रूप से इंडो–पैसिफिक समझौते में अफ्रीका के बढ़ते महत्व को केवल व्यापक समुद्री सुरक्षा में इस क्षेत्र के महत्व को जारी रखना होगा।
- समुद्री शक्ति प्रक्षेपण और नौसेना के प्रभुत्व के लिए भूगोल के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हिंद महासागर में एक नए भू–राजनीतिक वातावरण में द्वीपों के बढ़ते महत्व के बारे में बहुत कम संदेह है।

महत्व –

- भारत ने कुछ सदस्य देशों की उच्च स्तरीय यात्राएं की हैं जैसे भारत के उपराष्ट्रपति ने कोमोरोस का दौरा किया और राष्ट्रपति कोविंद ने 2018 में मेडागास्कर का दौरा किया जिसके बाद रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

- इसलिए, भारत का प्रवेश, यहां तक कि एक पर्यवेक्षक के रूप में, आईओसी के लिए महान रणनीतिक महत्व का है क्योंकि यह पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीप देशों के साथ सामूहिक समझौते की अनुमति देगा (WIO) और फ्रांस के पहले से ही मजबूत दोस्त के साथ संबंधों को और बढ़ावा देता है।
- यह कदम भारत की एसएजीएआर (सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास) नीति को अधिक महत्व देगा।
- भारत के लिए, दिल्ली के हिंद महासागर से जुड़ाव को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि नौसेना अपने मिशन आधारित तैनाती के तहत अपनी उपस्थिति को मजबूत करना शुरू कर सकती है। क्षेत्र के साथ जुड़ाव, विशेष रूप से द्वीपों के साथ– उनकी भू–रणनीतिक स्थिति को देखते हुए– भारतीय नौसैनिक उपस्थिति का समर्थन करने में महत्वपूर्ण बन सकते हैं।

क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर और नेशनल साइबरक्राइम ट्रेनिंग सेंटर

समाचार –

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 12 मार्च 2020 को अपना 35 वां स्थापना दिवस मनाया। उस दिन, अपराध मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri–MAC) और राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (NCTC) लॉन्च किए गए थे।
- अपराध मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri–MAC) – जघन्य अपराध और अंतर–राज्य समन्वय से संबंधित अन्य मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए शुरू किया गया था।
- **राष्टोय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र (एनसीटीसी)** – पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, अभियोजकों और अन्य हितधारकों के लिए बड़े पैमाने पर साइबर अपराध जांच पर पेशेवर गुणवत्ता वाली ई–लर्निंग सेवाओं के लिए शुरू किया गया।

NCRB और इसकी पहल –

- अपराध और अपराधियों पर सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए एनसीआरबी की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में की गई ताकि अपराधियों को अपराध से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977–1981) और एमएचए की टास्कफोर्स (1985) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।
- यह समन्वय और पुलिस कंप्यूटर निदेशालय (DCPC) सीबीआई की अंतर–राज्य अपराधियों की डेटा शाखा, सीबीआई की केंद्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो और बीपीआर एंड डी की सांख्यिकीय शाखा, का विलय करके गठित किया गया था।
- सीसीटीएनएस परियोजना के तहत देश भर में 15993 पुलिस स्टेशनों और 8208 उच्च पुलिस कार्यालयों की नेटवर्किंग के लिए NCRB की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सीसीटीएनएस का विशाल डेटाबेस अपराध के मामलों को तेजी से सुलझाने में मदद करेगा।
- देश में बहुत पहले से ही फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जा रहा था और राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) एनसीआरबी द्वारा स्थापित किया जाना पुलिस के लिए गेमचेंजर होगा।
- NCRB ने 'भारत में अपराध', भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या', 'प्रीज़न स्टेटेस्टिक्स इंडिया' तथा 'फिंगर प्रिंट इन इंडिया' जारी की है, जिन्हें शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं द्वारा व्यापक रूप से संदर्भित किया जा रहा है।
- एनसीआरबी बाल पोर्नोग्राफी के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में शामिल हुआ था।
- सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2020 का आयोजन एनसीआरबी द्वारा साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था, जिसे पुलिस, उद्योग और शिक्षाविदों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। इसने सीसीटीएनएस में सुधार के लिए अभिनव विचारों को इकट्ठा करने में मदद की है।

भारत और आर्मेनिया ने एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए

समाचार –

- भारत ने रूस और पोलैंड से प्रतिस्पर्धी बोलियों को पछाड़कर चार स्वाथी हथियार बनाने वाले राडार की आपूर्ति करने के लिए यूरोप में आर्मेनिया के साथ 40 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किए।
- स्वाथी हथियार का पता लगाने वाले राडार 50 किमी की सीमा में दुश्मन के हथियारों, मोर्टार और रॉकेट जैसे तेज, स्वचालित और सटीक स्थान प्रदान करते हैं।

- ये राडार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित किये जाते हैं।
- रडार एक साथ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न हथियारों से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल को संभाल सकता है। भारतीय सेना भी जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ अपने संचालन के लिए समान राडार का उपयोग करती है। इस प्रणाली को 2018 में परीक्षण के आधार पर भारतीय सेना को सौंप दिया गया था
- अर्मेनियाई लोगों ने रूसी और पोलिश प्रणालियों का परीक्षण भी किया, जो अच्छे पाए गए लेकिन उन्होंने अंततः अधिग्रहण के लिए भारतीय प्रणाली को चुना
- यह मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने अगले पांच वर्षों में निर्यात को 35,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य घोषित किया है।
- यह सौदा भारत की स्वदेशी प्रणालियों की बिक्री के लिए एक नया बाजार खोलेगा, जो इसके यूरोपीय और अन्य प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बहुत सस्ता है
- सरकार रक्षा आदेशों को सुरक्षित करने के लिए दक्षिण–पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य–पूर्व देशों को भी लक्षित कर रही है।
- हाल के वर्षों में शिपमेंट की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ, सरकार ने 2024–25 तक 35,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है।
- 2016–17 में रक्षा निर्यात 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,500 करोड़ रुपये 2017–18 में बढ़कर 10,700 करोड़ रुपये हो गया। चालू वित्त वर्ष के लिए, केंद्र ने 20,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।

इंडिया पर्सप्रेक्टिव

1. भारत–ब्राजील संबंध –

- ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सनारो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया के चुनिंदा नेताओं में शामिल हुए। अपनी भारत यात्रा के दौरान, दोनों राष्ट्रों ने अपने बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गए।
- कई वर्षों में यह पहली बार है कि लैटिन अमेरिका के किसी नेता को भारत के राष्ट्रीय दिवस उत्सव के लिए आमंत्रित किया गया है, जो भारत की विदेश नीति की गणना में इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालता है।

कारोबार करारनामे –

- आगे की राह का मानचित्रण करते हुए, दोनों नेता 'रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रूप से बढ़ाने' पर सहमत हुए, और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान की।
- इनमें अन्य चीजें, कृषि उपकरण, पशुपालन, कटाई के बाद की तकनीक और जैव ईंधन शामिल हैं। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर भी चर्चा की, जो साझेदारी को अधिक रणनीतिक गहराई प्रदान करेगा। वार्ता का लक्ष्य आम वैश्विक दृष्टि और साझा मूल्यों पर आधारित देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा देना था।

आर्थिक तालमेल –

- दो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ, भारत और ब्राजील, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर है, उनकी साझेदारी में नई आर्थिक जीवन शक्ति को स्थापित करने के लिए निर्धारित है। भारत और ब्राजील के शीर्ष व्यापार जगत के नेताओं के बीच बातचीत ने दोतरफा व्यापार और निवेश बढ़ाने का खाका तैयार किया। आर्थिक तालमेल से उत्साहित, दोनों पक्षों ने सीमा हटाई और अगले कुछ वर्षों में वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लगभग 8 बिलियन डॉलर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए।
- भारत ने राष्ट्रपति को अपना पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की बोल्सनारो का आर्थिक पुनरुत्थान एजेंडा और ब्राजील की कंपनियों को भारत में निवेश करने और भारतीय कंपनियों के साथ दीर्घकालिक वाणिज्यिक साझेदारी बनाने के लिए प्रेरित करता है।
- भारत, अपनी ओर से, ब्राजील में भारतीय उत्पादों और कंपनियों के लिए अधिक बाजार पहुंच और निवेश के अवसरों के लिए पिचिंग करेगा।
- ब्राजील की भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय पाँच गुना है, लेकिन इसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का छठवाँ भाग है।
- ब्राजील में लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल, टंगस्टन, हीरे, पोटेशियम, फॉस्फेट, सोना, सीसा और ग्रेफाइट जैसे प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा के विशाल भंडार हैं।

- लैटिन अमेरिकी बिजलीघर भी भारत को आईटी क्षेत्र में अपनी सिद्ध विशेषज्ञता और बायोटेक और फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों में अपनी विशेषज्ञता के साथ एक ज्ञान शक्ति के रूप में देख रहा है।
- कृषि क्षेत्र में, भारत एक कृषि महाशक्ति के रूप में ब्राजील के उद्भव से बहुत कुछ सीख सकता है क्योंकि उसने उत्पादकता में नए मानदंड स्थापित किए है और भंडारण, वितरण और कृषि–प्रसंस्करण उद्योगों की अपनी तकनीक का आधुनिकीकरण किया है।
- ब्राजील ने तेल और गैस क्षेत्र में भारतीय अपस्ट्रीम निवेश के लिए सबसे बड़े गंतव्य के रूप में देश के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ में एक ऊर्जा शक्ति के रूप में ब्राजील में सिद्ध रिकॉर्ड, दोनों देश दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के अनुसंधान और विकास में सहयोग करने की योजना बना रहे हैं।

आगे की राह –

- व्यापार और निवेश को बढ़ाना निश्चित रूप से इस साझेदारी में और अधिक महत्व जोड़ देगा, लेकिन जो इसे अधिक से अधिक सामग्री प्रदान करेगा वह रणनीतिक और वैश्विक हितों का बढ़ता अभिसरण है। भारत और ब्राजील वैश्विक शासन वास्तुकला में सुधार के लिए अपने समन्वय को बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
- भारत–ब्राजील साझेदारी का वैश्विक कैनवास बहुपक्षीय प्लेटफार्मों के एक मेजबान में निकट सहयोग के साथ और अधिक बढाने के लिए तैयार है, जिसमें ब्रिक्स, IBSA, G4, G20, BASIC और संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं।

2. विदेश नीति में भारत का मार्ग

- पिछले एक दशक में, भारत की विदेश नीति की पहलों में एक कायापलट हुआ है। भारत की नई वैश्विक छवि अब एक अधिक परिपक्व, ध्वनि और कुशल बल के साथ देश की राजनयिक पहल को संचालित करती है।
- उद्देश्यपूर्ण, व्यावहारिक और सक्रिय, शेपर, एब्सटेनर नहीं स्टेबलाइजर, एक व्यवधान के बजाय एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता। अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही दुनिया में देश की विदेश नीति में भारत की विदेश नीति को एक नई शब्दावली और रूपरेखा मिली है।

विभिन्न देशों और महाद्वीपों में फैले 25 मिलियन मजबूत भारतीय प्रवासी, न्यू इंडिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

- भारत की विदेश नीति के विभिन्नतओं को 130 करोड़ लोगो के जीवन को बदलने तथा एक बहुध्रुवीय विश्व में उभरती हुई आर्थिक ताकत होने से शक्ति मिल रही है।

शार्पर और स्टेबलाइजर –

- 21 वीं सदी के दूसरे दशक में एक नया भारत उभर रहा है, जो जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक वास्तुशिल्प वास्तुकला सहित क्रॉस–कटिंग मुद्दों की एक विस्तृत सरणी पर अंतरराष्ट्रीय एजेंडा को आकार दे रहा है।
- लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और विशाल आबादी की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ यह नया भारत, वैश्विक मंच पर अपनी जगह पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विघटनकारी शक्ति होना भारत का तरीका नहीं है, स्थिरताकारी शक्ति होना चाहिए। स्व–केंद्रित होने और महज व्यापारी होना का भारत का तरीका नहीं है।
- पारस्परिक सशक्तीकरण के लोकाचार से प्रेरित, भारत ने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ धन, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता साझा की है। इसमें विकास सहयोग, क्रेडिट और अनुदान की लाइनों के माध्यम से चैनल, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग बढ़ाने में सहायता शामिल है।
- दक्षिण–दक्षिण एकजुटता की भावना में, भारत ने 160 देशों में विकास परियोजनाओं की मेजबानी के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट में लगभग 29 बिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया है।

नए भारत के लिए नई विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं –

- भारत का तरीका एक अपशकुन के बजाय एक निर्णायक या शेपर का अधिक होना होगा।
- भारत ने जलवायु परिवर्तन और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर पिछले कुछ वर्षों में अंतर उत्पन्न किया है।
- भारत एक ऐसा देश होगा जो वैश्विक अच्छाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सहन करने की क्षमता लाएगा।

कूटनीतिक पहल –

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साढ़े पांच वर्षों में 70 से अधिक देशों की यात्रा की है।
- भारत का वैश्विक कद बढ़ने के साथ–साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए एक अभूतपूर्व राजनयिक आउटरीच मिशन शुरू किया है।
- एक उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया में, भारत ने बहु–संरेखण का मार्ग चुना है, जो कि समान विचारधारा वाले देशों और प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ मुद्दों–आधारित संरेखण को मजबूर करता है।

एक नए भारत के लिए कूटनीति –

- राष्ट्रीय पुनरुत्थान को बढ़ावा देने के लिए कूटनीति इस द्रष्टिकोण का मंत्र है। भारत सरकार द्वारा 2022 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ पर 'न्यू इंडिया' बनाने के लिए सभी मित्र देशों के साथ साझेदारी के नेटवर्क का दोहन करने के लिए अपनी विदेश नीति को निर्देशित किया है।
- विकास–केंद्रित कूटनीति को राष्ट्रीय नवीनीकरण की प्रमुख योजनाओं – जैसे 'मेक इन इंडिया' और 'स्टैंड–अप इंडिया' के साथ देखा जाता है।
- देश का राजनयिक द्रष्टिकोण प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्ट–अप में मजबूत और स्थायी साझेदारी बनाने के लिए एक नये भारत को बनाने और वैश्विक स्तर पर भारत की गिनती बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। $5 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद को एक अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण और सहायक बाहरी साझेदारी के बिना संभव नहीं है।
- भारत ने एक नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए बहुपक्षीय सुधार की वकालत की है जो 21 वीं सदी की सत्ता और वास्तविकताओं की मौजूदा बदलाव को दर्शाता है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करके और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की और जलवायु परिवर्तन से निपटने का बीड़ा उठाया है।
- इस क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की मान्यता में, अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो रहे हैं जो एक स्वच्छ और हरित दुनिया के लिए एक श्वेत क्रांति की शुरुआत करना चाहते है। भारत ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की है, जिसे कोएलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसे अधिक वैश्विक समर्थन मिल रहा है।

आगे को राह –

- आगे, जैसा कि भारत अपने वैश्विक उत्थान की कहानी को अपनी शर्तों पर लिखना चाहता है, भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर लगातार जोर देना होगा क्योंकि यह देश के लोगों को लाभ पहुंचाने वाले स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को दिशानिर्देशित करेगा।

3. भारत– अमेरिका संबंध – भविष्य की राह

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 24 से 25 फरवरी, 2020 तक भारत की अत्यधिक सफल यात्रा पूरी की है।

भारत– अमेरिका के संबंध –

- पिछले कुछ वर्षों में भारत–अमेरिका संबंधों में व्यापक परिवर्तन देखा गया है, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समन्वय और साथ ही लोगों से लोगों का आदान–प्रदान शामिल है।
- दोनों देशों ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), कम्युनिकेशन्स कम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) जैसे सुरक्षित लॉजिस्टिक और सैन्य लॉजिस्टिक्स के साझाकरण पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भू–स्थानिक सहयोग के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर हस्ताक्षर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए इस यात्रा के दौरान सहमति व्यक्त की गई थी। ये समझौते भविष्य में संयुक्त संचालन की संभावना को खोलते हैं।
- भारत एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में, भारत को अमेरिकी उपकरणों के लिए उत्पादन केंद्र बनाने की दृष्टि से प्रौद्योगिकी और सह–उत्पादन के हस्तांतरण की तलाश करेगा।

व्यापार संबंध और मुद्दे –

- 2018 में, अमेरिका ने स्टील और एल्यूमीनियम पर 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के वैश्विक शुल्क लगाए। 5 जून, 2019 को, यूएस ने भारतीय वस्तुओं पर जीएसपी (सामान्यीकृत प्रणाली का दर्जा) वापस ले लिया, जिससे भारतीय निर्यात का 6.3 बिलियन अमरीकी डालर प्रभावित हुआ। 16 जून 2019 को, भारत ने 28 अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया।

- अमेरिका चिकित्सा उपकरणों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सामान, हार्ले डेविडसन मोटर साइकिलों के लिए कम शुल्क और बाजार पहुंच पर जोर दे रहा है।
- अमेरिका अपने डेयरी उत्पादों और बादाम, ब्लूबेरी, पेकन नट्स और अखरोट जैसे कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच पर जोर दे रहा है।
- भारत अपनी जीएसपी लाभार्थी की स्थिति को बहाल करना चाहता है, स्टील और एल्यूमीनियम पर अतिरिक्त शुल्क हटा दिया गया है तथा अंगूर और आम जैसे फलों के लिए बाजार में पहुंच प्राप्त करने में सक्षम है।
- H1 B वीजा के तहत रोजगार और विशेष व्यवसायों की परिभाषा और भारतीय आईटी उद्योग पर इसका प्रभाव एक लंबित मुद्दा है।
- भारत अत्यधिक कुशल भारतीय पेशेवरों द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास और विकास में दिए गए योगदान के महत्व पर जोर देना जारी रखता है।
- अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष पिछले दो वर्षों में बहुत कम हो गया है, द्विपक्षीय व्यापार 2018 में 142 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है।
- यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय ऊर्जा आयात के कारण था।
- यूएस–भारत ऊर्जा व्यापार पिछले चार वर्षों में 20 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया है।
- यह दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों में एक नया चालक होगा।
- अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (USIDFC) ने एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने का निर्णय लिया है
- यूएसआईडीएफसी ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 600 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तपोषण सुविधा की घोषणा की है।
- दोनों पक्षों ने एक सुरक्षित 5 जी वायरलेस नेटवर्क के महत्व पर चर्चा की थी और 'इस उभरती हुई तकनीक को स्वतंत्रता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक उपकरण होने की आवश्यकता थी, ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए जहां यह दमन के लिए एक नाली के रूप में भी कल्पना की जा सकती है सेंसरशिप।'
- दोनों पक्ष 'व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी' की स्थिति के लिए अपने रिश्ते को उन्नत करने के लिए सहमत हुए।
- संयुक्त बयान में, दोनों नेताओं ने 'आतंकवादी प्रॉक्सी का उपयोग करने और अपने सभी रूपों में सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की' पर भारी पड़े।
- दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी के महत्व को पहचाना, जो उन्होंने कहा कि 'क्षेत्रीय अखंडता, राज्यों की संप्रभुता, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही' के लिए सम्मान से जुड़ा होना चाहिए। यह कथन भारत को सुरक्षा के शुद्ध प्रदाता के साथ–साथ हिंद महासागर क्षेत्र में विकासात्मक और मानवीय सहायता के रूप में मान्यता देता है।
- दोनो पक्ष यूएसएआईडी के बीच एक नई साझेदारी पर सहमत हुए, जिसने इंडो–पैसिफिक के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर और तीसरे देशों में सहयोग के लिए भारत के विकास साझेदारी प्रशासन की घोषणा की। उन्होंने दक्षिण चीन सागर में एक सार्थक आचार संहिता की दिशा में प्रयासों पर ध्यान दिया, और आग्रह किया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी देशों के वैध अधिकारों और हितों का पक्षपात नहीं करता है।
- अमेरिका ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश के लिए समर्थन दोहराया।
- भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित 'ब्लू डॉट नेटवर्क' में रुचि व्यक्त की, जो BRI के विपरीत एक बहु–हितधारक पहल है, जो वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाएगा।

मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड ऐनलिसीस

ड्राफ्ट डीपीपी 2020 में सुधार

समाचार –

- 20 मार्च, 2020 को रक्षा मंत्रालय (MoD) ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 (DPP–2020) का मसौदा जारी किया। मसौदा DPP–2016 के आधार पर बना है। DPP–2016 में बिजनेस प्रोसेस रेन्जीनियरिंग के हिस्से के रूप में 47 संशोधन हुए हैं। नया मसौदा दो व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने का इरादा रखता है – पहला, प्रक्रियागत अड़चनों को हटाकर खरीद प्रक्रिया को तेज करना और दूसरा रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना।

ड्राफ्ट को मुख्य विशेषताएं –

- मसौदे ने मौजूदा खरीद श्रेणियों को संशोधित किया है, विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वदेशी सामग्री (आईसी) की आवश्यकता को बढ़ाया है।
- मसौदे ने रक्षा खरीद की कुछ नई अवधारणाओं को भी शामिल किया।
- मसौदे ने मौजूदा ऑफसेट दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और अनुबंध टेम्पलेट और दस्तावेज के अन्य प्रावधानों में बदलाव किए हैं।
- मसौदे ने डीपीपी– 2016 में मौजूदा पांच प्राथमिक खरीद श्रेणियों में एक नई श्रेणी, खरीदें (भारत में वैश्विक–निर्माण) को जोड़ा है।
- इसने लगभग सभी श्रेणियों में आईसी की आवश्यकता को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है।
- नई प्राथमिकता वाली श्रेणी के अलावा, कई स्टैंड–अलोन श्रेणियां/उप–श्रेणियां बनाई गई हैं।
- इनमें से एक 'लीजिंग' है। पट्टे पर लेने का उद्देश्य सशस्त्र बलों को उनके पास होने के बिना महंगे उपकरण (जैसे परिवहन, ट्रेनर विमान और सिमुलेटर) रखने और संचालित करने में सक्षम बनाना है।
- डीपीपी –2016 में पहली बार शुरू की गई 'मेक' श्रेणी को डीपीपी –2016 में दो उप–श्रेणियों में विभाजित किया गया था – 2016 मेक I (गवर्नमेंट फंडेड') और मेक II (इंडस्ट्री फंडेड)'।
- इन दोनों में एक तीसरी उप–श्रेणी, मेक III (स्वदेशी रूप से निर्मित)' जोड़ी गई है।
- 'इनोवेशन' श्रेणी पूंजी अधिग्रहण के दायरे में मौजूदा दो योजनाओं, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TDF) को लाती है।
- मसौदा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के रूप में एयरो–इंजन और एफएबी को संदर्भित करता है और उनकी खरीद का आह्वान करता है, भले ही आपूर्ति का एक ही स्रोत हो। एफएबी – सिलिकॉन वैफर्स के निर्माण के लिए निर्माण सुविधाएं खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, मसौदा एक बहु–विषयक सेवा गुणात्मक आवश्यकता निर्माण समिति (SQRFC) के गठन की परिकल्पना करता है।
- एसक्यूआरएफसी गुणात्मक आवश्यकताओं (क्यूआर) की तैयारी के लिए एक ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में काम करेगा।
- खरीद में तेजी लाने के लिए, क्यूआर के निर्माण के लिए छह महीने की समयसीमा (सूचना के अनुरोध पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की तारीख से) अनिवार्य है।
- यह समय सक्षम अधिकारी से एओएन मांगने के लिए एक वर्ष होगा।
- गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में, चार प्रमुख प्रावधान किए गए हैं।
- यह प्रावधान उपकरण की स्वीकृति की प्रक्रिया को अधिक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी बनाएगा।
- चार प्रावधान हैं – पहला, गुणवत्ता आश्वासन योजना; दूसरा, स्वीकृति परीक्षण प्रक्रिया; तीसरा, पार्टी निरीक्षण और चौथा गुणवत्ता आश्वासन परीक्षणों की पुनरावृत्ति नहीं।

मसौदा DPP 2020 के मुख्य मुद्दे –

1. खरीद श्रेणियों की बहुलता –

- DPP–2020 के मसौदे में परिकल्पित किए गए परिवर्तनों से 2003 की तुलना में खरीद श्रेणियों की संख्या दो से बढ़ेगी ('खरीदें' और 'Buy & Make') और कुल आठ हो जाएगी।
- इन आठ श्रेणियों में से छह प्राथमिकता वाली श्रेणियां हैं और अन्य दो 'लीजिंग 'और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल' हैं।
- कई उप–श्रेणियों के साथ 'मेक' और 'इनोवेशन' श्रेणियां हैं।
- यह श्रेणियां स्वदेशी या आयातित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वदेशी सामग्री के उच्च प्रतिशत के साथ प्रोटोटाइप के लिए हैं।
- इन श्रेणियों का प्रसार वर्गीकरण प्रक्रिया को भ्रामक, बोझिल और समय लेने वाला बना सकता है।
- प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, कुछ श्रेणियों को क्लब करने का मामला है।

2. लागत के लिए क्षमता निर्माण

- 2001 और 2018 के बीच, कुल पूंजी खरीद का लगभग 40 प्रतिशत अंतर–सरकारी समझौतों (IGA) के माध्यम से था।
- इन एजेंसियों में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) कार्यक्रम शामिल हैं।
- डीपीएसयू और ओएफबी के साथ नामांकन के आधार पर हस्ताक्षर किए गए अनुबंधों के साथ, एकल–स्रोत खरीद का हिस्सा बहुत अधिक है।
- इस तरह के एकल–स्रोत खरीद में लागत की उचितता काफी महत्व रखती है।
- जबकि डीपीएसयू और ओएफबी द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए एक आंतरिक लागत मूल्यांकन तंत्र है, यह कार्य लागत समितियों के लिए छोड़ दिया गया है।

- पूंजीगत अधिग्रहण विंग में लागत सलाहकारों का नेतृत्व लागत सलाहकारों द्वारा किया जाता है।
- हालांकि, यह पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि लागत मूल्यांकन के लिए व्यापक डेटाबेस, रक्षा से संबंधित लागत तकनीकों में विशेषज्ञता आदि की आवश्यकता होती है।
- हालांकि मसौदा DPP–2020 अधिग्रहण कर्मियों के संस्थागत प्रशिक्षण के लिए प्रदान करता है, लागत एक क्षेत्र है जिसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
- अन्य देशों (विशेष रूप से यूएस, यूके और फ्रांस) के संस्थागत तंत्र का अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि लागत के लिए एक विस्तृत कार्यप्रणाली भी निर्धारित करना है।
- कॉस्टिंग समितियों के मार्गदर्शन के लिए और लागत में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए लागत की इस विस्तृत कार्यप्रणाली की आवश्यकता होगी।

3. सैन्य सामग्री और एयरो इंजनों का विकास

- DPP–2020 का मसौदा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर और क्यूआर में इन आवश्यकताओं के समावेश के माध्यम से सैन्य सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है।
- हालांकि यह एक स्वागत योग्य निर्देश है, भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सैन्य सामग्रियों के विकास के बारे में मसौदे में किए गए प्रावधान और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के रूप में एयरो–इंजनों और एफएबी के विकास के लिए किए गए उपाय सतही है।
- यह निर्देश DRDO के जनादेश के साथ ओवरलैप भी है।
- बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था, परियोजनाओं की वित्तपोषण लागत, विकास के बाद खरीद आदेश का आश्वासन आदि जैसे मुद्दे हैं।
- इस तरह की परियोजनाओं को शुरू करने से पहले इस मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है।

4. आरएफपी के माध्यम से विशिष्ट ऑफसेट

- ऑफसेट दायित्व का निर्वहन करने के लिए मौजूदा राशियों में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण जोड़ा गया है।
- जबकि यह एक स्वागत योग्य कदम है, यह अधिक प्रभावी हो सकता है यदि MoD विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की मांग करता है।
- विशिष्ट तकनीकों का यह हस्तांतरण आरएफपी में आवश्यकता को निर्दिष्ट करके ऑफसेट दायित्व के निर्वहन के लिए होगा।

5. सार्वजनिक खरीद के लिए ईमानदारी की संहिता

- डीपीपी के प्री–कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट टेम्पलेट में एक प्रावधान है, जो विक्रेताओं को आंतरिक आचार संहिता के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।
- जो कर्मचारियों को रिश्वत और अनैतिक व्यवहार से रोकते हैं और कोड के कार्यान्वयन के लिए एक अनुपालन कार्यक्रम है।
- पारस्परिकता के लिए, सार्वजनिक खरीद (CIPP) के लिए ईमानदारी का एक कोड निर्धारित किया जा सकता है।
- अखंडता का यह कोड अधिग्रहण कार्मिक के लिए होगा, जिसे मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स 2017 में प्रावधानों की तर्ज पर घोषणा पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता होगी।

आर्म्स ट्रेड के पैटर्न

समाचार –

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने 2015–19 के दौरान अंतरराष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण की मात्रा में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एक रिपोर्ट जारी की, जो पिछले पांच साल की अवधि की तुलना में थी।
- रिपोर्ट में रूस–भारत, अमेरिका–जापान और चीन–पाकिस्तान जैसे प्रमुख रणनीतिक साझीदारों की ताकत पर प्रकाश डाला गया है, जो हथियारों के व्यापार से प्रबलित हैं।

रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया –

- अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक बने हुए हैं।
- अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है
- अमेरिका के प्रमुख हथियारों का निर्यात दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार निर्यातक (रूसी संघ) की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है।
- 2010–14 और 2015–19 के बीच, अमेरिका से प्रमुख हथियारों का निर्यात 23 प्रतिशत बढ़ा।
- अमेरिका दुनिया के शीर्ष 25 हथियारों के आयातकों में से 19 का प्राथमिक निर्यातक था।

SIPRI एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। SIPRI नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता के लिए, खुले स्रोतों के आधार पर डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। संस्थान स्वीडन में स्थित है और 1966 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है।

- एशिया और ओशिनिया पिछले पांच वर्षों में अमेरिका, रूस और चीन के लिए और भी बड़े बाजार बन गए। वे अमेरिका के लिए 30 प्रतिशत, रूस के लिए 57 प्रतिशत और चीन के लिए 74 प्रतिशत व्यापार उत्पन्न करते हैं।
- भारत के हथियारों के आयात में रूस का 56 प्रतिशत हिस्सा है।
- जापान का 96 प्रतिशत हथियार आयात अमेरिका से आया था।
- चीनी उपकरणों ने पाकिस्तान के हथियारों के आयात का 73 प्रतिशत हिस्सा बनाया।
- फ्रांसीसी हथियारों के निर्यात में 2015–19 में 72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 1990 के बाद से किसी भी पांच साल की अवधि के लिए अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कुल वैश्विक हथियारों के निर्यात का यह 7.9 प्रतिशत था।
- जर्मनी का हथियारों का निर्यात 2015–19 में, 2010–14 के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक था। इसका वैश्विक व्यापार में 5.8 प्रतिशत हिस्सा है।
- यूनाइटेड किंगडम ने 15 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
- 2015–19 में ब्राजील के हथियार आयात दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक थे – उप–क्षेत्र के हथियारों के आयात के 31 प्रतिशत के बराबर।
- दक्षिण अफ्रीका, 2015–2019 में सहारन अफ्रीका में सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा।
- 2010–14 के मुकाबले दक्षिण कोरिया के हथियारों का निर्यात 2015–19 के दौरान 143 प्रतिशत बढ़ गया। जो इसे पहली बार शीर्ष 10 सबसे बड़े निर्यातकों की सूची में पहुंचाता है।
- अशांत और संघर्ष–ग्रस्त मध्य पूर्व के देशों ने हथियारों के आयात में 61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जो पिछले पांच वर्षों में वैश्विक कुल का 35 प्रतिशत है।
- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) 2015–19 में आठवां सबसे बड़ा हथियार आयातक था।
- मिस्र के हथियारों का आयात 2015 में 19 गुना और सऊदी अरब के आयात में 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह 2015–19 में वैश्विक हथियारों के आयात का 12 प्रतिशत है।
- सऊदी अरब के हथियारों का लगभग तीन–चौथाई आयात अमेरिका से और 13 प्रतिशत यूके से हुआ।
- रिपोर्ट में तुर्की के हथियारों के आयात में कमी देखी गई है, जो पिछले पांच साल की अवधि की तुलना में 48 प्रतिशत कम थी।

आगे की राह –

- अनौपचारिक तंत्रों जैसे वासेनार अरेंजमेंट (WA) और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) के सर्वोत्तम तरीकों के पालन के माध्यम से राज्यों के बीच हथियारों के व्यापार को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।
- MTCR मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना चाहता है। पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण में अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है।

ईरान परमाणु समझौता

समाचार –

- ईरान परमाणु समझौता, एक अनिश्चित स्थिति में है जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वह समझौते को वापस ले रहे हैं।
- इस परमाणु समझौते को औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के रूप में जाना जाता था।

पृष्ठभूमि –

- 2015 में, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर P5 + 1 के रूप में ज्ञात विश्व शक्तियों के एक समूह के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर सहमति व्यक्त की – अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी।
- समझौते के तहत, ईरान ने अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को आर्थिक संकटों को उठाने के बदले में अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की।

JCPOA में की गई प्रतिबद्धताएँ –

1. यूरेनियम संवर्धन

- समृद्ध यूरेनियम का उपयोग रिएक्टर ईंधन बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन परमाणु हथियार भी।
- जुलाई 2015 में, ईरान में लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज थे। जेसीपीओए के तहत, इसे 2026 तक सबसे 5,060 से अधिक स्थापित करने की अनुमति नही थी।
- ईरान के यूरेनियम भंडार को 98 प्रतिशत घटाकर 300 किग्रा (660 एलबीएस) कर दिया गया, यह आंकड़ा 2031 तक अधिक नहीं होना चाहिए।
- इसे भंडार के स्तर को 3.67 प्रतिशत पर रखना था।

- जनवरी 2016 तक, ईरान ने नटंजा और फोर्डो में स्थापित सेंट्रीफ्यूज की संख्या को काफी कम कर दिया था, और टनों समृद्ध यूरेनियम रूस को भेज दिया था।
- इसके अलावा, अनुसंधान और विकास केवल नटंजा पर होना चाहिए और 2024 तक सीमित होना चाहिए।
- 2031 तक फोर्डो में कोई संवर्धन की अनुमति नहीं दी जाएगी, और भूमिगत सुविधा को परमाणु, भौतिकी और प्रौद्योगिकी केंद्र में बदल दिया जाएगा।
- साइट पर 1,044 सेंट्रीफ्यूज मेडिसिन, कृषि, उद्योग और विज्ञान में उपयोग के लिए रेडियोआइसोटोप का उत्पादन करेगा।

2. प्लूटोनियम मार्ग

- ईरान अराक शहर के पास एक भारी–जल परमाणु सुविधा का निर्माण कर रहा था।
- भारी पानी वाले रिएक्टर से निकलने वाले ईंधन में परमाणु बम के लिए उपयुक्त प्लूटोनियम होता है।
- विश्व शक्तियां मूल रूप से अराक को प्रसार जोखिम के कारण नष्ट कर देना चाहती थीं।
- 2013 में एक अंतरिम परमाणु समझौते के तहत, ईरान ने रिएक्टर को कमीशन या ईंधन नहीं देने पर सहमति व्यक्त की।
- JCPOA के तहत, ईरान ने कहा कि यह रिएक्टर को फिर से डिजाइन करेगा ताकि यह किसी भी हथियार–ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन न कर सके, और जब तक संशोधित रिएक्टर मौजूद है, तब तक सभी खर्च किए गए ईंधन को देश से बाहर भेज दिया जाएगा।
- ईरान को 2031 तक अतिरिक्त भारी जल रिएक्टर बनाने या किसी भी अतिरिक्त भारी पानी को जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. गुप्त गतिविधि

- समझौते के समय, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया कि जेसीपीओए ईरान को गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम बनाने से रोकेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षक, वैश्विक परमाणु प्रहरी, ईरान के घोषित परमाणु स्थलों की लगातार निगरानी करते हैं और यह भी सत्यापित करते हैं कि बम बनाने के लिए किसी भी खंडनीय सामग्री को गुप्त स्थान पर गुप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया गया है।
- ईरान अपने IAEA सुरक्षा उपायों के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए भी सहमत हुआ, जो निरीक्षकों को देश में कहीं भी किसी भी साइट तक पहुंचने की अनुमति देता है, जहां वे संदिग्ध हैं।
- 2031 तक, ईरान के पास किसी भी IAEA पहुंच अनुरोध का अनुपालन करने के लिए 24 दिन होंगे। यदि यह इनकार करता है, तो ईरान सहित आठ सदस्यीय संयुक्त आयोग इस मुद्दे पर शासन करेगा। यह प्रतिबंधों को फिर से लागू करने सहित दंडात्मक कदमों पर निर्णय ले सकता है। आयोग द्वारा बहुमत का वोट पर्याप्त होता है।

4. प्रतिबंधों को उठाना

- ईरान को यूरेनियम संवर्धन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों ने 2012 से 2016 तक तेल राजस्व में देश को 160 अरब डॉलर से अधिक की लागत वाली अपनी अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया।
- सौदे के तहत, ईरान ने विदेशों में जमी हुई संपत्तियों में $100bn से अधिक की पहुंच प्राप्त की, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल बेचने और व्यापार के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली का उपयोग करने में फिर से शुरू किया।

यूएस–तालिबान डील

समाचार –

- अमेरिकी अधिकारियों और तालिबान के प्रतिनिधियों ने दोहा में महीनों की वार्ता के बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौते से अमेरिका का उद्देश्य अपने सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करना है।

समझाता और उसकी पृष्ठभूमि –

- 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमलों में लगभग 3,000 लोग मारे गए।
- ओसामा बिन लादेन, इस्लामी आतंकवादी समूह अल–कायदा के प्रमुख, को जल्दी से जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में पहचाना गया।
- तालिबान, कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने जो उस समय अफगानिस्तान भागे थे, ने बिन लादेन की रक्षा की, उसे सौंपने से इनकार कर दिया।
- 9/11 के एक महीने बाद, अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए।

- अमेरिका एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हो गया था और तालिबान को जल्दी से सत्ता से हटा दिया गया था।
- तब से, अमेरिका तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है।
- डोनाल्ड ट्रम्प की अफगानिस्तान पर 2017 की नीति, अफगानिस्तान में सैन्य गतिरोध को समाप्त करने पर आधारित थी।
- अमेरिका ने अतिरिक्त 5,000 सैनिकों को अधिकृत करके ऐसा करने की योजना बनाई, जिससे अमेरिकी सेना तालिबान के बाद जाने के लिए एक स्वतंत्र हाथ दे और अफगान क्षमताओं को मजबूत कर सके।
- हालांकि, अमेरिका ने महसूस किया कि तालिबान विद्रोह को तब तक नहीं हराया जा सकता, जब तक उसे पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकानों और सुरक्षित अभयारण्यों का आनंद नहीं मिला।
- अमेरिका ने ट्रैक बदल दिया और पाकिस्तान से वार्ता की मेज पर तालिबान को पहुंचाने में मदद मांगी।
- वार्ता की शुरुआत सितंबर 2018 में तालिबान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने के लिए राजदूत जल्माय खलीलजाद की नियुक्ति के साथ हुई।
- कतर में यूएस–तालिबान वार्ता के नौ दौर के बाद, दोनों पक्ष एक समझौते के करीब लग रहे थे।

महत्व –

- यूएस–तालिबान अगले 14 महीनों में अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की पूर्ण वापसी की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकता है और अफगानिस्तान में 18 साल के युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक कदम का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
- इसके साथ ही काबुल में अफगान सरकार और अमेरिका के बीच एक अलग संयुक्त घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- शांति समझौते से दो प्रक्रियाओं को रोकने की उम्मीद है– अमेरिकी सैनिकों की चरणबद्ध वापसी और इंट्रा–अफगान संवाद।
- सौदा एक व्यापक और स्थायी युद्ध विराम देने के लिए एक मौलिक कदम है।
- यह सौदा अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया और मध्य क्षेत्र के लिए भविष्य का राजनीतिक रोडमैप प्रदान करने के लिए है।

सैनिकों की वापसी – अमेरिका 135 दिनों में 8,600 सैनिकों को वापिस लाएगा और नाटो या गठबंधन की टुकड़ी को भी आनुपातिक रूप से और एक साथ वापिस लाया जाएगा। सभी टुकड़ियां 14 महीने के भीतर बाहर हो जाएंगी।

तालिबान की प्रतिबद्धता – तालिबान द्वारा मुख्य आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता यह है कि तालिबान अपने किसी भी सदस्य, अल–कायदा सहित अन्य व्यक्तियों या समूहों को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान की मिट्टी का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

प्रतिबंध हटाने – तालिबान नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को तीन महीने और अमेरिकी प्रतिबंधों को 27 अगस्त तक हटा दिया जाना चाहिए। अंतर–अफगान वार्ता में बहुत प्रगति होने से पहले प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा।

कैदी रिहाइ – यूएस–तालिबान संधि के अनुसार 5,000 कैद तालिबान और 1,000 अन्य कैदियों को 10 मार्च तक छोड़ दिया जाएगा।

अन्य हितधारकों पर सौदे का प्रभाव –

- मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिका के अंतहीन युद्धों को समाप्त करने का वादा 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव अभियान के केंद्रीय विषयों में से एक था।
- यह सौदा इस साल के अंत में फिर से चुनाव के लिए अपनी बोली में उस मोर्चे पर प्रगति को प्रदर्शित कर सकता है।
- अमेरिका अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के नाम से तालिबान को एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं देता है। (तालिबान की प्रमुख मांग)
- हालांकि कई विशेषज्ञों का विचार है कि यह सौदा अंततः तालिबान को सत्ता में वापस आएगा।
- पाकिस्तान – यह सौदा पाकिस्तान को रणनीतिक लाभ प्रदान करता है, जो तालिबान का लंबे समय से लाभकारी है।
- चीन– चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के शुभारंभ के बाद, पाकिस्तान को चीन के अधिक रक्षा वाले राज्य के रूप में देखा जाता है।
- इस प्रकार, चीन तालिबान पर पाकिस्तान के प्रभाव का लाभ उठा सकता है, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जैसी अपनी रणनीतिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए।

भारत पर समझौते का असर –

- यह सौदा तालिबान के पक्ष में शक्ति संतुलन को बदल देता है, जिसमें भारत के लिए रणनीतिक, सुरक्षा और राजनीतिक निहितार्थ होंगे।
- यह सौदा अफगानिस्तान में भारत के प्रमुख दांव को खतरे में डाल सकता है।
- अफगानिस्तान की स्थिरता में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत ने अफगानिस्तान के विकास में काफी संसाधन लगाए हैं।
- भारत की सत्ता में मौजूदा अफगानिस्तान सरकार की निरंतरता में एक बड़ी हिस्सेदारी है, जिसे वह एक रणनीतिक संपत्ति मानता है।
- तालिबान के लिए एक बढ़ती राजनीतिक और सैन्य भूमिका और उसके क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार भारत के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि तालिबान को व्यापक रूप से इस्लामाबाद का एक संरक्षक माना जाता है।
- अफगानिस्तान मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है, यह सौदा मध्य एशिया में भारत के हित को प्रभावित कर सकता है।
- अमेरिकी सैनिकों की वापसी से लश्कर–ए–तैयबा या जैश–ए–मोहम्मद जैसे विभिन्न भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों के लिए उपजाऊ जमीन का प्रजनन हो सकता है।

CHAHAL ACADEMY

CHAHAL ACADEMY

Chahal Academy has pan India presence

VISIT US AT

N New Delhi: 982-155-3677
Corporate Office
Office No.B-7, Lower Ground floor, Apsara Arcade Near Karol Bagh, Metro Gate No. 7, New Delhi - 110060

M Mumbai Branch: 990-911-1227
415, Pearl Plaza Building, 4th Floor, Exactly opp Station Next to Mc Donalds. Andheri West, Andheri West, Mumbai, Maharasthra,-

K Kolkata : 728-501-1227
31/3, Bankim Mukherjee Sarani, New Alipore, Block J- Siddharth Apartment, 3rd Floor, Opposite Corporation Bank, Kolkata - 700053, West Benga

A Ahmedabad: 726-599-1227
Office No. 104, First Floor Ratna Business Square, Opp. H.K.College, Ashram Road, Ahmedabad - 380009

A Anand: 720-382-1227
Head Office
T9-3rd Floor Diwaliba Chambers,Vallabh Vidyanagar, Near ICICI Bank, Bhai Kaka Statue, Anand - 388120

B Bhubaneswar : 720-191-1227
1899/3902, First Floor, Lane No. 2, Near Laxmi Narayan Temple, Nilakantha Nagar, Nayapalli, Bhubaneswar - 751006, Odisha.

C Chandigarh : 726-591-1227
2nd Floor, SCO-223, Sector-36-D, Above Chandigarh University Office, Chandigarh - 160036.

D Dehradun Branch: 721-119-1227
Near Balliwala Chowk, General Mahadev Singh Road, Kanwali, Dehradun, Uttarakhand- 248001.

G Gandhinagar: 6356061801
Office No. 122 , 1st Floor , Siddhraj Zori , KH, O, Sargasan Cross Road, Gandhinagar, Gujarat 382421

K Kanpur : 720-841-1227
2nd Floor, Clyde House, Opposite Heer Palace Cinema, The Mall Road, Kanpur Cantonment, Kanpur - 208004, Uttar Pradesh.

P Patna : 726-591-1227
3rd Floor, Pramila mansion, Opposite Chandan Hero Showroom, Kankarbagh Patna - 800020, Bihar

R Raipur Branch: 728-481-1227
D-117, first floor, Near Shri Hanuman Mandir, Sector-1, Devendra Nagar, Raipur, Chattisgarh- 492009.

R Rajkot Branch: 762-401-1227
3rd Floor,Balaji House 52 Janta Society Opp LIC Of IndiaTagore Road Rajkot 360001

R Ranchi: 728-491-1227
3rd Floor, SMU Building, Above Indian Overseas Bank, Purulia Road, New Barhi Toli, Ranchi - 834001, Jharkhand.

S Surat: 720-391-1227
Office No. 601, 6th Floor, 21st Century Business Centre, Besides World Trade Centre, Near Udhna Darwaja, Ring Road Surat - 395002

V Vadodara: 720-390-1227
102-Aman Square, Besides Chamunda Restaurant, Behind Fatehgunj Petrol Pump, Vadodara, Gujarat- 390002

COMING SOON : BENGALURU| GUWAHATI |HYDRABAD | JAIPUR | JAMMU | KOCHI | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE

Write us at: chahalacademy@gmail.com | www.chahalacademy.com

Follow us at: YouTube Linked in